राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९६४ का ५वां दिवस [संख्या ४

मंगलवार, दिनांक २५ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, विद्युत्, यातायात, जन-सम्पर्क, देवस्थान तथा विधि एवं न्याय-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

उच्चस्तरीय स्कूल, बड़ी सादड़ी

३१. श्री शंकरलाल (सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चितौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी, उच्चस्तरीय स्कूल में विज्ञान की कक्षा खोलने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सही है कि विज्ञान की कक्षा के लिये अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। जुलाई, १९६० से।

(२) सन् १९५९-६० में इस विद्यालय के लिए विज्ञान विषय के अन्तर्गत केमिकल एवं अप्रेट्स खरीद करने हेतु २,५००) रु० की अतिरिक्त राशि स्वीकृत हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

हिण्डौन-खरेटा सड़क का सर्वे

३२. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हिण्डौन से खरेटा तक की सड़क की सर्वे हो चुकी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उसके बनने के लिये कुछ गिट्टियां भी आ गई हैं ?

Page No. 2

(श्री श्रवणलाल)

(३) यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक बनवा रही है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रवणलाल : इसका सर्वे कब हुआ था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसी पंचवर्षीय योजना में।

श्री श्रवणलाल : कुछ समझ में नहीं आया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १९६० में सर्वे हुआ था।

श्री श्रवणलाल : सर्वे के बाद में आज तक, इसका सर्वे हो जाने पर भी इसका एस्टीमेट कितने का हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह १५ मील की कुल सड़क बननी थी। इसमें से दस मील की स्वीकृति दी गई है। लेकिन फंड्स की कमी के कारण अभी तक इसको नहीं लिया जा सका।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ये जो सड़कें बनती हैं....

श्री अध्यक्ष : No general questions please.

श्री श्रवणलाल : जैसा आपने बतलाया कि धन की कमी के कारण नहीं लिया जा सकता, तो क्या सरकार हिण्डौन से खरेटा जाने वाली सड़क, जिसका सर्वे हो चुका है, के लिए धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती जहां से सरकार को लाखों रुपयों का फायदा हो सकता है। पत्थर के बिज़नेस में सड़क के बनाने के कारण सरकार को लाखों रुपए सालाना की इन्कम हो सकती है, उस पर पैसा खर्च नहीं कर सकती।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : धन की सुविधा होने पर इसको लिया जा सकेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सड़क के निर्माण के लिए आपने क्या क्राईटेरिया रखा है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्री विजयसिंह झाला : यह बहुत जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह प्रश्नोत्तर काल में नहीं पूछा जा सकता।

श्री श्रवणलाल : सर्वे के बाद एस्टीमेट हो चुका है। कुछ गिट्टियां डल चुकी हैं, सड़क का काम बंद पड़ा है।

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : जब सब कुछ आपको मालूम है तो फिर क्यों पूछते हो ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

शाहबाद व छबड़ा तहसीलों की सड़कें

३३. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) :

Page No. 3

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की शाहबाद व छबड़ा तहसीलों में कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन्हें पूरा करने पर वे क्षेत्र यातायात के साधनों से मध्यप्रदेश से जुड़ जाते हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के सुझाव उक्त तहसील निवासियों ने सरकार के पास भेजे हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(३) शाहबाद से राजपुरा होकर मध्य-प्रदेश की सीमा तक सड़क बनाने की स्वीकृति पंचवर्षीय योजना में करदी गई है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह कम्मराज की सड़क है जिसकी आपने स्वीकृति दी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं। जिसकी स्वीकृति दी गई है उसकी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैंने पूछा है कि कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं। कितने मील लम्बा आपका काम चल सकता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दस मील लम्बी होगी। आपने वेग प्रश्न पूछा है। कौनसी सड़कों से आपका मतलब है ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या आपको इससे कोई इन्फोर्मेशन नहीं मिली ? कोई डिमांड तहसीलों के पास नहीं हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महो-दय, वहां से स्टेशन की ओर छबड़ा कस्बे तक वह सड़क भी तैयार नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हो सकता है कि तैयार नहीं हो।

प्रश्न संख्या ३४

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी का गठन

३५. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जांच के लिये निर्माण

(श्री रामकिशन)

कार्यों को चैक करने के लिए किसी सरकारी कमेटी के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो वह कमेटी कब तक बना दी जावेगी और नहीं, तो क्यों नहीं?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : एक टैक्नीकल कमेटी बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है, किन्तु इसके गठन करने से पहले अन्य राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री रामकिशन : कौनसी कमेटी बनाने का मामला?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : टैक्नीकल।

श्री रामकिशन : अच्छा, टैक्नीकल।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : आजकल भ्रष्टाचार भी टैक्नीकल हो गया है।

श्री रामकिशन : कब तक आप राज्य सरकारों से जान लेंगे? किस स्टेज पर यह कमेटी है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री हरिश्चन्द्र): दूसरी स्टेट्स से इन्फॉर्मेशन मंगाई है, उसके बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कुछ स्टेट्स से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली है?

श्री हरिश्चन्द्र : मंगवाई है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह जरूरी है कि जब दूसरे राज्यों में गठन हो तब हम करें?

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरी रियासतों में क्या सिस्टम है, उसकी जानकारी करने के लिए....

श्री रामकिशन : दूसरे राज्यों में भ्रष्टाचार का तरीका दूसरा है। कमेटी बनने में जल्दी करनी चाहिए। इसमें खास कोई ऐसी टेक्नीकेलिटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

देवगढ़ हाई स्कूल के मेन्टीनेन्स के लिए धन-राशि

३७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हाई स्कूलों की मेन्टीनेन्स के लिए एक प्रतिशत के हिसाब से प्रतिवर्ष रकम मिलती रहती है, पर देवगढ़ के हाई स्कूल को ४ वर्षों से मेन्टीनेन्स के लिए कोई रकम नहीं दी गई है?

(२) यदि हां, तो क्यों और कब दी जायेगी?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। सब ही सरकारी भवन पर चलने वाली शालाओं को भवन के मेन्टीनेन्स के लिए एक प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से राशि देने का नियम है। देवगढ़

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

स्कूल को गत ३ वर्षों में कोई रकम नहीं मिली थी।

(२) इस वर्ष १९६३-६४ में इस विद्यालय को २५०) रु० दिया गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : लेकिन पूरे कायदे के साथ कितनी रकम मिलेगी?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पॉसिटी ऑफ फंड्स के आधार पर बड़ा कठिन है पूरी रकम देना।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्यों? दूसरी शालाओं में मिलती है या नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा नहीं है। उनको भी २५०) रु० मिलते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपने किस अनुपात से कमी की है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनुपात से तो नहीं है। डिस्क्रीशनरी फंड में ऐसा प्रोवीज़न नहीं रखा गया है....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं अनुपात के लिए पूछती हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसका मतलब हुआ कि किसी को आप ज्यादा दें या कम दें, यह आपकी मर्जी पर निर्भर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा तो नहीं है। भवन की आवश्यकता और संपन्नता दोनों का ध्यान रखा जाता है और जो संपन्न व्यक्ति हैं वह खयाल रखकर उनके सहयोग के आधार पर काम किया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं उसका खुलासा चाहती हूं कि संपन्नता और आवश्यकता से क्या मतलब है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसे देवगढ़ और भीम की आप एम. एल. ए. हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा विश्वास हो जाय कि आपकी ओर से भी कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी तो २५०) रु० हम देंगे तो इस भवन की समस्या का हल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

जयपुर-भरतपुर रूट पर बसों की कमी

३८. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए राजस्थान रोडवेज की बसें जो जयपुर-भरतपुर रूट पर चली हैं वे कम हैं?

(२) क्या यह भी सही है कि इस रूट पर बसों की कमी के कारण लोगों को बस स्टेन्डों पर रह जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस रूट पर और बसें बढ़ाने का इरादा रखती है?

उप-मन्त्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसें भी बढ़ा दी जाती हैं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : आपने बताया कि जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं कहता हूं कि पहले से कम बसें चलती हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले १२ बसें चलती थीं, आज १७ चलती हैं; इसलिए कम नहीं हैं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : पहले ४५ बसें चलती थीं।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): वह जयपुर रियासत में थीं।

श्री रामकिशन (वैर) : इससे क्या फर्क पड़ा?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बिजली की कन्सेशनल रेट

३६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में केवल बीकानेर को छोड़ कर अन्य स्थानों में सरकार ने बिजली के कन्सेशनल रेट क्यों रखे?

(२) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जल विद्युत मिलने के बाद रेट कम हो जावेंगे?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं, ऐसा नहीं है। कन्सेशनल रेट केवल तीन स्टेशनों पर लागू थे। बीकानेर में भी ऐसी स्थिति थी। किन्तु अब भाखरा की बिजली रेट लागू हो जाने के बाद कन्सेशन का सवाल नहीं उठता।

(२) जी नहीं। उद्योग और कृषि के रेट पहले तीन स्टेशनों से कम होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : यह परिवर्तन कब से हुआ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब से भाखरा रेट लागू हुए हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : विकास के काम में क्या बीकानेर और जयपुर में जो रेट दिये जाते हैं वे समान हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : अब तो मेरे खयाल में दोनों को बराबर कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : है क्या इस समय?

श्री हरिश्चन्द्र : अब हो जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : कब से हो जायेगा?

श्री हरिश्चन्द्र : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विचाराधीन है। उनके पास करते ही हो जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : भाखरा की बिजली के समय फर्क नहीं रखा गया तो अब ऐसा क्यों फर्क रखा गया?

Page No. 7

श्री हरिश्चन्द्र : दोनों की टेरिफ में जो फर्क है उसके लिए कोशिश की जा रही है कि उसको कम किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राजकीय उच्च विद्यालय, नापासर

४०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च विद्यालय, नापासर, जिला बीकानेर का वर्तमान भवन स्थानीय नागरिकों द्वारा बना कर राज्य सरकार को दिया गया है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि इस स्कूल में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नागरिकों द्वारा टीनों के छप्पर तैयार करवाये गये थे ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त भवन में साइंस के कमरे की भी कमी है जिसके लिये जन सहयोग की राशि स्थानीय नागरिकों द्वारा तीन-चार वर्ष पूर्व जमा कराने के बावजूद भी उक्त कमरा नहीं बनाया गया है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां। स्थानीय नागरिकों द्वारा कुछ टीन के छप्पर बनवाये गये थे परन्तु वे छोटे होने के कारण दुबारा साइज़ में बड़े बनवाये गये ताकि उनमें कक्षायें लग सकें।

(३) जी हां। इस शाला में विज्ञान के कमरों की कमी है। जनता ने २,५००) रु० इसके लिए जमा भी करा दिये हैं। पी. डब्ल्यू. डी, बीकानेर, से विज्ञान के लिये कमरे बनाने के बारे में उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री भीमसेन : क्या उचित कार्यवाही कर रहे हैं ? पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि टेन्डर इन्वाइट कर लिये हैं और कमरे जल्दी बन जावेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य: पी. डब्लू. डी. को लिखा है कि इसको सम्पन्न कराने के लिए हाथ में ले लें।

श्री फूलचन्द (सुजानगढ़) : ये रुपये कब जमा कराये गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : २,५००) में तो एक कमरा भी बनाना मुश्किल है। वह महत्व का प्रश्न है कि इसको कब सम्पन्न कराना है।

श्री भीमसेन : कब तक सम्पन्न कराना है, यह ही बता दीजिये ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : डाइरेक्टर को पन्द्रह दिन पहले ही सूचित किया गया था कि इस सम्बन्ध में पी. डब्लू. डी. को मूव करें। मेरा ख्याल है ६ महीने में हो जायेगा, अगर बजट की व्यवस्था ठीक हो गई तो।

श्री भीमसेन : यह तो आपने 'अगर' लगा दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा विभाग में खासा कटौती हुई है उसको देखते हुए कहां तक इसको सम्पन्न करने में सफल हो सकते हैं, यह विचार की बात है।

श्री फूलचन्द जैन : क्या आपने इसके एस्टीमेट कराये हैं कि कितने रुपयों की आवश्यकता होगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पी० डब्ल्यू० डी० के पास है एस्टीमेट ।

श्री भीमसेन : पी० डब्ल्यू० डी० ने एस्टीमेट बना कर आपके विभाग के पास भेज दिये आप उनकी सेंक्शन क्यों नहीं देते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सेंक्शन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल ।

सराड़ा-पलोदड़ा सड़क की भूमि का मुआवजा

४१. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सराड़ा-पलोदड़ा सड़क बनाने के लिये काश्तकारों की भूमि ली गई है ? यदि हां, तो क्या उन काश्तकारों को भूमि का मुआवजा चुका दिया गया है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : जी हां । जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई है उनका मुआवजा चुकाने के लिये चैक उदयपुर कलेक्टर को भेज दिया गया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): यह भूमि कब अवाप्त की गई थी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से रूलिंग दी गई है कि इस तरह से जो जमीन ले ली जाती है चाहे वह सड़क के लिए हो या नहर के लिए ली गई हो, उनका मुआवजा जल्दी से जल्दी चुकाया जाय । उसके बावजूद भी यह नहीं चुकाया जा रहा है । सारे राजस्थान में यह हालत है ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : एक्विज़िशन ऑफ लैंड का प्रश्न सदन में कई दफा आया है और आपने भी इस सम्बन्ध में आदेश दिये हैं कि यह जल्दी से जल्दी होना चाहिये । इस पर सरकार ने विचार किया है और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में तीन आदमियों की एक कमेटी नियुक्त की गई है । क्या क्या स्टाफ है और क्या क्या रूल्स रिलेक्स होने चाहिये ताकि एक्विज़िशन प्रोसिडिंग्स जल्दी से जल्दी हो सकें,यह सरकार के विचाराधीन है और उस कमेटी की रिपोर्ट आते ही, महीने दो महीने में, यह कार्यवाही हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री प्रभुलाल ।

माध्यमिकशाला, सारोला कलां

४२. **श्री प्रभुलाल सेन्टर** (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) माध्यमिकशाला, सारोला कलां,

Page No. 9

(श्री प्रभुलाल सेन्टर)

जिला झालावाड़ की छात्र संख्या क्या है ?

(२) क्या शिक्षा विभाग ने इस कस्बे में माध्यमिक शाला खोलते समय जनता द्वारा बिल्डिग के लिये दस वर्ष का वायदा करवाया था ? यदि हां, तो उसकी मियाद कब पूरी हो चुकी है ?

(३) अब इस माध्यमिक शाला के बिल्डिंग के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) ४६५ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

(२) जी हां, दस वर्ष की मियाद जनता द्वारा बिल्डिंग देने की १९६०–६१ में समाप्त हो चुकी है।

(३) नये भवन का विचार करना संबंधित ग्राम पंचायत का कार्य-क्षेत्र है, इस पर संबंधित ग्राम पंचायत का ध्यान शिक्षा निरीक्षक द्वारा आमंत्रित किया जावेगा ।

श्री प्रभुलाल सेन्टर: माननीय अध्यक्ष, किसी स्कूल में ४६५ छात्र हों और उस स्कूल की स्थिति ऐसी हो कि हर साल शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को बड़ी मुश्किल आती हो तो क्या सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती ? सरकार की ओर से अब तक एक पैसे की भी मदद नहीं दी गई है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक पाठशाला के लिए भवन की व्यवस्था का काम जनता पर रखा गया है । आश्वासन के मुताबिक भवन बनाने का काम जनता ने पूरा नहीं किया । हमारी भी मजबूरियां हैं । भवन का प्रबन्ध होने के पश्चात् ही यह पूरी हो सकती हैं ।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : दस वर्ष का वादा यहां किया गया था कि दस वर्ष में बिल्डिंग दे देंगे तो माध्यनिक शाला खोल देंगे । बिल्डिंग दिये हुए १४ वर्ष हो गये हैं। पाठशाला किराये की बिल्डिंग में चल रही है । सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिलेगा तो माध्यमिक-शाला की बिल्डिंग कैसे बनेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बात नहीं है। जनता द्वारा भवन दिये जाने की आवश्यक कन्डीशन है जिसकी पूर्ति नहीं की गई है। इसीलिए किराये पर यह स्कूल चला रखा है। ग्राम पंचायत किराया तक देने के लिये तैयार नहीं है और मकान मालिक हमको नोटिस दे रहा है । हमने जनता से, ग्राम पंचायत से कहा है कि कम से कम किराया तो चुकाये ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा सु०) : शर्त जनता से मांगी थी । क्या यह आइडिया दे दिया गया था कि ग्राम पंचायत इसको बनायेंगी । ग्राम पंचायत पहले नहीं थी और यह बोझा भी नहीं डाला था। अब ग्राम पंचायत पर यह बोझा भी डाल दो, आप अपने वायदे को बदल दो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वायदा बदलने का सवाल नहीं है। ग्राम पंचायत

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ने किराये पर लेकर मकान दिया है। ग्राम पंचायत और हमारेबीच क्या मुहाअदा है, यह क्लीयर है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जनता यदि सहयोग देने में असमर्थ है तो क्या आप स्कूल को बन्द कर देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बन्द करने का प्रश्न नहीं है। माननीय एम०एल०ए०, और दूसरों से सम्पर्क स्थापित करके हल निकालना पड़ेगा कि भवन निर्माण का प्रश्न किस स्थिति में रख सकें।

श्री भैरबलाल "कालाबादल" : जब शहरों में यह व्यवस्था नहीं रखी है तो आप गांव में यह शर्त और व्यवस्था क्यों रखते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है। यहां इस समय ग्राम और नगर का झगड़ा नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ग्राम वासियों की स्थिति न हो और यदि जहां ऐसे स्कूल चलते हों, क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती है कि उनको कुछ सहायता दी जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ४६५ छात्रों की संख्या को देखते हुए हमें अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माध्यमिक शाला में कितने कमरे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कितने कमरे और विन्डौज़ हैं यह मुझे नहीं मालूम है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्रामीण विद्युतिकरण एवं कृषि प्रयोजनों के लिए विद्युत्

४३. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Power Minister please reply:-

1. Is the Government aware that the work of the rural electrification and the utilisation of power for agricultural purposes gets unnecessarily delayed on account of the lack of understanding of the power programme and power utilisation by the cultivators and the Block Staff ?

2. Does the Government or the R. S. E. B. contemplate to establish a rural Electrification Department to examine schemes and to advise and help cultivators who are eager to make use of the electric power in future ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं। विद्युत् कार्यक्रम तथा विद्युत् उपयोगिता की जानकारी प्रदान करने के लिये जिला स्तर पर ग्रामीण विद्युतिकरण समितियों का संगठन किया गया है।

(२) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने इस प्रकार की योजनाओं के महत्व को ध्यान में रखकर प्रत्येक ओपरेशन व मेन्टीनेन्स सर्कल में एक पृथक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति की है ताकि जल्दी से जल्दी सर्वेक्षण व योजना बनाने का कार्य हो सके।

पत्रों की ग्राहक संख्या

४४.श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के पत्रों की ग्राहक संख्या के बारे में विभाग स्वयं के साधनों द्वारा कोई जानकारी प्राप्त करता है ?

(२) यदि हां, तो अब तक कितने पत्रों की ग्राहक संख्या के बारे में जांच की गई है ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि इस प्रकार की कोई जांच कराई जाय ?

जन सम्पर्क मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी नहीं ।

(२) जांच किसी के बारे में अभी तक नहीं की गयी है ।

(३) इस बारे में हाल में नियम बनाये गये हैं और उनके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

बीकानेर-रतनगढ़ ट्रान्समिशन लाइन का सर्वे

४५. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर रतनगढ़ ट्रान्समिशन लाइन (जो कि रेलवे लाइन के सहारे जाती है) को सिंथल के पास टेप करके बैलासर, सेजारासर व गुंसाईसर, नौरंगदेसर आदि बड़े बड़े गांवों में पानी खेती व घरों के उपयोग हेतु बिजली देने के सम्बन्ध में क्या सर्वे कराया गया ? अगर नहीं, तो अब कब तक सर्वे करवाया जावेगा ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र: जी) : नहीं । अभी तक सर्वे नहीं कराया गया हैं । जब उक्त ग्रामों में बिजली पहुँचने की संभावना होगी । उससे पूर्व सर्वे करवाया जावेगा ।

श्री भीमसेन : जब गांव के पास से बिजली की लाइन जा रही है तो उसको टेप करने में क्या आपत्ति है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा है कि एग्रीकलचर एक्सपेन्शन के लिये ५० लाख का प्रावधान किया गया है उसमें यदि आयगा तो ले लिया जायेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह जो लाइन गांव के बिल्कुल पास से जा रही है उसकी सर्वे कराना है वास्तव में बिजली दी जा सकती है या नहीं; इस तरह से जहां लाइन गांव से पास होती है उन गांवों को बिजली देने के बारे में सरकार क्या सोचती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अच्छा सोचती है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पांच पम्प के पीछे लाइन देने की आपकी योजना है, आपकी इस बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिये; जो लाइन गांव से पांच मील की दूरी पर पड़ती है उससे बिजली देने के लिये तैयार हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : तृतीय पंच वर्षीय योजना में आपने जो धन-राशि रखी है

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो जब विभाग सर्वे ही नहीं कराता है तो आप किस प्रकार से बिजली दे सकेंगे ? सर्वे रिपोर्ट तो आनी चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : लाइन गांव के पास से जाती है, इससे मतलब यह नहीं कि बिजली वहां पहुंच जायगी, पोटेन्शियल लोड तो होना चाहिये ? तो दिया जा सकता है।

श्री विजयसिंह झाला : लोड तो तब मालूम पड़ेगा जब कि आप सर्वे करायेंगे। आपकी यह निश्चित योजना होना चाहिये कि इतना निश्चित लोड होने पर अवश्य (रूप से) बिजली दी जायगी। हम पम्प तैयार करवाकर भेजते हैं, लेकिन योजना आपके यहां से कार्य रूप में परिणित नहीं होती है।

श्री हरिश्चन्द्र : केवल स्कीम के बन जाने से ही सारा काम नहीं हो जाता।

श्री विजयसिंह झाला : आपने पहले भी यह कहा था कि गांवों में बिजली दी जायेगी, जहां पांच पम्प होंगे वहां देंगे। जब हम जनता को तैयार करके पांच पम्प के लिये तैयार करते हैं और जितनी धन-राशि चन्दे के रूप में चाहिये वह भी देते हैं; फिर भी वह स्कीम आपके यहां से दबा दें, कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाता है। यह आप जो वायदा सदन में करते हैं क्या उसके खिलाफ नहीं है ?

श्री जोधसिंह (गिरवा) : उदयपुर डिविज़न में सिवाणा ग्राम में जहां की लोगों ने पैसा भी जमा नहीं कराया फिर भी वहां का प्रमुख कांग्रेसी होने के कारण वहां बिजली दे दी गई; दूसरी तरफ गिरवा के लोगों ने पैसा जमा करा दिया, लेकिन आज तक वहां बिजली नहीं लगी ?

श्री मुरलीधर व्यास : एग्रीकलचर परपंज़ के अलावा जहां पीने के पानी का सवाल है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको प्राथमिकता देने का सरकार सोचती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी समस्या जहां कहीं की है आप मुझे बताइये, जरूर वहां बिजली पहुंचायी जायेगी।

श्री विजयसिंह झाला : आपके आश्वासन का महत्व क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब

४६. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष कौनसी पाठ्य पुस्तकें देर से प्रकाशित हुईं तथा देरी से प्रकाशित होने का क्या कारण है ?

(२) आज दिन तक कौन कौन सी पुस्तकें पुस्तक विक्रेताओं के यहां उपलब्ध नहीं हैं ?

(३) सरकार भविष्य में इस देरी को रोकने के लिये क्या कदम उठाने वाली है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) इस वर्ष प्राय: सभी पुस्तकें ठीक समय पर उपलब्ध कर दी गई थीं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) समस्त राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं।

(३) पुस्तकों के आगामी वर्ष की आवश्यकता पूर्ण करने के लिये सभी पुस्तकों का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि अभी तक आदर्श ललित कला कक्षा ६, सिद्धान्त चन्द्रिका गृह विज्ञान कक्षा ६, ७, एवं ८ बिल्कुल भी छपकर बाजार में नहीं आया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, संगीत चन्द्रिका कक्षा ६, ७, ८ की छपाई एक विशेष प्रकार की छपाई होती है; इसलिये इसके मुद्रण में विशेष समय लगा है।

श्री विजयसिंह झाला : तो फिर आप यह कैसे कह रहे हैं कि सभी पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, यह बिल्कुल झूठ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा प्रायः सभी पुस्तकें।

श्री विजयसिंह झाला : 'प्रायः' शब्द लगाकर आप हमें धोखा देना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपको 'झूठ बोलना', 'धोखा देना,' ये बातें नहीं कहनी चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, एक-दो मिनिस्टरों की एक प्रकार की आदत हो गई है कि वे प्रश्नों का उतर इसी तरह टालते हैं, उत्तर देगें, 'अगर' 'प्रायः' ये ही उसमें होंगे।

प्रश्न संख्या ४७.

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

संगीत स्कूल, गुमानपुरा कोटा

४८. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) संगीत स्कूल, गुमानपुरा, कोटा की स्वीकृति किस तारीख को प्रदान की गई थी ?

(२) उक्त संगीत पाठशाला चलाई जाने में क्या अड़चन पैदा हो रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) :

(१) गुमानपुरा कोटा में संगीत स्कूल खोलने का कोई आयोजन नहीं है।

(२) अब संगीत स्कूल खोलने की कोई योजना ही नहीं है तब उसे चालू करने में अड़चन पैदा होने का प्रश्न ही नहीं होता।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं वहां से नम्बर नहीं लाया हूं नहीं तो बता देता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : योजना नहीं है तो क्या संगीत विद्यालय को सहायता देने की योजना है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो चल रही है उनके लिये योजना है, वे ग्रान्ट-इन-एड मांग सकते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या वहां के लिये योजना बनाने का सोच रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह संगीत का समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्वीकृती किस तारीख को प्रदान की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : है ही नहीं, स्वीकृति प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कोई मास्टर गाता होगा, इन्होंने स्कूल समझ लिया।

एक माननीय सदस्य : 'कालाबादल' गाते होंगे।

प्रश्न संख्या ४६

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिंह।

हाई स्कूल, भादरा का हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तन

५०. **श्री हरदत्तसिंह (नोहर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हायर सैकन्डरी स्कूल, छानी बड़ी, तहसील भादरा व हायर सैकन्डरी स्कूल, नीनाण, तहसील भादरा की हायर सेकन्डरी परीक्षाओं का गत वर्ष क्या परीक्षा फल रहा ?

(२) क्या सरकार उपरोक्त स्थानों का परस्पर कस्बा भादरा से फासला देखते हुए भादरा हाई स्कूल को शीघ्रतम हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) मार्च, सन् ६३ में जो हायर सैकन्डरी की परीक्षा हुई उसमें हायर सैकन्डरी स्कूल, छानी बड़ी व नीनाण का परीक्षा-फल ५८.३ तथा ६६.६ प्रतिशत रहा।

(२) सन् ६४–६५ में हाई स्कूलों को हायर सैकन्डरी स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है। अतः भादरा हाई स्कूल को हायर सैकन्डरी में परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरदत्तसिंह : यह प्रावधान कब बना देंगे, हाई स्कूल्स को हायर सेकन्डरी स्कूल में बदलने का ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : परिवर्तन की अभी नीति नहीं है।

श्री हरदत्तसिंह : यह नीति कब तक बना देंगे; क्या विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों प्रश्नों पर विचार हो रहा है; बनाया जाय या नहीं बनाया जाय। आर्थिक संकट दूर होने पर ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

नसीराबाद-नीमच स्टेट हाईवे पर रेलवे फाटकों की सड़क पर मुड़ाव

५१. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नसीराबाद से नीमच स्टेट हाईवे पर तहसील गंगरार में सोनियाणा के करीब रेलवे फाटक पर सड़क का मुड़ाव बड़ा खतरनाक है जिससे आए दिन बस एवं ट्रकों के एक्सीडेन्ट हुआ करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें सुधार करने का विचार रखती है ?

(२) क्या सरकार तहसील गंगरार में मेडीखेड़ा के रेल्वे फाटक पर उपरोक्त प्रकार के सड़क के मुड़ाव में भी सुधार करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। किन्तु एक्सीडेन्ट होने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(२) मामला विचाराधीन है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : इस महीने में ही एक्सीडेन्ट हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हो सकता है।

रूपारेल नदी के घाट सीतल पर पुल

५२. श्री मजलिसखां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रूपारेल नदी के घाट सीतल पर हर साल वर्षा-काल में काफी पशु और यात्री नदी के चढ़ाव के समय बह जाते हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि नदी के चढ़ाव की वजह से अलवर, भरतपुर, मथुरा में ट्रेफिक कई कई दिन रुक जाता है ?

(३) क्या राज्य सरकार की वर्ष ६३-६४ में उपरोक्त घाट पर पुल बनाने की कोई योजना है ?

(४) यदि हां, तो क्या इसका सर्वे करा लिया है कि इस पुल के निर्माण में कितनी लागत आवेगी ? अगर नहीं कराया है, तो क्या सर्वे कराने का विचार है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मजलिसखां : क्या भरतपुर-मथुरा आदि का ट्रेफिक रुक जाता है, यह सही नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : घंटे दो घंटे के लिये रुकता होगा।

श्री मजलिसखां : कम से कम १२-

(श्री मजलिस खां)

१२ घंटे रुकना पड़ता है, आपको सही जानकारी नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

टीचर्स की बकाया रकम

५३. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में किस किस जिले में टीचर्स की कितनी कितनी और किस किस वर्ष की और किस किस प्रकार की रकम बकाया है ?

(ख) इस बकाया के भुगतान के सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) (क) राजस्थान में जिस जिस जिले में टीचर्स की जितनी जितनी रकम बकाया है इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इन बकाया रकमों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग समय समय पर जिलों में जाकर बिलों को पास करते हैं तथा जो कमियां होती हैं, बताकर पूरी करवाते हैं। जो क्लेम पूरी तरह नहीं बनाये जाते उन्हें किस तरह से बनाया जावे ये इन्स्ट्रक्शन्स देते हैं तथा बाद में पूरे होने पर पास करते हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री श्रवणलाल : यह जो फिक्सेशन की ग्रेड की जोड़ लगाकर १६, ३०, ५१५ रु० के करीब बकाया निकलती है, यह कब से बकाया है ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : समय तो जानकारी करके ही बता सकता हूं। पर फिर भी मैं निवेदन कर दूं कि इसमें और प्रगति हुई है, ६४ में। इससे इस राशि में रिडक्शन आया होगा। मेरा ऐसा विश्वास है, जैसा मैंने निवेदन किया पहले भी सदन में यह प्रश्न आया था. उस वक्त से परसनल लेवल पर हम एफर्ट्स कर रहे हैं। इसमें बहुत सी दिक्कतें फाइनेन्स की आती हैं। तो वे लोग भी हमें सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसी हालत में यह सारा प्रश्न आप हम पर छोड़ दीजिये तो हम ज्यादा विश्वास दिलाते हैं कि इसे शीघ्रातिशीघ्र निपटा देंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह तो आपके ही ऊपर है, छोड़ने का क्या प्रश्न है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षक संघ भी हमें लिखता रहा है ! उनकी चिंताओं और कठिनाइयों को दूर करने में हम संलग्न हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : ६४ में कितना रुपया चुकाया है आपने ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ६३ में कितना चुकाया, यही बता दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका स्टेटमेन्ट मैं लाया नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) क्या आप कैटेगोरिकली यह एश्योरेन्स दे सकते हैं कि यह १६ लाख की बकाया अमुक समय तक चुका दी जावेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विशेष अगर कोई आपत्ति इस तरह की बीच में नहीं हुई तो मैं वह विश्वास दिला सकता हूँ कि अधिक से अधिक एक साल में इसका निपटारा करने का प्रयास किया जावेगा।

श्री रामकिशन (वैर) : यह तो कुछ भी आश्वासन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या शिक्षा मन्त्री महोदय अपनी योग्यता के आधार पर एक वर्ष की अवधि में इसे चुकाने का विश्वास दिला सकते हैं ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

मैं शिक्षा मन्त्रीजी से पूछ रहा हूँ। उप-मन्त्रीजी से नहीं।

मैं स्पष्ट निवेदन कर दूं कि आपने जो कहा है वह इसका इलाज भी नहीं है और उचित भी नहीं है। कैटेगोरिकली कोई आश्वासन दें आप।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फ्लोर ऑफ दी हाउस पर मेरा कब्जा है। आप शिक्षा मन्त्रीजी से उत्तर मांग रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : सन्तोषजनक उत्तर नही मिला। १६ लाख की बकाया दस-दस सालों से चली आ रही है। पर उप-मन्त्रीजी सन्तोषजनक रूप से यह तक नहीं बता सके कि यह रकम अब कितने सालों में वे पे कर देंगे। ऐसा है अध्यक्ष महोदय, कि सन्तोषजनक उत्तर तो मिलना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक प्रश्न। क्या उप-मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि १६ लाख इन टीचरों का सरकार पर बाकी रहता है, उसके पीछे यह राज तो नहीं है कहीं कि उनकी जो नौकरियां हैं जिसके बारे में पिछली बार भी प्रश्न आया था और उनके रिप्रेज़ेन्टेशन्स भी आये थे, उनमें उनका सीनियोरिटी के मामले पर तो नहीं अटक रहा है। या जो ऑफिस में पर्सेन्टेज लगाकर फीस के रूप में पेमेन्ट कर देते हैं उनको तो मिल जाता है और जो नहीं देते ऑफिस में कुछ तो उनका एक्यूमुलेशन कर रखा है उन गरीब मास्टरों का रुपया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पैसा देने का ? चन्दे से मतलब है क्या आपका ?

श्री रामकिशन : स्पष्ट मतलब है इसका। जो रिश्वत दे देते हैं ऑफिस में उनको मिल जाता है, जो नहीं देते उनका एक्यूमुलेशन कर रखा है।

श्री निजरंननाथ आचार्य : अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपकी समझ में मेरी बात कम आवेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं समझ गया इसको। ऐसी कुछ शिकायतें अवश्य हमारे सामने भी आई हैं। हम इसके प्रति जागरूक हैं। इन आम शिकायतों के निराकरण करने का भी प्रयास करते हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यह राशि वैसे बड़ी नजर आती है, पर यह २७ जिलों की है । अगर २७ जिलों में इसका विभाजन किया जावे तो इतनी ज्यादा नजर नहीं मालूम होगी । और मैंने जैसा निवेदन किया इसे निपटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । जिस खतरे का संकेत किया है उस ओर से भी सजग हैं कि शिक्षक को यह महसूस करने का मौका न आवे ।

श्री भैरोंसिंह : यहां सजग होने का सवाल नहीं पैदा होता । इस सदन में इस बारे में कम से कम दस बार मन्त्री और उप-मन्त्रीजी ने आश्वासन दिये हैं कि एक साल में बकाया दे दी जावेगी, छः महीनों में दे दी जावेगी । मैं निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय, उनके वे आश्वासन आज भी वैसे ही पड़े हैं । इनको जरा यह तो पूछें आप कि इनके टी.ए.,डी.ए. का एक पैसा भी कभी रुका है । बिल नहीं बनता, उससे पहले लेने की कोशिश करते हैं । आखिर ये करते क्या हैं ? १६ लाख का बकाया वर्षों से उन गरीब मास्टरों का लिये हुए बैठे हैं ! आज किसी भी प्रकार से यह न्याय की स्थिति नहीं कही जा सकती । कहने को कहते रहे कि वे एफर्ट्स कर रहे हैं । पर यह सरकार के लिये एक कलंक की बात है कि गरीब टीचरों का दस लाख रुपया खाकर आप बैठे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने अपने विचार व्यक्त किये । हमने प्रयास किया है । प्रति वर्ष प्रयास करते हुए शिक्षक को इस सम्बन्ध में एश्योरेन्स देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे आंकड़े मैं सदन में रख देता तो मुमकिन है हमारे प्रयासों की ओर संकेत मिलता । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सेक्रे-टरी, श्री शेखावत भी हमारे साथ प्रयत्नशील हैं और सहयोग दे रहे हैं । हम दोनों मिल कर प्रयास कर रहे हैं । मैं विश्वास दिलाता हूँ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): केवल बातों से तो काम नहीं चलने वाला है । इस तरह के आश्वासन 'इफ' और 'बट' में तो सुनते सुनते पूरे दो वर्ष हो गये हैं । कोरे आश्वासनों पर अब हम विश्वास करने वाले नहीं हैं । इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय को सख्ती से दृढ़ कदम उठाने चाहिये । क्या कभी आर० ए० एस० और आई०ए०एस० अफसर की सैलेरी रुकी है ? सैलेरी तो दूर रही, स्पेशल सैलेरी तक नहीं रुकती, उनका टी०ए०, डी०ए० नहीं रुकता । मन्त्रीजी की तनख्वाह नहीं रुकती, उनका टी०ए०, डी०ए० नहीं रुकता, राजाओं का तीस तीस लाख बकाया माफ हो जाता है । पर १६ लाख इन गरीब टीचरों का ही रुकता है । यह इस जनता की सरकार होने का दम भरने वाली सरकार के लिये एक अत्यन्त लज्जा और कलंक का विषय है !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रश्न करिये । आप तो लेक्चर झाड़ रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कैटेगेरिकली एश्योरेन्स चाहते हैं कि एक वर्ष के अन्दर अन्दर १६ लाख की बकाया दे देंगे, गवर्नमेन्ट को चाहे इसके लिये स्पेशल डाइरेक्टर ही क्यों न करना पड़े, पांच हजार खर्च भी क्यों न करने पड़ें; पर अब इस

(श्री भैरोंसिंह)

स्थिति को टोलरेट करने को हम तैयार नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या प्रयत्न कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट मैं सदन की मेज पर रख दूंगा। एक हफ्ता का समय आप इसके लिये मुझे दें। एक हफ्ते का समय चाहता हूं। इसके बारे में एक स्टेटमेन्ट दे दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: One Question।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं क्वेश्चन तो कर लूं। आप जवाब किसका देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो १६ लाख की बकाया का मामला है, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न बन गया है और मैं सदन के माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूं कि अध्यापकों की १६ लाख की बकाया सरकार में रहे तो यह चिंतन का विषय बन जाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा क्लेरीफिकेशन दे दूं। ये ५ तरह के एरियर्स हैं १६ लाख रुपये के। एक तो हमारे यहां पर जो रिवाइज्ड पे स्केल हुए, यूनीफाइड पे स्केल हुए उसके अन्दर बहुत से डिफरेन्ट टीचर्स का फिक्सेशन क्लेम है। किसी का फिक्सेशन यूनीफाइड पे स्केल में नहीं हो पाया, किसी का रिवाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन नहीं हो पाया, कोई टीचर छुट्टी चला गया महीने दो महीने की, उसके बाद उसकी तनख्वाह बन्द हो गयी और कोई ऑडिट से ऑब्जेक्शन्स रेज़ हो गए तो इस तरह के मामले हैं; यह कुछ टी० ए०, डी० ए० की मामूली रकम है। कोई टीचर्स इन्डीविजुअल के बहुत पैसे तो होते नहीं हैं टी ए०, डी० ए० के। इस प्रकार का मसला कोई इसी विभाग में नहीं है। जब मैं होम मिनिस्टर था तो मुझे तजुर्बा था, हमारे पुलिस में भी इसी तरह के कई फिक्सेशन के सवाल हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने कर दिया और शिक्षा विभाग नहीं कर पाया, यही तो कहना है।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए यह जो रकम आपको दिखती है यह ५ केटेगरी में है; टी० ए० बिल्स, फिक्सेशन और उसके बाद में लीव पर चले जाने के बाद में और उसके बाद में इन्क्रीमेन्ट ड्यू हुए; ये सब मिलाकर १६ लाख रुपये हो जाते हैं सारे राजस्थान के। इसके लिए स्पेशल अकाउन्ट्स ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट ने लगा रखा है जो कि इस मामले में इन्डीविजुअल केसेज़ के ऊपर गौर करता है। अगर कोई एक केटेगरी का मसला हो तो जल्दी हो जाये, लेकिन बहुत ज्यादा मामले हैं; इसलिए सबके रिप्रेज़ेन्टेशन्स को देखना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है। फिर भी शिक्षा मंत्री और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इसको साल भर के अन्दर अगले फाइनेन्शियल ईयर के अन्दर बिलकुल निपटा दें। क्योंकि जब तक टीचर्स को सेटिस्फेक्शन न हो कि प्रोपर्ली फिक्स हो गये हैं तब तक....

श्री अध्यक्ष : स्पेशल अकाउन्ट्स ऑफिसर कब से है ?

कुछ माननीय सदस्य : है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : सारी बहस का मतलब यही है कि माननीय सदस्यों को संतोष नहीं है कि सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है, जितना होना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : माननीय सदस्यों को संतोष दिलाने के लिए कहना चाहता हूं कि १९६२-६३ में किस किस जिले में कितनी रकम का चुकारा हुआ, उसके आंकड़े बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : उससे संतोष नहीं होता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दो सवाल हैं; एक तो यह कि फिक्सेशन के मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की....

श्री अध्यक्ष : क्या विशेष प्रयत्न किये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यही कि उसके लिए अकाउन्ट्स ऑफिसर नियुक्त किये।

श्री अध्यक्ष : यही पूछ रहे हैं कि कब से किया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह इस समय सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यही तो चाहिए, ताकि पता लग जाये कि पिछले वर्ष में सरकार कितनी सतर्क रही है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं आपको कल इसकी जानकारी दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Order ! Order please!! यह कल जवाब दे देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बोले जा रहे हैं मेरे मना करने के बाद में भी। आप कल जवाब दे देंगे।

प्रश्न संख्या ५४

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५

श्री अब्दुलजब्बारखां।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

लाखेरी ग्राम से स्टेशन तक सड़क निर्माण में विलम्ब

५६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी ग्राम से स्टेशन तक सड़क बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार से हो चुकी है ?

(२) यदि हां, तो यह मंजूरी कौन से वर्ष में हुई थी एवं इसका ठेका कौन से वर्ष में दिया गया था ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क के किनारे ४ वर्ष से गिट्टी व मिट्टी डाल रखी है किन्तु सड़क की कुटाई अभी तक नहीं करवाई गई हैं ?

(४) यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण में देरी होने व प्रत्येक साल बजट में रकम लैप्स होने के कारण क्या है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) वर्ष १६५६ में इस कार्य का ठेका १६६०–६१ में दिया गया था।

(३) कलकेशन व कुटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(४) रेखरण (Alignment) के झगड़े के कारण।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह कितनी मील लम्बी सड़क है, लाखेरी ग्राम से स्टेशन तक की ओर पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जमीन के झगड़े के कारण।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी मील लम्बी सड़क है और मैंने प्रश्न किया है कि ४ वर्ष से गिट्टी और पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कुटाई उसकी पूरी की जा चुकी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सड़क के किनारे पर गिट्टी और पत्थर के चक्के लगे हुए हैं, सड़क का काम पूरा नहीं हो रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, कागज पर पूरी हो गयी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सड़क पूरी की पूरी पड़ी हुई है और पत्थर, गिट्टी वगैरह उसके किनारे पर पड़ी हुई है और मंत्री महोदय चाहें तो मैं उनको चलकर दिखा दूं। आप कह रहे हैं कि पूरी हो चुकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पेमेन्ट का काम पूरा हो गया दीखता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जांच करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की तरफ से कुछ उत्तर मिलता है और मेम्बर जो प्रश्न पूछता है उसको चेलेन्ज करते हैं। आखिर इसकी कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए कि दोनों में से ठीक कौन है। मंत्री महोदय कहते हैं कि सही है और दूसरी बार मेम्बर कहते हैं कि गलत है और जो प्रत्यक्ष में सड़क को देखते हैं, उस पर चलते हैं वह कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है और मंत्री महोदय कह दें कि हो गया है, तो सदन में किसकी सूचना गलत है कम से कम सदन के द्वारा कोई जांच समिति या कुछ तो होना चाहिए जिससे मालूम हो जाये कि कौन सही है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय सूचना

(श्री अध्यक्ष)

विभागीय सूचना के आधार पर देते हैं और माननीय सदस्य जो वहां की प्रत्यक्ष स्थिति है उसकी जानकारी के आधार पर बात कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय को स्वयं को स्वीकार करना चाहिए और वे करते हैं। जो माननीय सदस्यों ने बात कही है वह तथ्यपूर्ण है और उसी को ध्यान में रखते हुए केवल इस बात में नहीं बल्कि और बातों में भी जांच करेंगे कि स्थिति क्या है।

श्री भैरोंसिंह : परन्तु मालूम कैसे हो कि कौन सही है और कौन गलत है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जांच करवा ली जायेगी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के सवाल पहले भी आये हैं और जांच भी की गयी है। निम्बाहेड़ा से आये हुए माननीय सदस्य ने एक बार रखा था और जो सूचना हमें मिली थी उसके ऊपर मैंने इन्क्वायरी कराई और उसकी रिपोर्ट भी उनके पास भेज दी गयी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी सूचना गलत है तो मैं त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हूँ।

श्री हरिश्चन्द्र : हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपकी सूचना गलत है या हमारे पास जो सूचना है वह गलत है ; हम इसकी जानकारी करवायेंगे और फिर उसकी सूचना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : जो मंत्री महोदय ने प्रक्रिया बताई है वह संतोषजनक है। जो माननीय सदस्य यहां पर बात उठायें उसका निराकरण जांच करके कर लें और जैसा भी हो हमारे सचिवालय को इसकी जानकारी दे दें।

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवामहल, जयपुर) : उसका पेमेन्ट राज्य सरकार ने कर दिया और पेमेन्ट कर दिया, यह जानने की जरूरत नहीं कि अब सड़क बनी या नहीं। एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि पत्थर, गिट्टी वगैरह सड़क के किनारे पर पड़ी हुई है और काम नहीं हुआ है और चूंकि सरकार ने पेमेन्ट कर दिया होगा तो समझ लिया होगा कि काम पूरा हो गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार में पूरी हर प्रकार की व्यवस्था है; कौन जांच करेगा और कौन पेमेन्ट करेगा। हर एक के बारे में यह कह देना कि पैसा दे दिया जाता है, बात गलत है।

नेक्स्ट। श्री रामकिशन।

श्री गोपीनाथजी का मंदिर, कामां

५७. श्री **रामकिशन** (वैर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कामां, जिला भरतपुर, स्थित मंदिर श्री गोपीनाथ जी को किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता मिलती है ? यदि हां, तो क्या ?

(२) क्या इस मंदिर पर कभी कोर्ट ऑफ वार्ड्स हुआ है ? यदि हां, तो कब और किस कारण ?

(श्री रामकिशन)

(३) क्या इस मंदिर की चल–अचल सम्पत्ति सम्बन्धी कोई रेकॉर्ड है ? यदि हां, तो कब से और वह किसके द्वारा प्रमाणित है ?

(४) क्या सरकार को मंदिर की जायदाद बेचे जाने और कुप्रबंध के सिलसिले में कोई शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो जांच द्वारा सरकार किस नतीजे पर पहुँची है व जांच कब और किस अधिकारी के द्वारा हुई है ?

(५) क्या यह सत्य है कि मंदिर के कामदार ने मंदिर की कुछ दूकान, मकान तथा खाली जगहों को बेच दिया है और आय को मन्दिर कोष में जमा नहीं किया है ?

(६) क्या मंदिर की जायदाद संबंधी रजिस्टर के मुताबिक मन्दिर की जायदाद को कभी किसी अधिकारी ने जांचा है ? यदि हां, तो कब, किस अधिकारी ने और परिणाम क्या रहा है ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं ।

(२) इस मंदिर पर सन् १६४२ में कोर्ट ऑफ वार्ड्स हुआ था । मन्दिर के गोस्वामी का देहान्त हो जाने तथा उसके वारिस के नाम दाखिल खारिज होने के कारण मन्दिर कोर्ट ऑफ वार्ड के प्रबंध में रखा गया था ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी हां, मन्दिर के कुप्रबंध के सिलसिले में सन् १६५५ में शिकायतें हुई थीं । विशेष रूप में मन्दिर के कामदार के विरुद्ध थी जो कि ठिकाने के गोस्वामी द्वारा नियुक्त था । जांच सन् १६५५ में इन्सपेक्टर, भरतपुर द्वारा कराई गई थी । जांच द्वारा जायदाद को नष्ट करने तथा मन्दिर की व्यवस्था खराब होना पाया गया ।

(५) इस प्रकार की विभाग में कोई सूचना नहीं है ।

(६) मंदिर की जायदाद को संबंधी रजिस्टर के मुताबिक किसी अधिकारी द्वारा जांच किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामकिशन : आपने प्रश्न के भाग (५) व (६) का जवाब दिया है, उसकी जांच करने के लिए इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि यह प्राइवेट प्रोपर्टी है और टेम्पल भी प्राइवेट प्रोपर्टी है । अब इसके रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही चल रही है और ज्यों ही वह कम्प्लीट हुई हमारे हाथ में सेक्शन ३८ आ जाता है, जिसके तहत उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

नाथद्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का क्षेत्र एवं मुकदमों की संख्या

५८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा); क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नाथद्वारा तथा भीम के लिए एक ही मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं ?

(श्री विजयसिंह झाला)

(२) क्या नाथद्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के क्षेत्र का कार्य देखते हुए दोनों जगह कार्य करना उपयुक्त है ?

(३) माहवारी औसतन मुकदमों की संख्या नाथद्वारा तथा भीम की अलग-अलग कितनी है ?

उप-मंत्री, विधि एवं न्याय (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) नाथद्वारा व भीम की माहवारी औसतन मुकदमों की संख्या इस प्रकार है :—

	सिविल	क्रिमिनल	योग
(१) मुंसिफ मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	१५	१५	३०
(२) मुंसिफ मजिस्ट्रेट, भीम	१६	८	२७

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : नाथद्वारा के मुकाबले में भीम में केसेज़ ज्यादा हैं इसका यह मतलब हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब यह हुआ कि नाथद्वारा में औसतन केसेज़ महीने भर में ३० है और वहां २७ हैं। टोटल केसेज़ जो अभी हैं वह नाथद्वारा में २६१ हैं और भीम में २१६ हैं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या सरकार की तरफ से ऐसा क्राइटेरिया निश्चित है कि इतने केसेज़ का एवरेज होने पर मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट रखेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : हाई कोर्ट ने यह क्राइटेरिया फिक्स किया है कि एक मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के पास में मुकदमों की संख्या जब तक ५०० नहीं होती है तब तक पूरा वर्क लोड नहीं होता है।

बीकानेर में पोलीटेक्नीक की बिल्डिंग

५६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर में पोली-टैक्नीक की बिल्डिंग के लिए धनराशि गत वर्ष के बजट में रखी जाने पर भी वह कार्य अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ तथा कब तक प्रारम्भ हो जावेगा।

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : नवीन पोलीटेक्नीक भवन के स्थान पर पुराने डूंगर कॉलेज में एडीशन ऑल्टरेशन किये जाने की स्वीकृति दिये जाने के कारण।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि भवन-निर्माण के लिए सरकार ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि नई बिल्डिंग बनाने के लिए टेन्डर इन्वाइट कर लिए गये हैं और वर्क ऑर्डर दे दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वर्क्स में कटौती के कारण इस योजना को रद्द कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पोली-टेक्नीक इन्स्टीट्यूशन में कई छात्र बाहर से आते हैं उनका वहां पर रहने का प्रबन्ध नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

है। जैसा कि आप कहते हैं कि डूंगर कॉलेज की बिल्डिंग है वहां डूंगर कॉलेज के ही छात्र रहते है। यह पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट का छात्रावास नहीं है। वह भी उसके अन्तर्गत थे। तो क्या छात्रावास बनने की योजना रखी गई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : संबंधित विभाग से इसके बारे में जानकारी करें तो संबंधित विभाग इसका उत्तर दे सकेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : विभाग से मैं जानकारी क्या करूं ? आपकी पहले बिल्डिंग बनाने की योजना थी और वह बजट में आया भी हो गया था; वह भी नहीं बनाया गया। उसके ऊपर जवाब है कि उसके अन्दर ऑल्ट्रेशन किया जा रहा है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उसके अन्दर जो छात्र है उनके लिए भी होस्टल की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण विभाग केवल भवन-निर्माण करता है और वह संस्था जिस विभाग द्वारा चलाई गई है उनके बजट वगैरह में पैसा हो तो भवन-निर्माण होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : बजट में पैसा था और बजट में आया हो गया था तो भी नहीं बनी हैं, तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस विभाग के जरिये जैसे ऑल्ट्रेशन की बात कही जा रही है तो उसमें होस्टल की योजना है कि नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी तक तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या प्रबन्ध होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

आबकारी एवं कर विभाग, निम्बाहेड़ा के भवन की बिक्री

६०. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

निम्बाहेड़ा में जो मकानियत आबकारी एवं कर विभाग द्वारा काम में ली जा रही है क्या वह बेची जा रही है ? यदि हां, तो क्या वह किसी स्कूल के लिए निश्चित कीमत पर दी जा सकती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : सुना नहीं साहब कुछ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका यूज होना चाहिए। क्या विभाग समझता है कि इसकी रेन्टल वेल्यू कितनी आती है ? यह लाभ होता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मकान ऑफिस के काम में आ रहा है, इसलिए बेचने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अब्दुलजब्बार : वहां पर स्टाफ कितना है ताकि इतनी बड़ी बिल्डिंग का उपयोग सही हो ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : स्टाफ कितना है इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार : प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि वहां पर एक चपरासी और इन्सपेक्टर रहता है और एक लाख की बिल्डिंग बेकार पड़ी हुई है । इसके लिए विचार करेंगी क्या सरकार ?

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा , ३४ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (रायसिंह नगर) : प्रश्न संख्या ४७ लेलें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ३४ ।

फर्टीलाइजर फैक्ट्री, हनुमानगढ़

३४. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर) : क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ फर्टीलाइजर फैक्ट्री लगाने का लाइसेन्स रतनगढ़ के सेठ श्री जालान को दिया गया तथा उन्हें बिजली, लिग्नाइट की कीमत तथा जिप्सम की दरों में कुछ रियायतें देने का पैक्ट भी सरकार ने किया है ? यदि हां, तो कितनी कितनी रियायतें देने का पैक्ट किया है और वे क्या रियायतें दी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त फैक्ट्री का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है तथा श्री जालान कुछ और रियायतें मांग रहे हैं ?

(३) सरकार इस फैक्ट्री को तुरन्त आरम्भ करवाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, श्री जालान को फर्टीलाइजर फैक्ट्री लगाने का लाइसेन्स दिया गया है । सरकार ने बिजली (लिगनाइट) व जिप्सम की दरों में रियायत नहीं दी है ।

(२) जी हां ।

(३) राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरू कराने के लिए प्रयत्नशील हैं, और इस मामले में भारत सरकार और श्री जालान के बीच बात चल रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कितना समय लगेगा इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में ? कब से आरम्भ हो जायगा यह प्रोजेक्ट ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह कहना अभी बड़ा मुश्किल है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हमने सुना है कि यह प्रोजेक्ट उदयपुर जा रहा है, यह कहां तक सही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिए श्री जालान और भारत सरकार में बात-चीत चल रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय मुख्य मंत्री से पूछ लें और बता दें । अखबार में मैंने एक न्यूज़ देखी है कि यह प्रोजेक्ट उदयपुर जा रहा है हनुमानगढ़ से ।

Page No. 27

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : मैं निवेदन कर दूं कि यह प्रोजेक्ट उदयपुर नहीं जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जो बातचीत श्री जालान और भारत सरकार के बीच चल रही है तो कौन सी चीज है जिससे इसमें रुकावट पैदा हो रही है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : फर्टीलाइज़र बनाने के लिए जिप्सम के साथ में जो जरूरी होती है वह उसका ट्रान्सपोर्ट कोस्ट, उसकी वजह से काफी हरडल पैदा हो रही है, क्योंकि नेप्था की कोस्ट काफी ज्यादा पड़ती है और उतनी कोस्ट पड़ने के बाद में श्री जालान का यह कहना है कि फॉरिन् कोलेबोरेशन के लिए काफी दिक्कतें सामने आती हैं। इस वजह से भारत सरकार को उन्होंने साइट चैन्ज करने के वास्ते मूव किया हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस समय ओरीजिनल लाइसेन्स दिया जाता है तो क्या इन तमाम बातों, कि कौन से रॉ मेटेरियल की जरूरत पड़ेगी और उनकी पूर्ति कैसे कैसे होगी, इन पर बातचीत करने के बाद में लाइसेन्स नहीं दिया जाता है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इतने डिटेल्स के अन्दर उस वक्त नहीं जा सकते हैं जिस वक्त कि लाइसेन्स दिया जाता है। उसके बाद में कोस्ट, फॉरिन् कॉलेबारेशन की बातचीत होती है। फॉरिन् कोलेबोरेशन में क्या क्या डिटेल्स जानना चाहते हैं, ये सारे फेक्टर्स बाद में डिसकस होते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि जैसी स्थिति रही हनुमानगढ़ में कि जिस फर्म को लाइसेन्स दिया गया है वह किन आधार पर साइट बदलने की बातचीत कर रही है; तो क्या ऐसे क्वेश्चन्स को लाइसेन्स देने से पहले तय करना सही नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : सेन्ट्रल गर्वनमेंट देखती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह जो फैक्ट्री लगाई जा रही है तो पहले पब्लिक सेक्टर में लेने की भारत सरकार की बात थी। उसके लिए यहां बाकायदा एक कमीशन भी आया था और उसने रिपोर्ट भी तैयार की थी। उस समय सब डिसकशन्स हुए थे कि लिग्नाइट का रेट क्या हो, कितना चाहिए; उसके बाद में यह स्कीम ड्रॉप आउट हुई और वह नांगल में लगी। ये बातें पहले नहीं सोची गई कि नेप्था वगैरह की कोस्ट इतनी होगी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने निवेदन किया कि पहले सोचा गया था। जो फैक्ट सामने थे उनके आधार पर उन्होंने एप्लीकेशन दी और हमने जिस वक्त कि लाइसेन्स दिया जा रहा था तो भारत सरकार से यह कहा था कि हम चाहते हैं कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री राजस्थान के अन्दर तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित होनी चाहिए। हम प्रिफर करेंगे कि वह पब्लिक सेक्टर के अन्दर हो, लेकिन फैक्ट्री राजस्थान के अन्दर लगनी चाहिए। उसके बाद में जिन्होंने एप्लाई किया और जिस स्थान के लिए एप्लाई किया उस वक्त में जो सरकमस्टान्सेज़ एग्ज़िस्ट करते थे उस आधार पर उन्होंने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एप्लाई किया। उन सारी बातों को देखते हुए भारत सरकार ने लाइसेन्स दिया। अब साइट चेन्ज करना चाहते हैं तो जो बात उस वक्त आई थी आज भी है। साइट बदलने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट रिकमेन्ड नहीं कर रही है। भारत सरकार के पास में जो फैक्ट्स लाइसेन्स देने के वक्त में थे वे आज भी हैं और उन पर वह निर्णय करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑल्टरनेटिव साइट कौन सी सजेस्ट की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह ऑल्टरनेटिव साइट कोटा के लिए एप्लाई कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान में एक और फैक्ट्री फर्टीलाइज़र जयसमन्द पर बनाने का विचार भारत सरकार और राजस्थान के बीच में चल रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भारत सरकार हमारी तरफ से प्राइवेट सेक्टर में नहीं लगा रही है। कहां पर चीपेस्ट फर्टीलाइज़र तैयार हो सकता है इसको देख करके साइट तैयार करना चाहिए। दो साइट हैं; एक उदयपुर के पास जयसमन्द और दूसरा बीकानेर का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस सम्बन्ध में लाइसेन्स देने में जो प्राइवेट केपिटलिस्ट्स हैं उनको मेग्ज़ीमम प्रोफिट कहां हो सकता है, उसका ध्यान रखती है या रीजन विकास हो सकता है सब जगह, इसका भी ध्यान रखती है क्या ?

निम्बाहेड़ा से बेगूं रूट की बसों का टाइम टेबल

५५. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(१) निम्बाहेड़ा से बेगूं कितनी बसें चलती हैं ? उनके टाइम टेबल की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा से शाम को बगैर स्वीकृति के मोटरें चलती हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? यदि नहीं लिया, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) निम्बाहेड़ा से बेगूं रूट पर दो बसें नं० आर० जे० एच० ४४ और आर० जे० एम० ४६ के परमिट दिए हुए हैं। इन दो बसों में से एक बस निम्बाहेड़ा से बेगूं तक और दूसरी निम्बाहेड़ा से कनेरा तक आर० टी० ए०, उदयपुर द्वारा स्वीकृत टाइम टेबल के अनुसार चलती हैं, इनके चलने के टाइम टेबिल की सूची संलग्न है।

(२) ऐसी कोई गाड़ी बगैर स्वीकृति के नहीं चलती। अतः एक्शन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री अब्दुल जब्बार : आर० जे० एच० ३०७ कोई गाड़ी रन करती है, उसके सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?

श्री भीमसिंह : आर० जे० एच० कोई गाड़ी नहीं चलती है, आपकी सूचना गलत है।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं निवेदन करता हूँ कि ३०७ नम्बर को गाड़ी चलती है।

दूसरी बात यह है कि आपने जो परमिट निम्बाहेड़ा-बेगूं का दिया है वह कनेरा से बेगूं तक चलती है। ये चेन्जेज़ क्यों हुई हैं?

श्री भीमसिंह : आर० टी० ए० से दुबारा चेन्ज कराया है क्योंकि वहां पर सवारियां उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिये यह कर्टेलमेन्ट स्वीकृति लेकर किया गया है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या इस तरह का कर्टेलमेन्ट हो सकता है? क्या सरकार के पास इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ है?

श्री भीमसिंह : हो सकता है, तभी आर० टी० ए० ने किया है अन्यथा अपील में जाता।

श्री अब्दुलजब्बार : दूसरा यह अर्ज करना है कि इन दो गाड़ियों के अलावा ३०७ नम्बर की गाड़ी भी चलती है। इसका ओनर कौन है और यह क्यों चलती है, क्या आप इसकी जांच का आश्वासन देते हैं?

श्री भीमसिंह : ३०७ नम्बर की कोई गाड़ी नहीं चलती है। आपको शायद भ्रम हो रहा है; वह यह है कि ४४ नम्बर की गाड़ी खराब होने से उन्होंने आर० टी० ओ० से ३०९ नम्बर की गाड़ी चलाने के लिए स्वीकृति ली है और वह चार माह से चल रही है। आपको शायद यह भ्रम हो गया है कि वह ३०७ नम्बर की गाड़ी है।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं कहता हूँ कि वह ३०७ नम्बर की ही है, ३०९ नम्बर की नहीं है; आप अमेन्डमेन्ट करलें। और दूसरी बात यह है कि कानूनन ऐसा करना गलत है या नहीं, इसकी जांच कर लें।

श्री भीमसिंह : मेरी सूचना के अनुसार स्वीकृति ३०९ की दी है आर० टी० ए० ने। अगर ३०९ के बजाय ३०७ नम्बर की गाड़ी चलती है और वाकई ३०७ नम्बर की गाड़ी की ही स्वीकृति दी है तो हो सकता है कि टाइप की मिस्टेक रह गई है।

श्री अब्दुलजब्बार : बनेड़ा से निम्बाहेड़ा दो बसें शाम को नहीं आती हैं। विभाग से मंत्री महोदय को जो सूचना दी गई है वह गलत है। निम्बाहेड़ा में ६.३० बजे और ६ बजे का कहा गया है वह गलत है।

श्री भीमसिंह : एक बस साढ़े छः बजे शाम को पहुँचती है और दूसरी सुबह १० बजे पहुँचती है।

श्री अब्दुलजब्बार : शाम को, ६ पी० एम० का लिखा है।

श्री भीमसिंह : मैंने भी ६.३० बजे शाम बताया है और दूसरी १० बजे सुबह।

श्री अब्दुलजब्बार : Departure from Nimbahera at 7.30 A. M. Arrival at Begun at 12.00 Noon.

Departure from Nimbahera at 4.00 P. M.

Arrival at Banera at 0.00 P. M.
Departure from Begun at 2.00 P.M.
Arrival at Nimbahera at 6.30 P.M.
Departure from Banera at 8.00 A.M.
Arrival at Nimbahera at 10.00 A.M.

(श्री अब्दुलजब्बार)

ये रेगुलरली नहीं पहुँचती हैं। पुलिस का रेकार्ड मंगाकर देख लीजिए, कितनी इर्रेगुलेरिटीज़ हो रही है नेताओं की छत्र-छाया में, नेताओं की गाड़ियां चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : कारण नहीं बतावें इस बारे में।

श्री अब्दुलजब्बार : अभी जैसे भरतपुर के पास आग लगी थी उसी तरह से एक्सीडेन्ट्स होंगे और आग लगेगी क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

दिनांक २४ फरवरी, १६६४ का स्थगित प्रश्न

क्रय विक्रय सहकारी समिति

६. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़)** : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में क्या क्रय-विक्रय सहकारी समिति का निर्माण हुआ है। अगर हां, तो कब से ?

(२) इस समिति को गोदाम बनाये जाने बाबत सरकार से कितना अनुदान एवं कितना लोन दिया गया ? क्या यह गोदाम सम्पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) इस समिति का राज्य सरकार द्वारा कितनी बार ऑडिट हो चुका है। ऑडिट के परिणाम के बारे में विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) केन्द्रीय क्रय-विक्रय संघ से इस समिति को कितना गेहूँ दिया गया ? क्या उसका हिसाब कुलया भुगतान हो गया ? नहीं, तो क्यों ?

(५) इस समिति में राज्य सरकार की कितनी हिस्सा पूंजी है ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) चित्तौड़गढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक १५.१२.५६ को हुआ है ?

(२) ऋण रु० १८,७५० गोदाम निर्माण हेतु दिया गया।

अनुदान रु० ६,२५०)

गोदाम निर्माण पूर्ण हो चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

(३) समिति का ऑडिट ४ बार हुआ है। ऑडिट रिपोर्टों में उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति के लिए समिति को लिखा गया और समिति द्वारा अब तक अधिकांश आक्षेपों की पूर्ति की जा चुकी है।

(४) राजस्थान राज्य क्रय—विक्रय सहकारी संघ लि० द्वारा इस समिति को ६४६२ मन २० सेर गेहूँ दिया गया। अब समिति को रु० ५५२३.८१ ही केवल देना शेष है। हिसाब का निबटारा हो चुका है।

(५) समिति में राजकीय हिस्सा राशि रु० २५,०००) मात्र है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या गोदाम निर्माण में निर्धारित से ज्यादा रकम लगी है?

श्री अध्यक्ष : जितनी रकम लगी है, वह बता दीजिये।

श्री भीमसिंह : मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ताश बनाने का कारखाना, भरतपुर

१०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भरतपुर में ताश बनाने का कोई कारखाना है? यदि हां, तो कब से?

(२) इस कारखाने को सरकार की तरफ से किस किस चीज का कितना कितना कोटा मिलता है?

(३) इस कारखाने में अब तक कितना प्रोडक्शन हुआ है और उसकी खपत कहां कहां हुई है?

(४) क्या इस कारखाने के लिये कोटा देने की किसी अधिकारी ने सिफारिश की थी? यदि हां, तो किसने?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जिला उद्योग अधिकारी के भरतपुर में ताश बनाने का कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर राजस्थान पेपर एण्ड अलाइड इन्डस्ट्रीज़ को ५०,६२५) रुपयों के मूल्य का कागज आयात करने का ई० सी० (Essentiality Certificate) उद्योग विभाग द्वारा दिया गया था पर import Licence न मिलने के कारण पार्टी के इस उद्योग के चालू न कर सकने पर उपरोक्त ई० सी० को रद्द करने के आदेश संचालक उद्योग विभाग द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं।

सरकार द्वारा नियंत्रित मन्दिरों की सम्पत्ति

११. **श्री विट्ठल भाई** (बांसवाड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य में सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों की अचल सम्पत्ति कितनी मालियत की है?

(२) राज्य में सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों की चल सम्पत्ति कितनी मालियत की है; अर्थात् सोना, चांदी, जेवर, बरतन, कपड़े, हीरे तथा जवाहरात आदि कितनी मालियत के हैं, और नकद रुपया कितना है?

(३) क्या सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों का रुपया किसी और उद्योग में भी लगा हुआ है? यदि हां, तो कहां २ किस किस उद्योग में और इससे वार्षिक आमदनी क्या होती है?

(४) क्या सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों की जायदाद, रुपया पैसा, सामान तथा चल-अचल सम्पत्ति और आय-व्यय की जांच

Page No. 32

(श्री विट्ठल भाई)

कराई जाती है ? यदि हां, तो वर्ष में कितनी बार ?

(५) क्या सरकार को किसी मंदिर में गबन, अव्यवस्था तथा धन के दुरुपयोग अथवा सम्पत्ति नष्ट करने की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो कहां २ से और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) राज्य में सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों की अचल सम्पत्ति जोधपुर व बीकानेर डिवीज़न में ३५,४०,८५७) रुपये की है। तथा जयपुर डिवीज़न में केवल ३० मंदिरों की ३०,१७,०८६) रुपये की मालियत की है। उदयपुर व कोटा डिवीज़न और जयपुर के १०५ मंदिरों की अचल सम्पत्ति का अभी मूल्यांकन होना शेष है।

(२) राज्य में सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों की चल सम्पत्ति कुल ४५,११,८१४) रुपये की मालियत की है। जिसमें सोना, चांदी हीरे, जवाहरात आदि का मूल्य शामिल है। कपड़े व बर्तन का मूल्यांकन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त नकद रुपया ६६,३८,३९०) तथा ६३ नये पैसे हैं।

(३) सरकार द्वारा नियंत्रित आत्म-निर्भर मंदिरों का ३०,००,००० (तीस लाख) रुपये इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को कर्ज दिया गया है जिसकी वार्षिक आय १,८०,००० रुपये होती है। इसके अलावा शेष राशि राजस्थान डेवलपमेंट लोन, सिक्योरिटी एण्ड शेयर्स तथा नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट आदिमें लगी हुई हैं जिसके ब्याज की आय अन्दाजन १,००,०००) (एक लाख) रुपया होती है।

(४) सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों की जायदाद रुपया पैसा तथा चल-अचल सम्पत्ति और आय-व्यय की जांच स्वीकृत नियमों के अनुसार समय समय पर कमिश्नर, सहायक कमिश्नर्स तथा इन्स्पेक्टर्स द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा महालेखापाल, राजस्थान, जयपुर व परीक्षक, लोकल फण्ड की पार्टी तथा देवस्थान विभाग की इण्टर्नल चैकिंग पार्टी भी इसकी जांच करती रहती है।

(५) जोधपुर डिवीज़न के कुछ मंदिरों में अव्यवस्था तथा धन के दुरुपयोग अथवा सम्पत्ति नष्ट करने की शिकायतें सहायक कमिश्नर, देवस्थान विभाग, जोधपुर के कार्यालय में प्राप्त हुई हैं जिसकी सूची संलग्न है। इन शिकायतों पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है। शेष किसी भी डिवीज़न में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

निम्बाहेड़ा में बिजली के कनेक्शन्स देने में विलम्ब

१२. **श्री अब्दुल जब्बारखां** (निम्बाहेड़ा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निम्बाहेड़ा में सन् ६३–६४ में कुल कितनी किलोवाट बिजली जेनरेट होती रही है ?

(२) कंज़म्पशन कितना होता रहा है ?

(श्री विठ्ल)

(३) कनेक्शन कितने दिये गये और कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं ? क्या कनेक्शन देने में देरी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या विभाग को इस प्रकार की देरी करने से नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो प्रति मास नुकसान का औसत ६३-६४ का बताया जाय ?

(५) इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है, और विभाग उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ।

उत्तर

(१) कुछ नहीं। निम्बाहेड़ा में बिजली जेनरट नहीं होती है.।

(२) जनवरी ६४ तक १,०७,१०० यूनिट बेचे गये।

(३) ३५६ कनेक्शन्स दिये गये हैं और २६ दरख्वास्तें अभी शेष हैं। जी हां, २ पॉवर कनेक्शन्स देने में देर हुई है क्योंकि रेल्वे लाइन पार करनी है। शेष कन्ज्यूमर्स ने नियमानुसार आवश्यक फोर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की हैं।

(४) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कस्बा नगर में बिजली की सप्लाई

१३. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा नगर, जिला भरतपुर को सन् ६३-६४ में बिजली सप्लाई हो जायेगी ?

(२) यदि हां, तो आवश्यक सामान वहां कब तक पहुँचा दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां, कार्य को पूरा करने की कोशिश की जा रही है । सामान पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है ।

राश्मी-गंगरार सड़क

१४. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील राश्मी से गंगरार आने वाली सड़क का कार्य कहां तक हो चुका है ? यह सड़क कब तक बन जायेगी ?

उत्तर

राश्मी से सड़क तीन माइल एक फर्लांग बन चुकी है। आशा है, चतुर्थ योजना काल में।

जयपुर-बीकानेर हाईवे

१५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर से बीकानेर हाईवे के कार्य को गति प्रदान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(२) यह कार्य कब तक पूरा हो जावगा ?

उत्तर

(१) ८५,४६,७४०)रु० की लागत के कार्य नेशनल हाईवे नं० ११ पर स्वीकृत कर दिये गये हैं और २८,३८,०५०) रु० के एस्टीमेट भारत सरकार के विचाराधीन है।

(२) आशा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ण हो जायगा।

टोंक जिले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृति

१६ श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) जिला टोंक में सन् १९६१ और १९६२ में कितने रुपये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के दिये गये तथा उक्त जिले से कितने छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-फॉर्म भर कर भेजे थे?

(२) जिले भर में कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली व कितने आवेदन-पत्र खारिज किये गये?

(३) क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-फॉर्म समय पर नहीं मिलने से कई छात्र समय पर आवेदन-फॉर्म नहीं भर सके? छात्रवृत्ति के आवेदन-फॉर्म किन तिथियों में कहां कहां कैसे भेजे जाते हैं?

उत्तर

१) सन ६१ में ४१४ छात्रों ने फॉर्म भर कर भेजे थे उनमें से ३१२ छात्रों को १३,२९२ रु० छात्रवृति के दिये गये। १९६२ में ५१९ छात्रों ने फॉर्म भर कर भेजे, इनमें से निरीक्षक, टोंक को १३३ छात्रों को ३,१३४ रु० छात्रवृति देने की स्वीकृति मिली इनमें से २२ छात्रों को छात्रवृति इसलिये नहीं दी जा सकी कि उनके सही पते उपलब्ध नहीं थे। सन् ६२ में पंचायत समितियों द्वारा जो छात्रवृत्ति दी गई है वह इसमें शामिल नहीं है।

(२) सन् ६१ में ३१२ छात्रों को छात्रवृत्ति मिली व १०२ फॉर्म खारिज किये गये, सन् ६२ में १११ छात्रों को छात्रवृत्ति मिली तथा २२ छात्रों को सही पता मालूम न होने के कारण नहीं दी जा सकी।

(३) १९६१ में फॉर्म भर कर भेजने की अन्तिम तिथि अगस्त ६१ थी। सन् ६२ में इस प्रकार के आदेश दे दिये गये थे कि यदि फॉर्म समय पर न मिलें तो फॉर्म हाथ से लिखकर या टाइप करके भी भेजे जा सकते हैं। आवेदन-फॉर्म भर कर शिक्षा विभाग में भेजने की अन्तिम तिथि ३१ अक्टूबर थी। शहरी क्षेत्र के आवेदन फॉर्म सीधे निरीक्षक व उपनिरीक्षक के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं। मिडल व उच्चशाला के फॉर्म सीधे उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग को भेजे जा सकते थे।

शिक्षा विभाग कार्यालय, अलवर द्वारा सामान की खरीद

१७. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 35

(श्री नत्थीसिंह)

(१) सन् १६६१-६२ के वर्ष में शिक्षा विभाग के अलवर स्थित कार्यालय में कितने रुपयों का सामान खरीदा गया ?

(२) क्या सामान की खरीद के टेन्डर मांगे गये थे ?

(२) किन किन दूकानदारों से टेन्डर प्राप्त हुए और उनसे क्या क्या सामान खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(१) सद् १६६१—६२ के वित्तीय वर्स में ७६,५१६.७१ रु० का सामान खरीदा गया ।

(२) जी हां ।

(३) जो सामान सन् १६६१—६२ में खरीदा गया उसकी सूची मय नाम फर्म व वस्तुओं सहित सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अधिक वितृस्त होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है ।)

प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फण्ड नियम

१८. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों तथा शिक्षकों के प्रोविडेण्ट फण्ड के जमा होने के संबंध में क्या नियम हैं ? कृपया नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) इन शिक्षण संस्था नियमों के अनुसार किस किस ने प्रोविडेण्ट फंड जमा नहीं करा रखा है ?

(ग) इन संस्थाओं को कितना कितना प्रोविडेण्ट फण्ड जमा कराना चाहिये था ?

(घ) जिन संस्थाओं ने नियमानुसार प्रोविडेण्ट फंड नहीं जमा कराया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(क) रिवाइज्ड ग्रान्ट—इन—एड रूल्स के नियम ४(जे) के अनुसार प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों तथा शिक्षकों के प्रोविडेण्ट फण्ड जमा होने के सम्बन्ध में नियम बनाने का प्रावधान रखा गया है । शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक ऐसे कोई नियम लागू नहीं किये गये हैं लेकिन प्रोविडेण्ट फण्ड के नियम बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

जिन संस्थाओं ने प्रोविडेण्ट फण्ड काटने की योजना लागू कर दी है उनको विभाग द्वारा उस रकम का सवा छः प्रतिशत तक का खर्चा मान्य मान कर अनुदान दिया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डूंगर कॉलेज में हॉल तथा छात्रावास

१६. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या सरकार को मालूम है कि डूंगर कॉलेज के नये भवन में कोई ऐसा बड़ा हाल नहीं है जिसको मीटिंग्ज़ आदि में इस्तेमाल किया जा सके ? अगर हां, तो इस अभाव की पूर्ति के लिये सरकार कब क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि बाहर के छात्रों के रहने के लिये छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है ? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

उत्तर

(१) हां। डूंगर कॉलेज बीकानेर के नये भवन में मीटिंग्ज़ करने के लिए एक बड़ा हाल नहीं है। वर्तमान संकटकालीन स्थिति के कारण निकट भविष्य में उक्त कॉलेज में एक बड़ा हाल निर्माण करने की कोई योजना नहीं है।

(२) यह कहना सही नहीं है कि कॉलेज के पास कोई छात्रावास नहीं हैं अपितु कॉलेज के पास २ छात्रावास हैं। एक नया छात्रावास अलग से बनाने की योजना है, आर्थिक स्थिति ठीक होने पर उस पर यथेस्ट निर्णय किया जा सकेगा।

(६. ०५ म. पू.)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(क) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन नई दिल्ली के संचलकों के प्रतिवेदन

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कंपनीज़ अधिनियम, १६५६ की धारा ६१६(क) के अंतर्गत नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू देहली के संचालकों के चतुर्थ एवं पंचम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं तत्सम्बन्धी लेखों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) कॉर्पोरेशन का चतुर्थ प्रतिवेदन एवं ३१ मार्च, १६६१ तक के लेखों का विवरण।

(२) कॉर्पोरेशन का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन तथा १ अप्रैल, ६१ से ३१ मार्च, ६२ तक के लेखों का विवरण।

(ख) रेवेन्यू लॉज़ कमीशन का प्रथम प्रतिवेदन।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेवेन्यू लॉज़ कमीशन के प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

(उपस्थापन)

श्री उपाध्यक्ष (राव श्री नारायणसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदनों की एक प्रति ही सदन की मेज पर रखी गई है या उनकी एक एक प्रति प्रत्येक माननीय सदस्य को दी जायगी। मेज पर रखने से तो ज्यादा से ज्यादा दो-तीन मेम्बर ही उनको देख सकेंगे, सारे माननीय सदस्य परिचित नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

हो सकेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इनकी एक एक प्रति सब को दी जाय।

श्री अध्यक्ष : सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है। यदि सबको एक एक प्रति नहीं दे सकें तो कम से कम एक एक प्रति विभिन्न ग्रुप्स या पार्टियों को दी जाय।

स्थगन-प्रस्तावों विषयक

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन की सूचना दी थी रावत भाटा के बारे में।

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना मिली थी, जिसके महत्वपूर्ण न होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया और उसके सम्बन्ध में राणा प्रतापसागर बांध के मजदूरों में संतोष न होने के कारण हड़ताल की है उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कल वक्तव्य देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक स्थगन-प्रस्ताव मैंने आज सुबह बीकानेर मेडिकल कॉलेज के बारे में दिया था।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि वह देरी से आया है और नियमानुसार नहीं है; फिर भी उसका जिक्र आप यहां कर रहे हैं।

(६.०८ म० पू०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

(अनेक सदस्य बोलने के लिये खड़े रहे)

श्री रामकिशन (वैर) : हमारी तरफ से कोई बोला नहीं है, इसलिये मुझे बोलने की अनुमति दी जाय। यदि किसी महिला को बोलने दिया तो मैं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ी हुई हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले दो-तीन वर्षों के राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों को यदि पढ़ा जाय ठीक से और ध्यान से उन पर सोचा जाय तो निस्संदेह इस वर्ष का उनका यह अभिभाषण पिछले भाषणों से कहीं संगतिपूर्ण और बेहतर है क्योंकि कई जगहों पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने प्रान्त की कई कमजोरियों तथा लक्ष्य की कमियों को स्पष्टतः स्वीकार किया है। वैसे जहां तक बिजली, सड़कें, शिक्षा और चिकित्सा का सवाल है हमें हमारी इस ओर की प्रगति पर संतोष है और मैं ऐसा समझती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो जो हमारे हाई स्कूलों और मिडल स्कूलों की संख्या है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक अखिल भारतीय स्तर तक पहुंच जायगी, यह बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही साथ यहां पर महिलाओं की भी विशेष सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में दी गई है, इस ओर हमारे बहुत कम माननीय सदस्यों का ध्यान गया है। मेरी समझ में सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के लिये पहले क्लास से लेकर एम. ए. और

Page No. 38

(श्रीमती सुमित्रा)

उससे भी ऊंची शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि राजस्थान में इस क्षेत्र में काफी संतोषजनक काम हुआ है।

सड़कों का जहां तक सवाल है, सड़कें बनी हैं, काफी अच्छी प्रगति हुई है। जहां कहीं पहले पहुंचने के साधन नहीं थे वहां पर अच्छा और काफी संतोषजनक काम हुआ है। लेकिन इस मामले में मैं राज्य सरकार को अपना एक सुझाव देना चाहती हूँ कि जितनी भी सड़कें इस राज्य में बनाई जायं मैं यह चाहती हूँ कि वे सब डामर रोड बनाई जायं, चाहे रोड कम ही बनें। हमने जितना टार्गेट रखा है उसमें कमी की जा सकती है, लेकिन जब तक रोड्स के ऊपर डामर नहीं डाली जाती है तब तक वे बारह महीने, छः महीने बाद बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। उनमें खड्डे पड़ जाते हैं। इसलिए जितनी सड़कें बनाई जायं, वे मुकम्मिल बनाई जायं, तो मेरी समझ में यह ज्यादा अच्छा होगा।

इसके साथ साथ इस दफा के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि राज्य में अकाल के पीछे अकाल पड़ने से यहां की आर्थिक स्थिति काफी कठिनाई में पड़ गई है; उस पर काबू पाने के लिए भी काफी सुविधायें जुटाई गई हैं। उन सुविधाओं का भी जिक्र किया है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूँ कि राजस्थान अन्न के उत्पादन के मामले में एक सरप्लस स्टेट है। यहां पर हर वर्ष ४८ लाख टन अनाज पैदा होता है जब कि राजस्थान राज्य का अन्न का कन्ज़म्पशन ३८ लाख टन है। इस बार कुछ अकाल की परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से हमारे यहां अन्न कम पैदा हुआ। लेकिन मेरी समझ में खरीफ की फसल के बाद अन्न के मामले में राजस्थान में इतना डेफिसिट नहीं हुआ था। जो मुख्य समस्या है वह समस्या यह है कि हमारे यहां से अन्न बाहर दूसरे प्रांतों को भेज दिया जाता है, दूसरी तरफ खरीफ की फसल ज्यादा ठीक से नहीं हो पाई थी और अकाल की परिस्थिति प्रान्त में उत्पन्न हो गई थी, उस वक्त सरकार इस तरफ ध्यान देती और सरकार जागरुक हो जाती और कोई कदम इस तरह का उठाती तो हमारे सामने आज यह समस्या नहीं होती। आज हमारे प्रान्त के अन्दर जो मंहगाई बढ़ती जा रही है, अन्न की कीमत पिछले वर्ष से दुगुनी नहीं तो कम से ड्योढ़ी तो हो गई है, इसके प्रति राज्य सरकार पहले से सचेत हो जाती और कोई इस तरह का कदम उठाती तो इस तरह की मंहगाई जो जन साधारण की कमर तोड़ रही है वह शायद नहीं हो पाती। लेकिन इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया और अब खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के बाद, रबी की फसल को पाला मार जाने के बाद अब सरकार कुछ सोचने का प्रयत्न कर रही है। यदि इस पर पहले सोच लिया जाता और इस दिशा में कोई कदम उठाया जाता तो शायद हमारे सामने यह मंहगाई की समस्या इस हद तक नहीं पहुंचती। इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि हमारे यहां अकाल की स्थिति के साथ साथ पेय जल की कमी की समस्या भी है। यह समस्या पेय जल की एक भारी समस्या

(श्रीमती सुमित्रा)

है। मैं समझती हूँ कि सत्रह साल के इस सुदीर्घ काल में जीवन की अन्यान्य आवश्यकता स्वच्छ पेय जल यदि हमारी सरकार जनता को मुहैया नहीं कर पाई तो यह जनता का दुर्भाग्य तो है ही लेकिन अपनी लोकतंत्रीय समाजवादी सरकार के लिए भी एक कलंक की बात है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने दूसरे राज्यों के प्रति हमारे राज्य को इस वर्ष सहायता पहुँचाने और अन्न पहुंचाने के लिए कृतज्ञता प्रगट की है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ राज्यपाल महोदय को एक गौरव भी महसूस करना चाहिए था और अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र करना चाहिए था कि इस वक्त तो विषम परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से हमें दूसरों से सहायता लेने के लिए उनके मुंह की तरफ देखना पड़ा, लेकिन हमें इस बात का गौरव और गर्व है कि राजस्थान प्रान्त ही वह प्रान्त है जो अन्न के भण्डार और चारे के मामले में एक सरप्लस स्टेट है और हर वर्ष फोडर और अन्न दूसरे प्रान्तों को भेजते हैं। इस बात का भी जिक्र वे साथ साथ कर देते तो बहुत अच्छा होता।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शक्कर की कमी का भी जिक्र किया है। मैं समझती हूँ कि राजस्थान की जनता का इतिहास पिछले समय का भी बहुत गौरवपूर्ण रहा है और वर्तमान में भी जब हिन्दुस्तान के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था तो यहां के लोगों ने गौरव की उस शानदार परम्परा को निभाया था। मैं मानती हूँ कि देश की बहबूदी के लिए और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए हमको शक्कर का निर्यात करना पड़ेगा और इस कारण शक्कर की कमी हो गई है तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान की जनता अपने देश की सुरक्षा के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। लेकिन आज जब गांवों में जाते हैं तो लोगों में असंतोष इस बात का है, वे कहते हैं कि हम बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हैं लेकिन शहरी और ग्रामीण जनता के साथ भेदभाव की नीति सरकार ने जो अपनाली है उससे गांव की जनता को इस बात का बड़ा दुःख है। मेरा ख्याल है कि शक्कर का समान वितरण शहरी और ग्रामीण जनता के बीच कर दिया जाय तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। लेकिन पता नहीं राज्य सरकार की क्या नीति है और यह नीति अपनाने के क्या कारण थे कि ग्रामीण परिवार को प्रति परिवार एक किलो चीनी दी जाती है और शहर में प्रति व्यक्ति एक किलो दी जाती है। मेरी राय में इस असमानता को मिटाने की आवश्यकता है, इस ओर शीघ्र ही कदम उठाया जाना चाहिए और जितना चीनी का कोटा राज्य सरकार को मिलता है उसका समान वितरण कर दिया जाय तो जो असंतोष जनता में फैला है वह कम हो सकता है। वैसे राजस्थान की जन-संख्या के आधार से राजस्थान में चीनी का कोटा कम मिलता है। मैं समझती हूँ, इसका उत्तरदायित्व हमारे खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों पर है क्योंकि जब हमारे ही समान बाकी के जन-संख्या वाले प्रान्तों को चीनी का कोटा हमारे कोटे से दुगुना मिलता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार पर हमारी सरकार क्यों नहीं दबाव डालती है कि हमको भी चीनी का और प्रान्तों के समान ही कोटा दिया जाय। अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार ने एक लोक-

(श्रीमती सुमित्रा)

मंत्री समाजवाद की बात कह कर इस बात की पुष्टि फिर से की है इसलिए जन-संख्या के आधार पर चीनी का कोटा फिक्स करने के लिए हमें भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए। इसके लिए यह भी कह सकते हैं कि यदि इस तरह आप जन-संख्या के आधार पर कोटा फिक्स नहीं करेंगे तो हम हमारे यहां से फोडर और अन्न दूसरे प्रान्तों में नहीं भेजेंगे।

(हिअर, हिअर)

इसके साथ ही साथ मैंने बिजली के बारे में कहा था कि बिजली की हमारे यहां प्रगति काफी संतोषजनक है और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष से काफी बढ़ा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेरह सौ गांवों में बिजली देने की योजना थी। उन गांवों में बिजली दी जा चुकी है। लेकिन इसमें किसानों के असंतोष का कारण एक है और वह यह है कि जब किसान सर्दी में ठिठुरते हुए और कांपते हुए और जेठ की दुपहरी में तपते हुए, लू से झुलसते हुए अन्न उत्पन्न कर न सिर्फ अपना पेट पालन करते हैं बल्कि सारे समाज का पेट भरने के लिए उत्पादन करते हैं, सारे समाज को अन्न मुहैया करते हैं ; ऐसी स्थिति में सरकार ने किसानों को बिजली दी है बारह नये पैसे प्रति यूनिट और जयपुर के नेशनल बॉल बेयरिंग फैक्ट्री को बिजली प्रति यूनिट दो या तीन नये पैसे के हिसाब से दी है। इस बात को जब किसान जानता है तो उसको बहुत अधिक दुःख और दर्द होता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह डेमोक्रेटिक सोशियलिज़्म है।

श्रीमती सुमित्रा : पता नहीं, आपकी निगाह में होगा।

तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऐसी विषम परिस्थितियों में आप जयपुर नेशनल बॉल बेयरिंग फैक्ट्री को तीन नये पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं, जब कि देश के अन्दर कुए से सिंचाई करके, खेती करके अन्न पैदा करने के लिए बिजली की दर आपने बारह नये पैसे प्रति यूनिट फिक्स की है। मैं माननीय विद्युत् मंत्री से निवेदन करूंगी कि जब वे जवाब दें तो इस चीज का स्पष्टीकरण करें। मैं चाहूँगी कि वे बतायें, इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, उद्योगों का जहां तक प्रश्न है उद्योगों ने राजस्थान में निस्संदेह तरक्की की है और इसका कारण हमारी राज्य सरकार का उद्योगपतियों को विशेष सुविधा देना है। इस उद्योग विकास से जहां हमारे राजस्थान की पर केपिटा इन्कम बढ़ी है वहां पर लोगों को रोजगार भी मिला है; यातायात के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर राज्यपाल महोदय ने निश्चय व्यक्त किया है, मैं चाहती हूँ कि परमात्मा सरकार को यह निश्चय पूरा करने में दृढ़ता प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, बे-रोजगारी का जहां तक प्रश्न है, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में १.८ लाख व्यक्ति बे-रोजगार थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में इस वक्त इस संख्या में ८.५ लाख की वृद्धि हुई है। इस दिशा में राज्य सरकार को निश्चित रूप से गम्भीरता से सोचना चाहिए और लोगों को नये रोजगार

Page No. 41

(श्रीमती सुमित्रा)

जुटाने के लिये निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए जिससे राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी से जो असंतोष व्याप्त हो रहा है वह किसी हद तक दूर किया जा सके और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये और प्रशासन में व्याप्त शिथिलता को रोकने के लिए सतर्कता आयोग गठित करने और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार सिर्फ इस प्रकार की सर्तकता आयोग नियुक्त करके और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करके इस भ्रष्टाचार पर कभी काबू नहीं पाएगी। हमारा प्रशासन बहुत शिथिल हो गया है और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने एक दृष्टान्त रखना चाहती हूँ। प्राचीन जमाने में नौशेरवा बादशाह के शासनकाल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था और शासन में शिथिलता आ गई थी। वह किसी भी तरह से रुक नहीं रहा था। इसके लिए उन्होंने डूंडी पिटवाई कि जो कोई भ्रष्टाचार और शासन में फैली हुई शिथिलता को समाप्त करेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जावेगा। दूसरे ही दिन एक आदमी आया और उसने कहा कि यह काम मैं करूंगा। दूसरे दिन बादशाह ने डूंडी पिटवा दी। उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा दिया और लोगों को कह दिया कि जो जो शिकायतें हों वे पर्चों में लिखकर सब उस गड्ढे में डाल दी जावें। दूसरे दिन गड्ढा भर गया। अगले रोज फिर उसने वही काम किया। लोगों ने अपनी शिकायतों की पर्चियां लिख लिखकर उस गड्ढे में डाल दी इसी तरह से चार रोज हो गये। बादशाह ने पूछा आपने कुछ नहीं किया, तो उसने कहा कि उसको एक दिन का और मौका दिया जावे; उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और लोगों से कहा कि अपनी अपनी शिकायतों की पर्चियें लिख कर गड्ढे में डाल दें। लोगों ने फिर अपनी अपनी शिकायतों की पर्चियें गड्ढे में डाल दीं। फिर वह बादशाह को अपने साथ लाया और उस गड्ढे से एक पर्ची निकलवाई, उस पर्ची में लिखा था बादशाह के शाहजादे ने एक १८ वर्षीय युवती के साथ बलातकार किया और बलातकार करने पर युवती ने आत्महत्या कर ली इस पर जब उसके बुड्ढे मां बाप शिकायत करने के लिये दरबार में पहुंचे तो दरबारियों ने और नौकरों ने उनको डांटा और डाट–डपट करके भगा दिया। बादशाह ने कहा कि इसके लिये क्या किया जावे। उसने कहा कि शाहजादे को फांसी की सजा दी जावे और फांसी के तख्ते पर लटका दिया जावे। दूसरे दिन सुबह शाहजादे को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। उसके बाद दूसरे रोज बादशाह ने उससे कहा कि दूसरी शिकायतों को भी निकाला जाए। उसने कहा कि अब उनको निकालने की जरूरत ही नहीं हैं। पर्चियों को बादशाह के अफसर रातों रात उठा ले गये और शिकायतों को रफा दफा भी रातों रात ही कर दिया।

तो माननीय अध्यक्ष, इस नजीर के द्वारा मैं सदन को यह बताना चाहती हूं कि यदि उसी तरह की हमारे चीफ मिनिस्टर में करने

(श्रीमती सुमित्रा)

की हिम्मत हो तो यह भ्रष्टाचार रुक सकता है। इस प्रकार के बहुत से दृष्टान्त हैं जहां इसी तरह के इतने बड़े बड़े अपराध किये हुए हैं, अगर माननीय चीफ मिनिस्टर की हिम्मत हो तो रातोरात शिकायतें रफा-दफा हो जावेंगी और प्रशासन में शिथिलता है वह भी दूर हो जावेगी। मगर मैं यह कहूंगी कि इसके लिये बड़े हौसले, हिम्मत और दिल पर काबू पाने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के शुरू में भी और अंत में भी प्रजातांत्रिक समाजवाद स्थापित करने के लक्ष्य के प्रति सजग हैं, ऐसा फरमाया है। बहुत अच्छी बात है और हम राजस्थान के सारे लोग इस बात के लिये गर्व से सिर उठाएंगे। लेकिन हमारा यह समाजवाद सफल यों नहीं हो पा रहा है कि इसमें कुछ घटिया किस्म के लोग जोड़-तोड़ करके ऊंची ऊंची कुर्सियों पर चले गये हैं और उन कुर्सियों पर चिपके रहने के लिये इस तरह के जोड़-तोड़ करते हैं कि उनकी कुर्सियें कायम रहें और वे कहीं कुर्सियों से हट न जावें। सरपंच ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जो सबसे अधिक बदमाश और चरित्रहीन हो, उस सरपंच को थानेदार से मिला देते हैं। थानेदार के साथ मिल कर वह लोगों पर झूठे केस बनाता है और अपने आदमियों से झूठी गवाही दिलवा देता है और इस तरह से गांवों में पार्टीबाजी चला करती है और उस अन्याय से लड़ने के लिये भले आदमियों को भी पार्टियां बनानी पड़ती हैं। इसलिये हमारा यह कर्त्तव्य है कि जो इस प्रकार के लोग अपनी कुर्सियों के बचाव के लिये नीचे से ऊपर तक हैं उनका समाज से बहिष्कार किया जावे और जब तक ऐसे लोगों का समाज और सरकार से बहिष्कार नहीं होगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहेगा।

अंत में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके लिये एक बार पुनः धन्यवाद देती हूं और आप भी सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में गंभीरता से सोचें और इस धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रति वर्ष हम सदन में चर्चा किया करते हैं। धन्यवाद का प्रस्ताव हम पारित करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जावे तो यह धन्यवाद कॉन्सटीट्यूशनल है। जो हमारे राज्यपाल महोदय अभिभाषण देते हैं उसमें जो उनके केबिनेट मिनिस्टरी की कार्यवाही जो वे करते हैं उस विषय पर विचार करते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि प्रति वर्ष राज्य सरकार जो भी कार्यवाही करती है उस पर विशेष रूप से इस सदन में चर्चा की जाती है और बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे राज्य सरकार के सामने रखे जाते है। लेकिन इन सारी बातों को उठायें उसका परिणाम क्या निकलता है। क्या केबिनेट मिनिस्टर उन बातों पर विचार करते हैं ? मैं तो यह कहूंगा कि बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिये बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न प्रस्तुत करते हैं प्रश्नों के द्वारा, उसका भी रवैया यह बना रखा है कि

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

उसका जवाब अन्धाधुंध देते हैं कम। से कम उन प्रश्न पर विचार किया जावे। हम देखते हैं, वे क्या उसका जवाब देते हैं। वे उसको पहले पढ़ने की कोशिश नहीं करते और जैसा उनके पास लिखा हुआ आता है उसको दे देते हैं। प्रश्न प्रस्तुत करने का महत्व यह होता है कि जो भी दिक्कतें हैं उन पर माननीय मंत्री महोदय विचार करें और उनका निराकरण करने की चेष्टा करें। होना तो यह चाहिये कि जब प्रश्न का उत्तर आए उस समय तक उस समस्या का समाधान हो जाना चाहिये। लेकिन यह बात उनके दिमाग में नहीं पहुंचती। इन सारी बातों पर विचार करने के बाद धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे और पास किया जावे, यह कहां तक उचित होगा, यह माननीय सदस्यों के विचारने का प्रश्न है।

हम यहां बैठते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता को जितनी कठिनाइयां होती हैं उनको सदन के सामने रखते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जनता में संतोष है या असंतोष है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर हमें विचार करना है। आज जनता के किसी तबके के आदमी को ले लीजिये, चाहे साधारण तबके के आदमी को ले लीजिये, चाहे मध्यम दर्जे के आदमी को ले लीजिये, किसी भी तबके के आदमी को ले लीजिये, सबमें असंतोष है और इस असंतोष का मूल कारण भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार के निवारण के लिये माननीय सदस्या ने बताया कि जो सत्तारूढ़ व्यक्ति हैं उनमें जब तक ऐसा मिनिस्टर नहीं आयेग,। जो अपने निकट से निकट सम्बन्धी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का सख्त से सख्त दण्ड दे तब तक हम भ्रष्टाचार का निवारण नहीं कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने शाहंशाह की एक नजीर दी। माननीया सदस्या ने इतना भी बता दिया होता कि शाहंशाह सुखाड़ियाजी के शाहजादे ने कौनसा ऐसा बलात्कार किया है जिसकी सजा देकर भ्रष्टाचार के निराकरण किये जाने की चेष्टा की जाती है।

मैं दो–तीन महत्वपूर्ण मुद्दे निवेदन करना चाहता हूँ। देखिये, आपने गत वर्ष में क्या प्रगति की! आप शिक्षा के मसले को ले लीजिये, डेवलपमेंट की प्रोब्लम को ले लीजिये, और जीवन के लिये जिन वस्तुओं की-खाद्यान्न आदि की आवश्यकता है उन आवश्यक वस्तुओं की समस्या को ले लीजिये। आप इन तीन चीजों को ले लीजिये; गत वर्ष में इनकी उन्नति हुई है या अवनति हुई है, इनका उत्थान हुआ है या पतन हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो विचारणीय है, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के सम्बन्ध में आपकी यह कौनसी नीति है कि भारत सरकार से नियन्त्रित होकर आपको काम करना पड़ता है। राजस्थान के अन्दर जो अच्छे से अच्छा अन्न उत्पन्न किया जाता है उसको बाहर भेजे देते हैं और राजस्थान को जनता को बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ घटिया से घटिया, सड़ा अनाज सप्लाई किया जाता है, जिसको वर्षों तक कोटरियों में विदेशों में रखा जाता है, वहां से जिस हालत में आता है वह अलग वहां से आने के बाद वर्षों तक यहां कोटरियों में बन्द रखा जाता है, उसे पशु तक खाना पसन्द नहीं करेंगे, पर राजस्थान के निवासियों के लिये यही अन्न है खाने के लिये। खाने की एक सबसे बड़ी और प्राथमिक आवश्यकता है, हर केबिनेट मिनिस्टर का यह आवश्यक कर्त्तव्य

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

हो जाता है कि वह खाने की इस समस्या का हल करे।

जयपुर की समस्या को ले लीजिये। अन्न की समस्या तो है ही, पर पीने का पानी बन्द हो जाता है। जयपुर शहर की चार–दीवारी के अन्दर की कुछ चौकड़ियों में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है कि वहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सुबह के वक्त भी इतना कम प्रेशर आता है कि ऊपर की मंजिल में पानी नहीं चढ़ता। ईद के त्यौहार के अवसर पर ईदगाह के पास हजारों मुसलमान नमाज पढ़ने के लिये इकट्ठे हुए, चौकड़ी रामचन्द्रजी और चौकड़ी विश्वेश्वरजी में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं, पानी बन्द कर दिया गया जिससे हजारों मुसलमानों को पीने को पानी नहीं मिला। पीने के पानी तक की व्यवस्था जिस राज्य में नहीं की जाय, पानी के लिये जनता को परेशान किया जाय पानी और हवा ये तो ईश्वर द्वारा दी हुई चीजें हैं, पर राजस्थान सरकार यहां यह करती है कि इसमें भी आजादी नहीं, वहां उस मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरी बहुत जरूरी बात है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि लॉ एण्ड ऑर्डर को मैन्टेन करने के लिये, न्याय की सुचारु व्यवस्था को चलाने के लिये १७ वर्ष के राज्य के बाद भी राजस्थान सरकार ने क्या सुविधायें दी हैं, जिनसे हम कह सकें कि हर व्यक्ति को सस्ता और जल्दी न्याय मिलता है, हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा का मौका है। मैं व्यक्ति विशेष के बारे में वकालत करनेर खड़ा नहीं हुआ हूं मैं यह बता देना, चाहता हूँ कि जितनी अदालतें हैं उनमें ऐसा देखने को मिला है, मैं अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं, डेढ़–डेढ़, दो–दो महीनों तक न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है, तारीखें पड़ती रहती हैं, फरीकेन आते हैं और चले जाते हैं, उनको व्यर्थ की परेशानियां और खर्चा उठाना पड़ता है, पर राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जाता कि जनता को न्याय मिलता रहे। जनता की इन परेशानियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

फिर डेवलपमेंट के प्रश्न आते हैं। उनकी जयपुर में यह व्यवस्था कर रखी है कि कलेक्टोरेट किसी एक कोने में है, तो सिविल कोर्ट्स किसी दूसरे कोने में, सैटलमेंट का ऑफिस तीसरे कोने में है तो डेवलपमेंट का किसी चौथे कोने में डाल रखा है। यदि आप वास्तव में जनता को सुविधा देना चाहते हैं तो एक को सांगानेर, दूसरे को आमेर और तीसरे को पुराने घाट में लगा दीजिए ताकि लोग आसानी से जा सकें। कलेक्टोरेट की बिल्डिंग के सामने, कोर्ट ऑफ जस्टिस की, कोर्ट्स ऑफ लॉ की डिग्निटी को मैन्टेन करने के लिए कई सुझाव राजस्थान सरकार के सामने दिए गये, पर उन पर सोचने तक का कष्ट नहीं करते। यदि सरकार चाहे तो ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे लोगों को सुगमता से न्याय मिल सके, पर सरकार ऐसा चाहती ही नहीं है। किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में ५ थाने हैं किसी की अदालत में ८ थाने हैं और किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में ३० थाने हैं। यदि कोई

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

मजिस्ट्रेट सुबह ८ बजे जाकर रात को १० बजे तक भी बैठा रहे तो वह मुकदमों के फैसले नहीं दे सकता, इतने मुकदमे आते हैं। मैंने यह शिकायत आपके सामने रखी, पर आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। इन्हीं कारणों से जनता में असंतोष फैलता है क्योंकि "Justice delayed is justice denied" बल्कि यह कहा जा सकता है कि, "Justice is delayed, justice is corrupt."

तो इस करप्शन को फैलाने का उत्तरदायित्व केबिनेट पर, इन मिनिस्टर्स पर डाला जा सकता है। या तो इनएफिशियेन्सी कहिए या पोलिटिकल रीज़न्स हो सकते हैं जिनके कारण शिकायतें आती हैं, वे जानते हैं पर उन शिकायतों के निराकरण की चेष्टा तक नहीं करना चाहते। डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली उनका हाथ इसमें माना जाना चाहिए। यह उनकी एक आदत सी पड़ गई है, जब तक ये अपनी इस आदत को नहीं सुधारते तब तक किसी भी हालत में धन्यवाद के पात्र नहीं हो सकते।

एक छोटी सी समस्या है, अब मैं उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। राजामल तालाब की स्कीम बनाई गई जिसमें सैकड़ों प्लॉट अलॉट किये गये। सौ, डेढ़ सौ प्लॉटस बन गये और सौ, डेढ़ सौ बनने वाले हैं; उनमें मकान बनाने के लिए लोन्स दिये जाते हैं, दो-तीन सौ सोसाइटीज़ ऐसी बनी हुई हैं जिनकी ओर से एप्लीकेशन्स दी जाती हैं, उनको लोन्स दिये जाते हैं, पर म्यूनिसिपल कर्मचारियों को जिनको कि म्युनिसिपैलिटी से पट्टे मिल चुके हैं, उनको लोन दिए जाने का सवाल आता है तो इन्कार कर दिया जाता है, उन्हें लोन्स नहीं दिये जाते। राजस्थान सरकार की ओर से डिसीज़न लिया गया है कि कुछ व्यक्तियों को लोन दिए जाते हैं, लेकिन नगरपालिका के कर्मचारियों की ओर से इतनी एप्लीकेशन्स दिये जाने पर भी लोन नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि पी० डब्लू० डी० की तरफ से यह सरकार को कहा गया है कि इनको लोन नहीं दिए जायं। क्या वजह है कि इनको लोन नहीं दिये जाते? एक को लोन दिया जाता है और दूसरे को नहीं दिया जाता, यह कौनसा न्याय है? सरकार की इस नीति के कारण यह सारा रुपया लैप्स हो जायगा और इससे इन लोगों की बर्बादी होगी। इससे सैकड़ों व्यक्ति प्रभावित होने वाले हैं। इसका परिणाम यह होगा कि यह रुपया राज्य सरकार का बेकार चला जायगा। राज्य सरकार किसी की मदद नहीं कर सकती। नतीजा यह होगा कि असंतोष की लहर फैलेगी।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कि एक तबके के विषय में वेतनवृद्धि के लिए आश्वासन दे दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि वेतनवृद्धि की जो कार्यवाही की गई है क्या इससे बढ़ती हुई मंहगाई का सामना किया जा सकेगा? आपके सामने आंकड़े बहुत प्रस्तुत किये जाते हैं और किए जा चुके हैं। इन्हीं दो-तीन महीनों के समय में मंहगाई किस स्टेज से किस स्टेज तक बढ़ गई है? आप विचार कर चलिए :

"बुभुक्षितः किम् न करोति पापम्
क्षीणजनाः निष्करूणा भवन्ति।"

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

इस कहावत के अनुसार भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता ? ७५ रु० की तनख्वाह पाने वाला अहलकार जिसके घर के अन्दर ३-४ बच्चे हों, जिसके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हों, स्कूल को फीस देते हों; फीस तो देनी पड़ती है, पोशाक भी पहननी पड़ती है, उनके लिए जूते भी लेने पड़ते हैं, इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा कैरीक्यूलर एक्टिविटीज़ के अन्दर हमारी राज्य सरकार विशेष ध्यान देती है, उनके लिए भी खर्च करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई में, मकानों के किराए आदि ऐसी समस्याएं हैं और उन सब पर फिर अनाज जो बाजार में बहुत मंहगा मिलता है और फिर हम उम्मीद करते हैं कि ६ बजे से लेकर ५।। बजे तक एक अहलकार जिसकी तनख्वाह १२५ या १५० रु० हो, वह अल्मोस्ट एफीशियेन्सी के साथ काम करे, अपने अफसरों की घुड़कियों को बर्दास्त करे, मंत्रियों की पॉलिसियों को निभाने की चेष्टा करे ! फिर उनकी तरक्की के लिए आप पांच रुपये, सात रुपये या १० रुपये महीना भी बढ़ाने की कोशिश न करें, तो यह आपके सोचने का विषय है । ठीक बात है कि राज्य सरकार को इसके लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ती है और यदि पांच रुपये एक व्यक्ति के बढ़ाये जाते हैं तो हो सकता है कि सरकार को लाखों रुपये खर्च करने पड़ें । यह खर्च आप कहां से पूरा करें, यह आपके सोचने का विषय है। इस पर थोड़ा सा दिमाग को जोर देने की आवश्यकता है । प्लान्स भी करते हैं, डेवलपमेंट्स भी करते हैं और उन डेवलपमेंट्स से राज्य सरकार के उत्पादन में भी वृद्धि होती है, यह निश्चित बात है । लेकिन इनमें काफी अपव्यय होता है। यदि इस प्रकार के अपव्यय को रोका जाय, जो राष्ट्र का रुपया नष्ट किया जाता है, इस पर थोड़ा सा इन्तजाम आपकी ओर से किया जा सके तो वास्तव में विकास में वृद्धि आ जाएगी । लेकिन जहां आपके १० करोड़ रुपये खर्च होते हैं उससे आउटपुट आपको क्या मिलता है ? अगर उसका सूद भी लगाया जाय तो मुमकिन है कि सूद जितना भी रुपया प्राप्त नहीं हो सकता है।

हर साल आंकड़ों के सब्ज़ बाग देख कर ऐसा लगता है कि हमारा राष्ट्र उन्नति कर रहा है, राजस्थान प्रगति की ओर जा रहा है । ये सारी बातें तो आप बताने में होशियार हैं । आंकड़ों पर आपका काबू मालूम पड़ता है, उनके अन्दर प्रगति दिखा कर दुनिया की आंखों पर पर्दा डालना चाहते हैं। उस असत्यता को बंद करना चासते हैं, जब कभी भी राज्यपाल महोदय की स्पीचेज आई उनमें आंकड़ों की प्रगति बराबर पाते आ रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ गया, इन्डस्ट्रीज बढ़ गईं, चोरियां कम हो गई, डकैतियां कम हो गईं, दुनियां भर के काम कर डाले । लेकिन मेरी समझ में अभाव ज्यों का त्यों बना रहता है । थोड़ी देर के लिए माना जाय कि १७ साल के समय में जितने भी इस तरह के काम किए उसमें जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि इस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं होता जा रहा है, लेकिन जरा विचार करिए । जैसे एक माननीय सदस्य ने अभी आपको बताया कि आजादी के बाद पैदा होने वाली इन्सानों की समस्याएं अब आपके सामने आएंगी । इस वक्त तो समस्याएं उन इन्सानों की है जो आजादी से पहले पैदा हुए ।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

शिक्षा में आपने बहुत उन्नति की बात कही है, आंकड़ों के आधार पर आप कहते हैं। लेकिन देखिए मोरल स्टैन्डर्ड्स जो इन छात्रों के बढ़ने चाहिए थे वे बढ़े हैं या घटे हैं, यह भी एक सवाल है ? ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्ति इस बात की शिकायत करते हैं कि इन्टरव्यू में हमारे पास इण्टर-मीजिएटस आते हैं, ग्रेजुएट्स आते हैं लेकिन उनको अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता, हिन्दी का मजमून लिखते हैं तो अशुद्धियां करते हैं। ये सब बातें आप जानते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि स्तर को इस तरह बदलें कि इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने न आ सके ?

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

इस प्रकार की एक कोन्क्रीट इन्स्टंास नहीं, सैकड़ों दी जा सकती हैं।

इन सब बातों के होते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर है। शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं, उप-शिक्षा मंत्री भी हैं। १७ वर्षों में जितनी प्रणालियां चली हैं उनसे नैतिक स्तर में गिरावट आई हैं।

मैं कांग्रेस की तारीफ करता हूं कि आजादी से पहले जो इसमें ब्रेन्स थे आपके गोपालकृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय जैसे भी व्यक्ति थे। इन १७ सालों के अन्दर कोई ऐसा ब्रेन नहीं निकला है। आपने एक्स्ट्रा कैरीक्यूलर एक्टिविटीज़ इतनी लगा दीं कि जो वास्तविक बात होनी चाहिए थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप सड़कें बना सकते है, भवन बना सकते हैं। प्लाटो के शब्दों में:

"Nations are made not from rocks and trees but from moral standards of its citizens."

आप बहुत बड़े बड़े रोक्स और ट्रीज़ को इकट्ठा करने की बात, फर्नीचर सजाने की बात, बहुत भवन बनाने की बात, इन सब आंकड़ों को लेकर नहीं कह सकते कि आपने राष्ट्र का उत्थान किया है। इसके लिए व्यक्तियों के चरित्र-निर्माण की आव-श्यकता होती है और जब तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी आप उनको आंकड़ों के सब्ज़ बाग दिखाकर संतुष्ट नहीं कर सकेंगे।

एक सबसे बड़ी बात यह है कि....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मसला ऐसा है जिसको लाने के बाद उपभोक्ता भण्डारों का सवाल एक महत्वपूर्ण बात है। सप्लाई के लिए खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं के लिए राज्य सरकार ने नियंत्रण कर रखा है और बड़े ही सस्ते रूप में वह सामान सप्लाई के लिए मिलता है। लेकिन उस सप्लाई का तरीका क्या है ? अब यह भ्रष्टाचार कहां से उत्पन्न होता है और वह भी जीवन की आवश्यकताओं का ! आपने जो बड़े बड़े भण्डार बना रखे हैं उनके नाम पर कोटा अलॉट किया जाता है। वह कोटा भंडारों के पास जाता है और जब रेकॉर्ड चैक करते हैं तो जनता के ६०, ७०, ८० जितने भी भंडार हैं उन सबको अलॉट कर दिया जाता है लेकिन यह सारी कागजी कार्यवाही होती है।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

अभी गुड़ की प्रोब्लम यहां चली। शहर में यह समझ कर गुड़ की सप्लाई बन्द कर दो कि शहर वालों को गुड़ की आवश्यकता नहीं है। गांवों में जहां तक गुड़ की सप्लाई का सवाल है तो अभी मुझे गांवों में घूमने का अवसर मिला। मैंने कोऑपरेटिव स्टोर्स वालों से बात की! मुझे यह मालूम हुआ कि वहां कोटा अलॉट ही नहीं किया गया है। कोटा ऊपर का ऊपर हवा में ही चला गया। कहां चला गया? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जानते हुए भी इसका निराकरण नहीं कर सकते। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या सरकार यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि जहां तक सप्लाई और कोटे का सवाल है यह मिनिष्टर-इन-चार्ज और सेक्रेटरी के हाथ में न रह कर हाई पर्सोनल की एक कमेटी के पास रख दे जो कि रिक्वायरमेंट के अनुसार कोटा अलॉट कर दें! अगर राज्य सरकार यह व्यवस्था कर सकती है तो मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि सप्लाइज़ को लेकर जो लोगों करप्शन फैला हुआ है उसको बन्द किया जा सकता है। लेकिन मुझे विश्वास है और मैं यह जानता हूँ कि राज्य सरकार शायद ही यह तरीका काम में लेगी। अगर यह काम लेगी तो बड़े बड़े खतरों में अपने आपको डाल देगी। इसमें हाई पर्सोनेलिटीज़ इन्वोल्व्ड हैं। अगर उनके ऊपर प्रबन्ध लगा दे तो निश्चित है कि सरकार की आज जो पॉवर है, आज सरकार जो पॉवर में है वह कल बदल जाय। उनकी स्थिति बदल जाय।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनिट में ही समाप्त करना चाहूँगा।

जब तक आप उनको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे समस्या का निवारण नहीं कर सकते।

एक बात और बताना चाहूँगा :

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए प्रस्तुत होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के पिछले भाषण के बाद आज इस दूसरे भाषण के समय काफी पानी दरियाओं के पुलों के नीचे से गुजर चुका है। इस ओर के लोग भुवनेश्वर और गोपबन्धुनगर की स्वच्छ गंगा में स्नान करके आये हैं हुकुमरान इधर के। उधर के बहादुर साथी भी महुआ का चुनाव जीत कर आये हैं। सबसे पहले राज्यपाल के भाषण में इस ओर इंगित किया गया है कि हमने अपनी योजनाओं में बड़ी कठोरता के साथ इस बात का ध्यान रखा है कि आमदनियों की दरिया कम हो और जो धन है और क्रेडिटिंग पॉवर है वह कुछ आदमियों के हाथों में केन्द्रित होने से रोकी जाय।

अध्यक्ष महोदय, देश में घटनायें हुई हैं और कुछ आंकड़े मुख्य रूप से उभर कर भारतवर्ष में आये हैं और काफी आंकड़ों में कन्ट्रोवर्सीज़ पैदा हुई हैं। इसी समय राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग उठायी और इससे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पहले राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस ने राजाओं प्रिवीपर्सेज़ को जब्त करने के लिए कहा। यह बात स्पष्ट हो गई है कि देश की सारी पूंजी २०–२२ लोगों के पास केन्द्रित होकर रह गई है और देश की जनता केवल सात आने रोज पर जिन्दा रह रही है। भुवनेश्वर में इन सारी परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी जिस गंगा-जल से स्नान कर आये हैं और समाजवाद की जो पूंजी लेकर आप आये है वह आश्चर्यजनक है। राजस्थान की कांग्रेस के हुक्मरान ने स्टेट को एक प्रोग्रेसिव स्टेट बना लिया है, इसका उदाहरण है महुआ का इलेक्शन। वहां की जनता ने एक शीशा दिखाया है जिसके अन्दर आप अपना मुंह देख सकें।

अध्यक्ष महोदय, महुआ के अन्दर जो चुनाव हुए वे याद दिलाते हैं आदिकालीन लड़ाइयों की, उस समय तलवार से तलवार की टक्कर थी, यहां पर दौलत से दौलत की टक्कर हुई। हर प्रकार से साधनों का दुरुपयोग हुआ इधर से या उधर से। मैंने सुना है, स्वतन्त्र पार्टी के दल के नेता ने और मुख्य सचेतक ने यह कहा था कि सरकार की की ओर से दो सौ ट्रकों का महुआ के इलेक्शन में प्रयोग हुआ है, खांड की सप्लाई हुई और स्कूलों का दान हुआ है। दोनों ओर से साधनों का दुरुपयोग हुआ। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि महुआ में दोनों ओर की शक्ति का पूरा प्रदर्शन हुआ; चाहे इधर से हुआ हो या उधर से हुआ हो। मेरे दल के नेता के द्वारा व्यक्त किये गये कुछ शब्दों और पार्टी के द्वारा रखे गये तथ्यों की याद दिलाता हूँ। इस पार्टी को सामने लाकर खड़ा कर दिया है और आज वक्त आ गया है, वक्त की आवाज नहीं सुनते, उस चीज को नहीं पहिचानते और विश्वास को नहीं पकड़ते कि आपने जनता के साथ कुछ वायदे किये हैं, मजदूरों के साथ आपने कुछ वायदे किये हैं, अपने देश के प्रिविलेज्ड लोगों के साथ कुछ वायदे किये हैं, लेकिन जब आप लैन्ड एक्वीज़ीशन बिल में सुधार करते हैं और मनीलैन्डर्स बिल में मनीलैण्डर्स को एक प्रिविलेज्ड क्लास बना देते हैं तो आप किसान और मजदूरों और साधारण जनता के साथ किये गये वायदों को आप भूल जाते हैं और चन्द लोगों के साथ किये गये वायदों को आप याद रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का भाषण उस समय हुआ जब राजस्थान में अकाल की काली घटायें छाई हुई हैं और इस भाषण में भी इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। दूसरी वर्षा के बाद हमारी एन्युअल इन्क्रीज़, ६२–६३ और ६४ की रेट के अनुसार कूतें तो एन्युअल इन्कम की इन्क्रीज़ ६.९७ परसेन्ट होती है और ५४ की कीमतों के आधार पर २.७७ पोइन्ट होती है और पर आइटम परसेन्टेज के इन्क्रीज़ में २. करेन्ट रेट पर आंके तो स्पष्ट रूप से मंहगाई की ओर इंकित करते हैं ये आंकड़े। हरएक आंकड़े की चालबाजी में हुक्मरान ने जनता को भरमाने की कोशिश की है। आंकड़ों से और जो वास्तविक स्थिति है जिसमें सारा राजस्थान झुका पड़ा है, स्पष्ट सामने आ गयी है। ३२) मन गेहूँ, २०) मन बाजरा और २०) मन मक्का की कीमत आज आ गयी है। २) सेर गुड़ बाजार में मिल रहा है। सर्विसेज़ के लोग, काम करने वाले मजदूर, सफेद पोश इन्सान के लिए, मजदूरों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के लिए यह एक दुर्लक्ष्यपूर्ण है, जो एक दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति में पहुँच चुके हैं और जिनकी जिन्दगी एक भयानक स्थिति में पहुंच चुकी है और ऐसी स्थिति में जब कि देश पर अकाल की काली घटायें छायी हुई हैं। ये आंकड़े स्पष्ट इंगित करते हैं। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात की जाती है तो हुक्मरान की पॉलिसी इस रूप में झुकती है कि इरिगेशन के द्वारा, बैटर टेक्निकल एडवाइस के द्वारा और फर्टीलाइज़र के द्वारा उपज हमारी बढ़ रही है।

भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की जो पॉलिसी रही है उसको पहिचानने की कोशिश नहीं की। वह भीलवाड़ा हो, बिलाड़ा हो या गंगानगर हो, सरकार की नीति धरती को नीलाम करने की है। आज भी हुक्मरान के राज्य में आधी बटायी ली जाती है। आदिवासियों को ले लीजिये। उनके तीस-तीस साल, चालीस-चालीस साल के कब्जे छुड़ाये जा रहे हैं। सीलिंग लागू की। आपने हर प्रकार की रियायत दी, बागात की छूट दी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए छूट दी, मैकेनाइज़्ड फार्म्स के लिए छूट दी। जागीरदार और बड़े बड़े भू-पतियों और पूंजी-पतियों को आश्वासन दिये, बड़े बड़े डिप्लो-मेटिक तर्कों से बहलाने की कोशिश की। सीलिंग को बाई ग्रेड किया जा रहा है। पहले पांच सौ एकड़ वाले को छोड़ेंगे, फिर सौ एकड़ वाले और उसके बाद ५.० एकड़ वाले को छोड़ेंगे और फिर ३० एकड़ वाले आवेंगे और तब तक यह धरती कहां रहेगी, मैं यह पूछना चाहता हूँ ? हर प्रकार का मौका दिया है गत दस वर्षों में। भू-पतियों को, भू-स्वामियों को हर प्रकार से मौका दिया है, उनको रियायतें दी हैं, राजा–महाराजाओं को रियायतें दी हैं, प्रिवी पर्सेज़ दिये हैं। तीस-तीस लाख के बिजली के बिलों को माफ किया है। बड़े बड़े भू-पतियों को कहा है, बालकों को कहा है कि जमीन इधर-उधर कर लो, ठिकाने लगा दो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : It is absolutely wrong.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राज्यपाल महोदय के भाषण में यह दिया जा रहा है कि ५०० पर लागू किया जाय। १५० पर करेंगे। क्या दिक्कत है ३० पर लागू करने में ? क्यों नहीं फौरन डिक्लेरेशन कर दिया जाय ?

(१०.०० म० प०)

अध्यक्ष महोदय, बहुत मजाक हुआ लोगों के साथ। लोगों को कहा गया कि आप दरख्वास्तें दीजिये। बन्द लिफाफों के अन्दर दरख्वास्तें दी गईं। इस तरह गंगानगर में करीब एक लाख दरख्वास्तें आ चुकी हैं। उन लिफाफों को खोला गया, बेढंगे तौर पर खोला गया, दरख्वास्तें ले ली गईं, दो दो रुपया प्रति दरख्वास्त के हिसाब से बहुत बड़ी राशि एक-त्रित हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जब कभी आमदनी बढ़ाने का प्रश्न आता है इस सरकार की नीति है किसानों की उपज बढ़ाने के लिये वे नीतियां बहुत घातक नीतियां हैं। जगह जगह धरती का नीलाम किया गया। सरकार की कोशिश यही है कि किसी प्रकार भी गरीबों को धरती प्राप्त न हो जाय। चाहे बिलाड़ा तहसील हो, भीलवाड़ा हो अगर कोई किसान बगैर सेटल-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मेंट हुई धरती पर कोई हल चला लेता है तो उस पर पन्द्रह गुना तावान कायम किया जाता है। डूंगरपुर के आसपुर क्षेत्र में अगर कोई आदिवासी जिसका अलोटमेंट न हो उस धरती पर खेती कर ले तो पन्द्रह गुना तावान वसूल किया जाता है। गंगानगर के इलाके में जहां १८ लाख बीघा जमीन बेकार पड़ी है, जहां धरती को जोतने वाले नदारद हैं वहां यदि कोई धरती जोत ले तो उस पर भी पन्द्रह गुना तावान, किसी खाली धरती पर किसी किसान ने हल चला दिया तो पन्द्रह गुना तावान ! इसी प्रकार से सेटलमेंट द्वारा रिजेक्ट हुई धरती पर कोई हल चला दें तो उस पर भी पन्द्रह गुना तावान।

इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि धरती अलोटमेंट के जो कानून बनाये गये हैं उनको अलोटमेंट कानून न कह कर कन्सीलियेशन का कानून कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। गंगानगर इलाके में धरती अलोटमेंट का कानून लागू है, उसका नाम लैन्ड अलोटमेंट न होकर लैन्ड कन्सीलियेशन एक्ट होना चाहिये। वहां के अलोटमेंट के लिये सन् ५६ के अन्दर तीस हजार दरख्वास्तें प्राप्त हुईं। उनमें से पच्चीस हजार दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी गईं और उनमें से पांच हजार दरख्वास्तों को ही अधिकारी माना। राजस्थान केनाल में जो बंजर भूमि है उसको यदि कोई तोड़ता है तो उसको नोटिस दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष बैठे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय की याद आ रही है, इसलिये उपाध्यक्ष महोदय निकल जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यह धरती के अलोटमेंट की रूपरेखा है। आज सारे राजस्थान में तीस हजार मील का क्षेत्र अकाल ग्रसित क्षेत्र है जिसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन जो आंकड़े इसमें बताये गये हैं कि इससे केवल २६ लाख लोग ही ग्रसित हैं, मैं इस बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान की आबादी २ करोड़ से ऊपर है; उसके अन्दर २६ लाख लोग ही नहीं आज राजस्थान की एक तिहाई आबादी अकाल से ग्रसित है। ७० लाख पशुओं पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ सरकार ने डिपोज़ खोले हैं, २१२ बताये गये हैं; उसमें से केवल ८० डिपोज़ कायम कर सके हैं और जितनी राशि दी गई है वह सारी यदि बांट ली जाय जिसके बारे में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं, मैं इस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा।

एक चीज और है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा, इसमें ५७ हजार पशु बताये गये हैं जिनकी निकासी हुई है। इस बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार की जो इसमें नीति रही है या सरकारी कर्मचारियों की नीति रही है, ५७ हजार से कई गुना पशुओं का एक्सोडस हुआ है। जिस प्रकार की शिथिलता राहत देने के अन्दर बरती गई है राजस्थान की बहुत कीमती राठी ब्रीड को एक प्रकार से समाप्त कर दिया है। पिछले सैशन में भी मैंने कहा था कि पांच हजार पशु अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तहसील के अन्दर मारे गये, वे सब राठी ब्रीड के पशु थे। अध्यक्ष महोदय, इस बात

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पर जवाब देते हुये हमारे मंत्री महोदय ने यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर एक भी पशु नहीं मरा। जिला परिषद गंगानगर ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव भेजा जिसमें उसने कहा कि ३० हजार पशु केवल राठी ब्रीड हमारे इस इलाके में मारे गये। एक्सोडस का जो अन्दाजा लगाया गया है गंगानगर जिले का, उसमें से केवल २० से ३० हजार तो राठी ब्रीड का एक्सोडस हो चुका है; गांव कूपला में १२ हजार भेड़ें मारी गईं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : भेड़ों के कोई बीमारी हो गई थी क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय....

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं जब कभी बोला हूँ उपाध्यक्ष महोदय की हाजरी में बोला हूँ आज ही मुझे आपकी उपस्थिति में बोलने का अवसर मिला है।

श्री मानसिंह महार : चीन से कोई पुड़िया ले आये दिखते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आप से अर्ज कर रहा था, पशुओं का एक्सोड्स हो रहा है, वह पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। गंगानगर जिले के अन्दर एक प्रकासेत्वरिपाटी है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): थोड़ी मैं आपसे जानकारी कर लूं। आपने जो कहा कि एक ही गांव में १२ हजार भेड़ें मर गईं, वह कौन सा गांव है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कूपली ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १२ हजार भेड़ें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १२ हजार भेड़ें तो सारे डिस्ट्रिक्ट में, इस गांव १२ सौ भेड़ें मरी हैं।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : जिला परिषद गंगानगर ने किस तारीख को सर्व सम्मति से प्रस्ताव भेजा है, तो बता दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो जिला परिषद की मीटिंग में रहते नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मीटिंग में हाजिर थे या नहीं, यह बात नहीं; आप तो यह बता दीजिये किस तारीख को सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पास करके भेजा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप भी इस प्रस्ताव को जानते हैं और मुख्य मंत्री भी जानते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं नहीं जानता। जिला परिषद् के सदस्यों को जिले की सब जानकारी होती है और मैं समझता हूँ वह आपको है। जब मैं गंगानगर गया था जिला परिषद के सदस्य भी मुझसे मिले थे और उसमें आप भी साथ थे। उस समय अकाल के बारे में बातचीत की थी। उस समय आपने कोई बात इस तरह की नहीं की थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको ५० पेज का मेमोरेन्डम दिया है। आप काम में बहुत बिज़ी हैं इसलिये आपको वह पढ़ने का अवकाश नहीं मिला होगा, उसमें सब है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एक माननीय सदस्य : उन पचास पेजों में सारा फेमिन कोड होगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब भी आपके लिये ५५० पेज का मेमोरेन्डम मौजूद है। केबिनेट के वहां आने का था १६ तारीख को, लेकिन केबिनेट नहीं आई। वहां हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे, लेकिन आप तो महुआ में डेरा डाले हुए थे ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय मुख्य मंत्री, जो केबिनेट के सदर हैं वे उपस्थित थे। केबिनेट के आने की क्या आवश्यकता थी ? आपने मुख्य मंत्री के सामने पचास पेज का मेमोरेन्डम दिया और केबिनेट के आने पर आपने ५४० पेज का मेमोरेन्डम तैयार किया और अगर सारा हाउस आता तो न मालूम कितने हजार पेज का मेमोरेण्डम आप तैयार करते !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कलेक्टर गंगा नगर तरफ से, सारी म्युनिसिपैलिटीज़ की तरफ से वह पेश किया जाने वाला था; किन्तु १६ तारीख को तो आपकी जीप का चक्का महुआ में पंक्चर होगया था, वहां पर आप कैसे पहुँच सकते थे ?

अध्यक्ष महोदय, अकाल की इस दुर्लक्ष्य-पूर्ण स्थिति के अन्दर कलेक्टर गंगानगर ने सरकार से अपील की है कि इस राठी नस्ल को बचाने के लिए, राठी नस्ल की गायों को बचाने के लिए इनका फिरोजपुर के इलाके में एक्सोडस करने का इन्तजाम किया जाय यह नस्ल बच सकती है। आज इनके लिए उस इलाके में फोडर के डिपो नहीं हैं। आठ फोडर डिपोज़ खोलने की बात थी यह बात पिछले महीने से कलेक्टर गंगानगर फेमिन रिलीफ कमेटी के अन्दर कह रहे थे; चार महीने से कह रहे थे, किन्तु अभी तक वे दुकानें नहीं खोली गईं।

चार महीने से फोडर डिपोज़ का प्रोग्राम बना लिया। दूसरे प्रोग्राम बना लिये। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से एक कानी कोड़ी भी हमारे पास नहीं आई। इसके लिये एस.डी.एम. भादरा को स्पेश्यली जयपुर इसके लिये भेजा। इस पर केवल १४ हजार पहुँचे। यह तो वह काल है जो प्रकृति की देन है।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) **:** गंगानगर जिले में........

(अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपको भी जानता हूँ। शोपुरा, करनपुरा के भी किस्से मुझे आपके मालूम हैं। आपकी जीप पाकिस्तान जाती है, मैं जानता हूँ।

श्री मनफूलसिंह : आपकी जाती है जीप तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने क्या क्या गबन-घोटाले किये हैं, मैं अभी बताऊंगा। सारे किस्से आपके जानता हूँ। आप सब्र करें। मैं अभी उन पर भी आऊंगा।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक अकाल तो था प्रकृति की तरफ से उसके कारण पड़ा वह। पर एक अकाल राजस्थान और

Page No. 54

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पंजाब की सरकारों ने डाला। आप पूछेंगे अध्यक्ष महोदय, कि यह कैसे ? तो मैं बताता हूँ।

राजस्थान ग्रेनरी के रूप में मशहूर है, गंगानगर इलाके की बदौलत सारे भारत भर में। यह एक बड़ी धान मण्डी है। इसमें धान के गेहूँ के लहलहाते खेत हैं, सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं यहां हैं। गंगनहर और भाखरा का यह इलाका है। ३६ लाख एकड़ धरती सिंचित करने की बात है जिसमें जहां से सारे राजस्थान को अन्न प्राप्त होता है। पर आज इस इलाके की जो दुर्लदयपूर्ण स्थिति हो गई है वह सब राजस्थान सरकार की कमजोरी के कारण और पंजाब सरकार की धक्काशाही के कारण हुई है। यह भयानक स्थिति है। यह अकाल सरकार ने पैदा किया है। आज गंगानगर की नहरों से पानी गायब हो चुका है, खेत सूख गये हैं। भाखरा की नहर का अपने अधिकार का पानी प्राप्त नहीं हुआ। गंगानगर में २५ पर्सेन्ट से ज्यादा सिंचाई नहीं हुई।

मैंने नन्दाजी का आश्वासन और प्लानिंग कमीशन के आश्वासन अखबारों में पढ़े हैं आपने भी पढ़े होंगे ; जिनमें इस बात की स्पष्ट घोषणा है कि बोर्डर क्षेत्र के साथ विशेष रियायत की जावेगी। इस पर लगातार मैंने गृह मन्त्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाया है कि बोर्डर क्षेत्र की स्थिति राजस्थान में बड़ी दुर्लदयपूर्ण है।

गंगानगर में जो टेलें स्थित हैं उनमें एक बूंद पानी नहीं पहुंच सका और अगर कहीं पहुँचा भी है तो एक दो सिंचाई से अधिक नहीं हो सकी है। आप अन्दाज लगाइये ; एक ओर पाकिस्तान के लहलहाते खेत हैं, फसलें हैं, दूसरी ओर भारत का बोर्डर है जिसमें सूखी फसलें और उजाड़ गांव हैं और कई गांव तो खाली हो गये हैं। अब आर. ए. सी. की पोस्ट ने शिकायत की कि नहरी विभाग का ध्यान बार बार दिलाने के बावजूद पानी नहीं मिला। समूचा की पोस्ट जहां चार चार ट्रकों से पानी पहुँचाया जाता था। वहां की टेल पर पानी नहीं पहुँचा। पंजाब ने इस बार हमारे हिस्से का पानी भी नहीं दिया। पंजाब में देखा है, १५ अक्टूबर के बाद पानी चलाया। भाखरा डेम, पोंग डेम पर १५ पर्सेन्ट का हमारा निश्चित हक है। ५५ से बराबर ले रहे हैं। पर १५ परसेन्ट पानी कभी भीह में नहीं मिला ; दस ग्यारह परसेन्ट से अधिक प्राप्त नहीं हुआ।

हरि के बैराज पर १८ हजार क्यूसेक्स पानी का अधिकार है। पर राजस्थान कैनाल का अधिक पानी पंजाब सरकार इस्तेमाल कर रही है। अध्यक्ष महोदय, एक ओर पानी के अभाव में हमारे यहां बुवाई नहीं हो सकी। राजस्थान का इतना बड़ा भूभाग अकालग्रस्त हो, ३०) मन गेहूँ बिक रहा हो, वहां दूसरी सरकार की हठधर्मी के कारण गेहूँ की फसल बीजी तक नहीं जा सकी ; तो यह एक दुर्लदयपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।

मैं आपके सामने कुछ आंकड़े उपस्थित करूं कि गेहूँ की पैदावार के अन्दर ही तकिना फर्क पड़ गया था। गौर फरमाइयेगा। ६२-६३ में गेहूँ का प्रोडक्शन टनों में १२,२४,०७७ हुआ। ६१-६२ में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

१२,०२,४७७ हुआ ।

एक माननीय सदस्य : जो चाहो सो आंकड़े बोल लो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो आप होते तो बोल देते । सात लाख टन का फर्क पड़ा है । अगर ६३–६४ के आंकड़े लें तो निश्चित रूप से बहुत अधिक फर्क इसमें पड़ेगा ।

असल बात तो यह है कि ५६ में जब इण्डो–पाक ट्रीटी हुई थी, राजस्थान सरकार ने अपने हकों को उस समय सुरक्षित नहीं किया । आज उसी का परिणाम है कि गंग नहर को एक बचत की नहर बना दिया गया । आप उस पर गौर फरमाइये । सतलज के पानी का सारा अधिकार था । व्यास के पानी का खरीफ की फसल में २१ परसेन्ट का अधिकार था । रावी का १६ और पाकिस्तान को ८४. इसमें से ७.६६ पर्सेन्ट हमारा शेयर था और बाकी ईस्ट कैनाल का शेयर था । १५ अक्टूबर के बाद ईस्ट कैनाल चलती रही और हमारे हकों को लुटने दिया गया और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह आई कि कुछ कोन्स्टेन्ट दोनों फसलों के साथ जोड़ दिया गया । ६६० क्यूसेक्स में से ६५० दूसरी फसलों में कान्स्टेन्ट निश्चित रूप से पानी पाकिस्तान को देना पड़ता था । पानी दरियाओं में भले ही सूख जावे, उसका नुकसान हमें । शायद पाकिस्तान के नुमाइन्दों ने सोचा होगा कि इस शर्त को मान लें, पर सतलज के पानी का प्रश्न कहां पैदा होता है ।

हरि के बैराज का बांध लोअर लेवल पर । सतलज का एक बूंद पानी नहीं आता और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि ६६० क्यूसेक्स पानी हमें हर हालत में देना पड़ता है । एक ओर तो यह स्थिति है ।

दूसरी ओर यह स्थिति है कि पंजाब लगातार हमारे एक जिले के एक हिस्से को बाढ़ में डुबा रहा है । सर हिन्दु केसीपेज का पानी हनुमानगढ़ क्षेत्र में निकलता है और जैसे सरकार के स्टेटिस्टिकल विभाग के आंकड़े हैं उन्हीं पर से मैं बता रहा हूं कि प्रति वर्ष हमें इसके लिये ५ करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं । पिछले तीन-चार वर्षों में ३० करोड़ रुपये सरकार को खर्च करने पड़े हैं । एक योजना इसके लिये ४।। करोड़ की बनाकर भारत सरकार को भेजी । टैक्नीकल डिफेक्ट निकाल कर उसे सेन्टर ने रिजेक्ट कर दिया । मैं कहूंगा इसमें पंजाब सरकार की चालबाजी थी । पंजाब सरकार ने गंग कैनाल के पानी को क्यों रोका ? भागवे की योजना को लोअर रीच में लाने के लिये हमारी सरकार ने मान लिया क्योंकि अपर रीच में लाने से पंजाब के गांव और जमीन डूब में आते । हमने दो पेजेज में इस योजना को बनाया था । ३२१ लाख की बनाई थी योजना तो, पर वह ८० लाख की योजना बना कर रख दी गई बाद में ।

नोहर भादरा में ६०० क्यूसेक्स पानी की योजना बनाई, पर इसमें भी अड़चन पैदा हो गई । पंजाब सरकार गंग कैनाल के पानी को क्लच करके दबाव डालना चाहता है हमारे पर । मैंने पंजाब का क्षेत्र देखा है । फाजिलका और सरहिन्द के क्षेत्र

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में आठ आठ पानी लगा है। फिरोजपुर में दो दो मांगे आउट लेट बना लिये हैं।

हमने इस प्रकार से घोषणा की थी कि हम अपने ड्राइव में गन्ना बढ़ावेंगे। राजस्थान की सरकार के साथ धोखा किया। पानी उन्होंने ले लिया।

एक प्रश्न पैदा होता है, माननीय मंत्री जी, मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं, हमारे हुकमरान क्या कर सकते हैं? वे यह कर सकते हैं जो आसाम की सरकार ने किया। आइल रिफाइनरीज की बात जब दूसरे राज्यों में लगाने की चली तो वे केन्द्र के पास गये और उन पर यह दबाव डाला। केन्द्र को अपने प्रोग्राम में चेन्ज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर दूसरी जगह लगाने की बात की तो हम इस्तीफा दे देंगे। वे दिल्ली गये और वहां के मुख्य मन्त्री ने अपने मन्त्रियों सहित जवाहरलाल नेहरू के मुंह पर इस्तीफे मारे और सारे आसाम की जनता के विरुद्ध, अगर आप कोइन कुर्सियों का लोभ नहीं है और राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के प्रति कुछ भी दर्द आपके दिलों में है तो भारत सरकार से कह दीजिये कि या तो गंग नहर में पानी पूरा दो, हमारे हक का पूरा पानी दो, वरना ये हमारे इस्तीफे लो।

अध्यक्ष महोदय, हरिजन उद्धार के नाम पर बहुत सी बातें सुनी हैं और पिछले सदन के अन्दर यहां पर एक मनीलेन्डर्स बिल भी आया था और बहुत से लोग उसके ऊपर चिढ़ भी गये थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के प्रभाव से और दबाव से उस बिल के अन्दर बहुत सी रियायतें भी दे दीं, लेकिन मैं इस सदन का ध्यान रिज़र्व बैंक की उस रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहूंगा जो कि अभी अभी पब्लिश हुई है। उनकी रूरल सर्वे की रिपोर्ट है जिसके अन्दर उन्होंने इस बात को निश्चित रूप से इंगित किया है कि सारे भारतवर्ष के अन्दर मगरूज, कर्जदारी सबसे अधिक अगर कहीं पर है तो वह राजस्थान के अन्दर है और वह ७० प्रतिशत राजस्थान के अन्दर है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आदिवासियों के इलाके देखने का मौका मिला। मैंने धौलपुर के क्षेत्रों की बातें सुनीं। मैंने राजस्थान के मगरूज किसानों का एक चित्र देखा। अध्यक्ष महोदय, जिस सागड़ी प्रथा के विरुद्ध यहां एक कानून बना, मैं अर्ज करूं कि आज डूंगरपुर के अन्दर वह सागड़ी बाकायदा कायम है। आज भी १० रुपये बोहरा देता है तो १२ रुपये लिखाता है और उसके बाद ६ किश्तें बांधता है। तो पहले किश्त पर ही मैथेमेटिकल प्राग्रेशन से इन्टरेस्ट लगाता है। अध्यक्ष महोदय, उस आदिवासी क्षेत्र में जाकर देखें कि उदयपुर के अन्दर राजस्थान की नियामत चली गयी। एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी चली गयी, मेडिकल कॉलेज चला गया, इन्जीनियरिंग कॉलेज चला गया; लेकिन उदयपुर के अन्दर स्थिति यह है कि उदयपुर के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े हो जायें तो उनकी जमानत जब्त हो जाये। उदयपुर आज इसका सुबूत है। आज वहां का आदिवासी और उदयपुर का रहने वाला गरीब इन्सान ३० रुपये मन का गेहूं लाकर खाता है और २० रुपये मन बाजरी लेकर खाता है। मैं मुख्य मन्त्रीजी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

से कहूंगा कि आज उनको खाने के लिए दाने चाहिए, वे यूनिवर्सिटी को नहीं चाटेंगे, मेडीकल कॉलेज को नहीं चाटेंगे, उसके पेट के अन्दर दाना चाहिए। वह सादड़ी प्रथा आज वहां पर है। आज भी उनकी औरतें और बच्चे गहने हैं। आज भी ऐसे आदिवासी हैं जो सादड़ी प्रथा से त्रसित हैं।

श्री भीखाभाई (समाज कल्याण मंत्री): आप अर्थ तो समझते हैं नहीं, यह सादड़ी नहीं सागड़ी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या फर्क पड़ता है इस अर्थ में।

अध्यक्ष महोदय, आज सारा का सारा डूंगरपुर क्षेत्र है वहां से १०-१५ हजार आदमी अहमदाबाद के अन्दर जाते हैं और मजदूरी करते हैं। आज सारे डूंगरपुर के अन्दर एक भी इन्डस्ट्री कायम नहीं हो सकी है। जवाई बांध के ऊपर फर्टीलाइजर की बात कही मुख्य मंत्रीजी ने....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जयसमन्द है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्षमा कीजिए, जयसमन्द। एक योजना थी नहर ले जाने की आसपुर क्षेत्र में। अब वह योजना खत्म कर दी गयी है क्योंकि फर्टीलाइजर फैक्ट्री जो हनुमानगढ़ के अन्दर लगने वाली थी वह जयसमन्द के ऊपर लगेगी और जो नहर आसपुर क्षेत्र को सिंचित करने को थी वह अब नहीं लगेगी।

अध्यक्ष महोदय, १० करोड़ रुपये का एक कट किया गया है और वह अकाल की स्थिति को देखते हुए किया गया है। योजनाओं को पीछे फैंकने की बात सोचना और अर्थाभाव दिखाना, उसके संबंध में मैंने और मेरे दल ने लगातार कई योजनायें सदन के सामने उपस्थित की हैं। मैंने सदन का ध्यान दिलाया है कि जहांमाइनिंग लीज का सवाल है, करोड़ों रुपयों का लीकेज होता है, सेल्स टैक्स के रूप में; एक्सेस रॉयल्टी के ऊपर और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेन्स के बारे में आपकी इन्डस्ट्री और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पॉलिसी बहुत ही करप्ट पॉलिसी है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट लाइसेन्स के अन्दर बहुत से घोटाले हैं। १ करोड़ ८५ लाख रुपये का इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट का लोन था उससे संबंधित कागजात जला दिये गये और मैं अर्ज करूं कि इस संबंध में इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट से कोटा दिये गये हैं उसमें बहुत भारी गबन है। मैं आपके सामने कुछ गबन के केसेज़ स्पष्ट रूप से रखूंगा कि झुंझुनू वाले सेठ मुरलीधर को कोटा दिया गया ८० लाख रुपये का आयर्न एण्ड स्टील का, जिसमें ५० लाख रुपये का कोटा बार्ब्ड वायर के संबंध में था। केवल २॥ लाख रुपये का कोटा सिर्फ जयपुर शहर के अन्दर यूज़ किया और बाकी सारा का सारा कोटा ब्लैक के अन्दर बेच दिया गया। इसी तरह से शारदा एण्ड कम्पनी जो कि खेतान भवन के अन्दर है उसको ८ लाख का कोटा दिया गया और यह सारा का सारा ब्लैक के अन्दर बिक गया। अलवर में एक ऑइल मिल को २ लाख ५० हजार रुपये का कोटा कैम्फर का दिया गया है। यह सारा का सारा कोटा ब्लैक में बिक गया और हनुमानगढ़ के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्दर बारूद बनाने का ठेका दिया गया। १६५६ से ६३ तक का ठेका २३०० में दे दिया गया। कोई आगरे में एक रामलाल माथुर हैं उनको यह ठेका दिया गया। यह ठेका और किसी महाशय ने चाहा और इसके लिए २२ हजार ३०० रुपये देने के लिए तैयार थे, वह भी केवल एक वर्ष के लिए। जब कि २३०० रुपये के अन्दर ५ वर्ष का उसको ठेका दे दिया गया। इसमें १ लाख रुपये का सरकार को घाटा हुआ। अगर इस संबंध में आप एक एफ० आई० आर० चाहते हैं एन्टीकरप्शन के सामने, आपको मैं एफ० आई० आर० का नम्बर बताऊं। इस संबंध में बाकायदा तलाशी हुई। खेतान एण्ड भवन वाली कम्पनी के ऊपर छापा मारा गया और आयर्न एण्ड स्टील कॉर्पोरेशन कलकत्ता और बम्बई के अन्दर हमारे यहां के इन्टेलीजेन्स के डी० आई० जी० गये और उन्होंने वहां से लेकर सीज़ किया और इसका केस एन्टीकरप्शन के अन्दर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके ऊपर कार्यवाही ठप्प है।

अध्यक्ष महोदय, अभी दो वरिष्ट अधिकारियों के यहां छापे मारे गये; एक उदयपुर के अन्दर एम० एल० सेठी हैं उनके यहां छापा मारा गया और दूसरा छापा जयपुर के अन्दर मिस्टर सूद के यहां, जो कि डाइरेक्टर आफ माइन्स नागपुर हैं और गंगानगर के अन्दर कलेक्टर थे। जो सेठी साहब के यहां छापा मारा गया उसमें ७ लाख की राशि का माल बरामद हुआ, २ लाख से अधिक केश बरामद हुआ। पिछले सदन में मेरे दल के नेता ने इन्हीं सेठी साहब का एक पत्र रखा था चौथमल एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर का। यही सेठी साहब कमल एण्ड कम्पनी, जिनका सिटी ट्रान्सपोर्ट के ऊपर कब्जा है और जो उनके रिश्तेदार हैं और ब्रोदर-इन-लॉ इनके एडवोकेट जनरल हैं और जो कमल एण्ड कम्पनी सूरतगढ़ के अन्दर जाल फैलाये हुए है, जिसमें बहुत मुकम्मिल भ्रष्टाचार है और यह सेठी साहब लीज़र्स के साथ माहवारी रकमें बांधे हुए हैं।

साहू जैन ब्रदर्स, जयपुर उद्योग के संबंध में मैं आपके सामने एक केस रखूं कि फलौदी के पास २० मील की लीज़ का भाग था, लेकिन ३ और ६ मील का ऐसा हिस्सा था जिसको कि यह लीगली एक्सकेवेट कर रहे थे। परमानन्द की एक दरख्वास्त ली, जिस दरख्वास्त के अन्दर इस क्षेत्र का सारा लीज़ ले लिया गया और जब उस एरिया को एक्सकेवेट करने गये.......

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : किसका कह रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माइनिंग स्टोन का। मैं आपके सिर पर नहीं मारना चाहता था, लेकिन आप मरवाना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वहां रेगिस्तान है, स्टोन कहां है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह उनको समझना पड़ेगा कि जयपुर उद्योग में क्या पड़ता है ? यह क्षेत्र सवाई माधोपुर और लाखेरी के बीच में है। जब यह ठेका दिया गया है और जब रॉयल्टी कॉन्ट्रेक्टर वहां पर रायल्टी कलेक्शन के लिए पहुंचा तो उन्होंने उस वक्त जो वहां पर इन्जीनियर थे मि०

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मेहता उनको इन्फोर्म किया कि जयपुर उद्योग वाले एक्सकेवेट कर रहे हैं। इस पर जी०एल० मेहता ने १,८००) रु० रायल्टी कांट्रेक्टर को दिलवा दिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप–मंत्री, खनिज) : किस साल की बात बता रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह १९५३-५४ की बात है। अब की बात तो अब बताता हूँ। उसके लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आ रहा हूँ धीरे-धीरे। जब बाकायदा माइनर मिनरल रूल्स कायम हुए तो यह जो एरिया है यहां पर जो डेड रेन्ट कायम हुआ वह ६४,०००) रु० इस क्षेत्र के लिए कायम हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह क्या फलौदी का हुआ क्या ? माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं। वह लाइम के अन्दर ज्यादा है और लाइम स्टोन के लिए जो रॉयल्टी होती है वह कम है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन उसका डेड रेन्ट ६४,००८) रु० है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह ६४,०००) रु० केमिकल इन्डस्ट्रीज़ में काम आने वाले चूने के लिए है जो कि जोधपुर डिवीज़न में है और जिसको लाइम स्टोन कहते हैं उसके लिए इतना नहीं है।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : उन्हें कहने दें। उन्होंने कितनी ही बातें सही कही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मिनरल रूल्स के तहत डेड रेन्ट का ६४,०००)रु० तय हुआ था। मैं अपनी चीज के सम्बन्ध में डेफिनिट हूँ। इसके अन्दर हजारों रुपयों की एक्सेस रायल्टी की चोरी करते हैं और मिनरल कन्सेशन रूल्स के तहत यह सारा कुछ है। और इसके साथ साथ कम से कम ५७ लाख रुपये का स्टोन यहां पर एक्स्केवेट किया गया है, अपनी सीमेन्ट मिल के अन्दर यूज़ किया गया है और उन्होंने बाकायदा एक्सेस रॉयल्टी इस माइन के अन्दर कन्सील की है। अब भी बाकायदा रॉयल्टी को कन्सील करते चले आ रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि यह माननीय सदस्य जानते नहीं हैं कि इस एरिया में कन्सील करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इससे सीमेन्ट का प्रोडक्शन होता है और सीमेंट की तादाद कन्सील नहीं होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सीमेन्ट की तादाद का प्रश्न नहीं है। और दूसरे तरीकों से भी यह कन्सील होता है। सीमेन्ट की तादाद को मैं अर्ज करता हूँ कि उसको अगर आप टेली करेंगे तो काफी करप्शन मिलेगा। आपने कभी सीमेंट की तादाद को टेली करने की कोशिश नहीं की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी ही अपना भाषण समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जितना भी एक्सेस रॉयल्टी और डेड रेन्ट का प्रश्न है उसके अन्दर यही एक प्रश्न मुख्य रूप से आता है कि जो डेड रेन्ट सरकार तय कर देती है उसके बाद में माइनर मिनरल कन्सेशन्स रूल्स के तहत जहां कि सवा छः पर्सेन्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पर हन्ड्रेड क्यूबिक फुट रॉयल्टी चार्ज होती है वहां पर उसको मेजर मिनरल डिक्लेअर कर देते हैं और उस रॉयल्टी में उनको कन्सेशन देते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स की डेफिनिट केटेगरीज हैं । माइनर और मेजर मिनरल्स राजस्थान गवर्नमेंट डिक्लेअर नहीं करती है और न कर सकती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कन्सेशन्स इन रूल्स के अन्दर दिये गये हैं, विशेष रूप से मांडी और खारचारी लाइम स्टोन के अन्दर । मैं अर्ज करूं कि नीम के थाने के अन्दर सीमेन्ट फेक्ट्री लगाने की घोषणा मंत्री महोदय ने की थी, और इस बात को मुख्य मंत्री महोदय मानेंगे कि जहां पर वह ५ साल का लीज़ बाकायदा माइनर मिनरल रूल्स की दफा ८ के अन्दर मौजूद है कि सरकार १० साल के लिए लीज़ दे सकती है वहां मोदी ब्रदर्स द्वारा जो लीज़ ली हुई है, तो उन्होंने १० साल का ओप्शन दिया है तो उनको १० साल के लिए लीज़ रेन्ट पर दी है । केबिनेट मीटिंग के अन्दर, जो सीकर में हुई थी उसमें आपने बाकायदा घोषणा की थी कि हम यहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री लगायेंगे । इसके बावजूद भी आपने वहां पर मोदो ब्रदर्स को १० साल का लीज़ दिया और इस खारचारी माइन्स के सिलसिले में कौल साहब ने उनका सैल्स टैक्स चैक करने के लिए जो रेकॉर्ड सीज किया है उसमें यह बात स्पष्ट उभर कर सामने आई है कि कम से कम ८ लाख का सेल्स टैक्स का एवियेशन हुआ है, चोरी हुई है और इसके साथ-साथ मैं यह अर्ज करूं कि मुझे यह मालूम हुआ है कि उनका महकमा अब इस सिलसिले में स्लगिश हो गया है । तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूँ....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : यह माननीय सदस्य जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ८ लाख का वहां पर जो सैल्स-टैक्स का कहा है तो उनको ये फीगर्स कहां से मालूम हुए हैं । मेरा जहां तक ख्याल है, मैंने कभी नहीं कहा है कि ८ लाख का गबन हुआ है । एसेसमेंट उनका हो रहा है और उनकी अपील रेवेन्यू बोर्ड में भी चल रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहता हूँ कि आपको इत्तिला देने के लिए मेरे पास सूचना है कि सैल्स-टैक्स में ८-१० लाख का घोटाला है ।

(व्यवधान)

मैं यह सूचना अर्ज कर दूं कि मुझे यह विदित है कि उसको रफा-दफा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी ही भाषण समाप्त करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण के अन्दर औद्योगिक शान्ति, इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर शान्ति की बात भी कही गई । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इन्डस्ट्री में शान्ति रही है । यह ठीक है कि २ अक्टूबर, ६२ को जब कि राजस्थान के सारे मजदूरों के ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेंस में इस बात का समझौता

(श्री योनेन्द्रनाथ हांडा)

किया था। सरकार के साथ में बाकायदा पीस ट्रूस हुई थी कि कोई भी मजदूर हड़ताल नहीं करेगा और मजदूर एक दिन की डेली वेजेज़ देंगे। इसके साथ साथ मालिकों ने और सरकार ने भी वायदे किये थे। उस वायदे को तो लगातार मजदूरों ने दो साल तक निभाया है, लेकिन सरकार ने उस वायदे को नहीं निभाया है। मैं अर्ज करूं कि मैं आपको बताऊं कि कितने मैनडेज़ वेस्ट हुए है। कम से कम ६०,००० मैनडेज़ वेस्ट हुए हैं। २ अक्टूबर, ६२ से पहले १ लाख से ज्यादा मैन डेज़ वेस्ट हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मजदूरों को विक्टीमाइज़ेशन को रोकने का जो वायदा किया गया था उस वायदे को वे नहीं निभा पाये। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए सारे राजस्थान के मजदूरों ने एक मांग-पत्र पेश किया है और इस बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए मांग-पत्र में मांग की है कि उनका जो डियरनेस एलाउन्स हैं उसमें ८० नये पैसे पर पॉइन्ट बढ़ाया जाय; २ अक्टूबर, सन् ६२ को बेस मानते हुए यह इन्क्रीमेंट किया जाय। सरकार ने ५२ को बेस मानते हुए ३६.२ पोइन्ट्स इस कंज्यूमर्स इन्डैक्स के अन्दर माना है। और इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने उन्होंने यह मांग भी पेश की है कि कंज़्यूमर्स प्राइस इन्डैक्स डियरनैस एलाउन्स के साथ जोड़ा जाय और फेयर प्राइस शोप्स वहां पर खोला जायं और बेसिक सैलेरी के अन्दर भी इन्क्रीज़ की जाय। ८०) रुपये बेसिक सैलेरी मानी जाय और तीन साल के बाद बेसिक सैलेरी १०२ की जाय। सारे राजस्थान की ट्रेड यूनियन्स, जिनमें सरकारी पक्ष की ट्रेड यूनियन्स शामिल नहीं हैं, तथा जिनमें एच०एम०पी० शामिल हैं, प्रजा सोशियलिस्ट और समाजवादी पार्टी की ट्रेड यूनियन्स शामिल हैं उन्होंने सरकार के सामने इस बात की घोषणा करदी कि इन बढ़ी हुई कीमतों के अन्दर और बढ़ी हुई स्थिति के अन्दर मजदूर अपनी मुख्य मांग को मांगता है और यदि सरकार उन्हें नहीं मानेगी तो सारे राजस्थान में २१ फरवरी को सारे राजस्थान के मजदूर, चाहे वे पी० डब्ल्यू० डी० के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल विभाग के हों, चाहे वे प्राइवेट फैक्ट्रीज़ व मिलों में काम करने वाले मजदूर हों, एक दिन की हड़ताल करेंगे। लेकिन सरकार ने कुछ अक्लमंदी से काम लिया है। उन्होंने १८ तारीख को मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों को बुलाकर घोषणा की कि ५) रु० जहां तक वेज कोड लागू होता है उन कंसर्न्स में, मंहगाई में वृद्धि करती है। लेकिन यदि हम मंहगाई का स्तर २ अक्टूबर, ६२ को बेस मान कर लें और देखें कि कितना पोइन्ट इन्क्रीज़ हुआ है तो पता चलेगा कि १४–१५ पोइन्ट इन्क्रीज़ हुआ है। तो इस हालत में केवल ५ रु० की वृद्धि हो काफी नहीं है। सरकार ने माथुर कमेटी का जिक्र किया है जिसमें डीयरनेस अलाउन्स को कन्ज़्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स के साथ जोड़ने की बात कर दी है, लेकिन इस चीज का क्या इन्तजार करेंगे कि माथुर कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन इसके साथ साथ यह बात निश्चित रूप से है कि इतनी कम तनख्वाह में मजदूर गुजर नहीं कर सकते, इतने थोड़े डीयरनेस अलाउन्स में वे गुजर नहीं कर सकते और सारे राजस्थान के मजदूर तुले हुए हैं कि निय-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मित मांग करके लेकर रहेंगे । राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस चीज को स्पष्ट नहीं किया कि जो कांट्रेक्टर्स के मजदूर हैं उनकी क्या स्थिति है । यदि सारे राजस्थान के कांट्रेक्टर्स के मजदूरों की स्थिति देखें तो बहुत दुर्लक्षपूर्ण है । अभी रावत भाटा, राणा प्रतापसागर के साढ़े चार हजार मजदूर स्ट्राइक पर हैं । उनकी हालत दयनीय है । २।। रुपये डेली वेजेज़ पर कांट्रेक्टर उनको रखते हैं और दो महीने बाद एक रुपया या डेढ़ रुपया देते हैं और कहते हैं कि लेना है तो लो या चले जाओ । मिनिमम वेजेज़ एक्ट उन पर लागू नहीं है । वहां पर एक भी फेयर प्राइस शोप नहीं है । वहां के मजदूरों ने एक स्कूल की मांग की थी, लेकिन स्कूल के बजाय कौल साहब का महकमा वहां पर पहुँच गया और शराब की दूकान खोल दी । फेयर प्राइस शोप की मांग की तो कोटा शराब का बढ़ गया । वहां पर इलाज का कोई बन्दोबस्त नहीं है, यदि मजदूर बीमार पड़ जाते हैं....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : माननीय सदस्य ने सिफारिश की थी कि वहां शराब का ठेका खोला जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शराब के ठेके से मेरा ताल्लुक नहीं है । मैंने जिस चीज की सिफारिश की थी वह आप जानते हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : बाकी ठेके किसकी सिफारिश से दिये गये, यह भी बता दीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सीकर में अंग्रेजी ठेके की सिफारिश किसने की थी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a Point of order, Sir, अभी सदन में इस तरह की बात हुई है उसकी स्पष्टतया जांच होनी चाहिये कि रिपोर्ट की तरह तो नहीं है; सदन को स्पष्ट मालूम होना चाहिये कि वित्त मन्त्रीजी ने इनकी सिफारिश पर ठेका खोला है या रिपोर्ट है; यह स्पष्ट बात सदन के सामने आनी चाहिये । सदन की कार्यवाही को इस तरह से हल्केपन से नहीं लेना चाहिये ।

श्री रामनन्द अग्रवाल (अलवर) : सरकार ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि सिफारिश पर सरकार काम करती है, पक्षपात तरीके से सरकार काम करती है, यह वित्त मन्त्रीजी ने स्वीकार किया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा इससे ताल्लुक नहीं है । वहां के यूनियन ने फेयर प्राइस शोप की मांग की थी वह खुली नहीं । ज्यादा मेडिकल फेसिलिटी की मांग की थी वह इन्क्रीज़ नहीं की गई, लेकिन इतनी बात जरूर हुई कि वहां पर शराब का ठेका खुल गया । वहां पर मोडर्न कन्ट्रक्शन कोर्पोरेशन काम करता है जिसमें ५।। हजार मजदूर काम करते हैं, यह मनुभाई शाह की है, उनके रिश्तेदारों की है...

श्री अध्यक्ष : इस तरह से आप बाहर के लोगों का नाम न लें । आपका समय भी समाप्त हो चुका है । माननीय कृषि मंत्री ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक मिनिट में अर्ज करना चाहता हूँ कि वहां स्ट्राइक चल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रही है। सरकार को कदम उठाना चाहिये। सरकार ने डिक्लेयर किया है, ५ रु० डियरनेस अलाउन्स मजदूरों को बढ़ाने के लिये क्या वह पी०डब्ल्यू०डी० के मजदूरों पर भी लागू होगा; इसका स्पष्टीकरण सरकार कर दे।

श्री अध्यक्ष : श्री कृषि मन्त्री।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया उस पर जो वाद-विवाद चल रहा है मैंने एक दिन छोड़ कर सारा वाद-विवाद सुनने की कोशिश की। उस दिन मैं अचानक दिल्ली में फूड मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स होने की वजह से सदन में उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन फिर भी जो कुछ विचार सदन में रखे गये उनकी सूचना मेरे पास है और जो तथ्य इस सदन में अभी लाये गये बहस के दौरान, माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उनके बारे में मेरी तरफ से जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।

इस साल जो गवर्नर महोदय का एड्रेस हमारे सदन में प्रस्तुत हुआ है उसमें इस सदन के सारे माननीय सदस्य महसूस करते हैं, और सही करते हैं कि हमारा पिछले साल का जो सारा कार्यक्रम रहा है वह काफी कठिन परिस्थितियों में से गुजरा है। आप सब महसूस करेंगे कि इस पिछले साल में या इस चालू साल में जिसमें से हम चल रहे हैं, काफी कठिन परिस्थितियां राजस्थान में उत्पन्न हुईं कुछ कारणों की वजह से; उनमें से बहुत से कारण इन्सान की ताकत के बाहर की हैं जिसकी वजह से यह हालत हमारे यहां और सारे देश में पैदा हुई है। आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारा इस साल का जो वर्ष है वह राजस्थान के १३ जिलों में करीब सवा चार हजार गांवों में अकाल की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में इस वर्ष वर्षा की कमी की वजह से खाद्यान्नों का उत्पादन भी कम हुआ है और इस वजह से घास और चारे का उत्पादन भी कम हुआ है और राजस्थान की करीब ३० लाख जनता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और यह एक ईश्वरीय प्रकोप है और इस प्रकोप को जितनी मजबूती के साथ और सख्ती के साथ, एक इन्सान की सरकार में फेस करने की शक्ति होनी चाहिये, मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं रख रही है और न आगे भी रखेगी। आप इस बात को महसूस करेंगे और जो गवर्नर महोदय ने एड्रेस पेश किया है उसमें यह कहा है कि इस कठिन परिस्थिति को मीट करने के सिलसिले में एक धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया है उसको लेकर आगे चल रहे हैं। काफी बड़ी रकम है। राजस्थान जब से बना ४६ में, उसके बाद कोई तीन–चार वर्ष इस प्रकार स्केयर्सिटी की हालत पैदा हुई। वैसे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान इतना बड़ा प्रान्त है जो १ लाख ३२ हजार स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है; जिसमें औसत रेन फाल ३.४ इंच से लेकर ८०–१०० इंच तक चलती है। ऐसी विशेषता वाले प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे रह जाते हैं जिनमें वर्षा की कमी के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कारण कुछ न कुछ कठिनाई अन्न और चारे के बारे में हर साल रहती है, लेकिन फिर भी पिछले दो-तीन सालों में ज्यादा अकाल की परिस्थिति बनी, उनके मुकाबले में इस साल राजस्थान के १३ जिलों में करीब सवा चार हजार गांवों में अकाल की परिस्थिति बनी है। उसकी अहमियत और इन्टेन्सिटी को ध्यान में रखते हुए जो निश्चय किया है वह भी काफी बड़े पैमाने पर है।

मैं अकाल की इन सारी की सारी बातों के अन्दर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुख्य मंत्रीजी जब अपना जवाब इस सदन में पेश करेंगे तो आपके सामने विस्तृत तौर से इस महकमें के सम्बन्ध में बात करेंगे। मैंने इसकी शुरुआत आपके सामने इसलिए की खास तौर से कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे इन इलाकों का दौरा किया था, जैसा वे अपने भाषण में बता रहे थे; खास तौर से पाकिस्तान के बोर्डर की तरफ बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर ऐसे इलाकों में वे गये थे और वहां जो हालात उन्होंने महसूस की उनको उन्होंने यहां बताया और उन सब हालात को लेकर कहा कि मंत्री महोदयों को अपने इलाकों में जाकर डेरा लगा देना चाहिये, लोगों की मुसीबतों को हल्का करने के लिए। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि अकाल की शुरुआत होते ही, जब इसकी छाया हमारे प्रांत पर पड़ने लगी तब काफी बड़े पैमाने पर, मैं कह सकता हूँ सिवाय एक-दो जिलों को छोड़ कर, जिन गांवों में अकाल की छाया पड़ने लगी थी उनमें मैं स्वयं दौरा करने गया था। वहां लोगों को मैं एक बात कह कर आया था और तब से उसी बात को लेकर हम चल रहे हैं कि ईश्वर के डाले हुए प्रकोप को कम करने के लिए सरकार की और इन्सान की जितनी कोशिश है उसके अनुसार हम कोशिश करेंगे और राजस्थान में आने वाली बरसात, जब तक हमें इसकी भयंकरता को महसूस करना है, तब तक हम इस बात की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में भूख से कोई इन्सान न मरने पाये। हम इस बात की भी कोशिश करेंगे कि हम हमारे पशुधन को जितने बड़े पैमाने पर बचा सकें उतना बचाने की कोशिश करें। यह बात राजस्थान के उन इलाकों में एक विश्वास और हौसला पैदा करने के लिए घर घर में और गांव गांव में जाकर मैंने कही थी। उसी बात को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी दृढ़ता से दोहराना चाहता हूँ कि इस बात का हम प्रयत्न करेंगे, लोगों की दिक्कतें जितनी कम की जा सकती हैं उतनी कम करने की हम कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भाई हांडाजी बोल रहे थे, और आंकड़े पेश कर रहे थे कि बारह हजार भेड़ें मर गई, फिर कहने लगे बारह हजार नहीं बारह सौ भेड़ें मर गई, फिर कहने लगे कि तीस हजार गायें मर गई; मैं आपके जरिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर भूख की वजह से, अकाल की वजह से कोई मौत हुई हो, आज भी उसके निशान हमें देखने को राजस्थान में नहीं मिलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह बात कहने का आधार क्या है? सरकारी रिपोर्ट तो आपके पास नहीं आई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब रिपोर्ट्स आती हैं। हम लोगों से मिलते हैं। जनता की आज भी यह राय है कि भूख से एक भी व्यक्ति को नहीं मरने दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने आदमी नहीं, कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं दूसरी बात यह....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भूख से व्यक्ति मरे हों या नहीं, मैंने गाय के लिए कहा है कि गायें मरी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये मेरी बात। आपकी बात मैंने सुन ली।

जानवरों के सम्बन्ध में बात कही गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि उस इलाके में चारे की हालत जैसे नोर्मल कन्डीशन में होनी चाहिए उस तरह की नहीं है। पानी की उस इलाके में काफी हद तक कमी हुई है। कई गांवों में चारे और पानी की कमी है। लेकिन उस इलाके के जानवरों और पशुओं को दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया गया है। हमारे नागौर और जोधपुर जिले की पांच–छः तहसीलों के पशु एक निश्चित रास्ते से, अजमेर–कोटा–बूंदी होते हुए, उन इलाकों में जाते हैं, उनके लिए चारे का इन्तजाम किया गया। कोटा बूंदी के इलाकों में हमारे ७०–८० हजार मवशी और बहुत से परिवार जाते हैं, उनके लिए भोजन का प्रबन्ध किया था। उस प्रबन्ध के साथ साथ उन इलाकों में घास के डिपोज़ खोल कर, रास्ते में नाज का इन्तजाम कर, जानवरों की तादाद को ध्यान में रखते हुए सब प्रकार की सुविधायें, जितनी हम दे सकते थे, वे पहुंचाई गई हैं। और अब उन इलाकों में भी देख-भाल की जा रही है उन लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से और चारे पानी की वजह से वह कठिनाई और तकलीफ नहीं हो, इसे दृष्टिकोण में रख कर लगातार इन्तजाम किया जा रहा है। उसके बाद जो लोग यहां पर बच गये हैं और जिन लोगों को बाहर के इलाकों में जाने की आदत नहीं है या जिनके लिए जाना सम्भव नहीं रहा है बावजूद सारी कोशिशों के उन इलाकों में जो लोग रह गये हैं उनके लिए दो सौ के करीब डिपोज़ खोल कर, सब्सिडी देकर घास का इन्तजाम किया गया है, आज तक ८०-८५ डिपोज़ खोल कर प्रबन्ध किया गया है। यह हो सकता है कि जैसी घास जानवरों को मिलनी चाहिए, जानवरों को जैसी घास की आदत है उस तरह की घास नहीं मिली हो। फिर भी इस बात की कोशिश की गई है और आज भी घास के डिपोज बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। जो मुसीबतें उस घूड़े के इलाके में हैं उन मुसीबतों में ट्रकों पर घास लाद लाद कर घास पहुंचा रहे हैं, बीस तीस ट्रक एंगेज कर रखे हैं। वे दो तीन चक्कर लगा कर घास पहुंचा रहे हैं और घास का हर जगह इन्तजाम किया जा रहा है। काफी विषम परिस्थिति के होते हुए भी, इन सारी बातों को ध्यान में रख कर इस बात की कोशिश की जा रही है कि जानवरों को बचाया जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तक बड़े पैमाने पर जानवरों के भूख से मरने की सूचना नहीं है। इस प्राकर की हालत मेरी जानकारी, जिन इलाकों में मैं गया हूँ, नहीं है। वैसे तो गांवों के अन्दर जिस प्रकार बीमारी की वजह से

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पशुओं की मौत होती है, कभी कभी उनको ठीक खुराक न मिलने से, कमजोर हो जाने से जो मौत होती हैं–आमतौर पर जो डैथ रेट जानवरों की होती हैं इस नोर्मल डैथ रेट को छोड़ कर मैं आपको कह दूं कि कोई जानवर भूख से नहीं मरा हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई मरा नहीं, लेकिन वह जो नोर्मल खुराक मिलनी चाहिए, नोर्मल हालत में वैसी न मिलने की वजह से उनकी तन्दुरुस्ती में कमी होती है, उसकी वजह से कुछ जानवरों की मौत हो सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर यह बात हो गई हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसी स्थिति राजस्थान में नहीं है और इस स्थिति से बचाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जितनी घास देने का इन्तजाम किया है, दस हजार मन घास देना चाहते हैं वह जो पॉपूलेशन जानवरों और मवेशियों की मानी है उसके लिए ढाई दिन के लिए होती है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूँ कि हम ऐसा ही मान कर चल रहे हैं जैसे उन इलाकों के अन्दर कोई स्टॉक नहीं हो और दूसरी चीजें जानवरों के लिए खाने की हो नहीं और जानवर उसी घास को खावेंगे–ऐसी बात नहीं है। नागौर में ही लीजिये। वहां जो तहसील अफेक्टेड हैं उनमें स्टॉक्स हैं और चारा इस हालत में भी बिक रहा है। बाड़मेर में काफी बड़े पैमाने पर सिवाना तहसील के अन्दर और उसके पड़ौसी जालोर, आहोर के अन्दर घास के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। इसलिये कोई व्यक्ति इसी स्टॉक पर डिपेन्ड करके चलता हो, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में अलग अलग इलाके हैं, जहां अकाल की स्थिति है, उनके पड़ौसी इलाकों में घास के काफी स्टॉक्स हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए यह बात सच नहीं है कि दस लाख मन घास उनके लिए हो; वैसे अगर स्थिति ने मजबूर किया, और घास की आवश्यकता हुई तो उसकी व्यवस्था की जायगी। वैसे अकाल की इन्टेन्सिटी आज है वह साल के शुरुआत की स्थिति से बढ़ी है और ज्यों ज्यों पीछे वाले महीने आयेंगे, अभी फरवरी है; खास तौर से मार्च, अप्रैल और मई के, उसके बाद जून में बरसात, जुलाई में बरसात होकर जब तक नई घास नहीं पैदा हो जायगी तब तक आगे का पीरियड काफी मुश्किल पीरियड आता जायगा। सब दृष्टिकोणों से, लोगों की मजदूरी के दृष्टिकोण से, चारे के इन्तजाम के दृष्टिकोण से, लोगों को धान देने के दृष्टिकोण से आगे आने वाला पीरियड है वह मुसीबत का पीरियड होगा, लेकिन हम उसके लिए सतर्क हैं और किसी माह में किसी इन्तजाम को इन्टेन्सीफाई करने की आवश्यकता हुई, किसी प्रकार की मुसीबत को फेस करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा तो उसको करने के लिए सरकार और सरकार के सदस्य जागरूक हैं और हर इन्तजाम करने की कोशिश करते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में, जब अकाल की हालत है, जैसी कि माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, और गवर्नर महोदय ने भी कहा कि जिन दिनों एमर्जेन्सी डिक्लेअर हुई, अक्टूबर-नवम्बर के महीने में, उसके बाद—आपको मैं हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ—देश के अन्दर प्राइसेज़ का ट्रेन्ड

Page No. 67

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किस प्रकार से चला, इसके बाद फूड ग्रेन्स की कीमत, दूसरी चीजों की कीमतों के ऊपर एमर्जेन्सी का असर हुआ। जब एमर्जेन्सी डिक्लेअर हुई थी, देश के व्यापारी और दूसरे लोगों ने एमर्जेन्सी की काफी मुसीबतों को हितकारी समझा, उस समय नेशन के लिए अपील जारी की गई, हमारे प्रेसीडेंट और प्रधान की तरफ से और ध्यान दिया। नतीजा यह हुआ कि उस दौरान में जब हमारी प्राइसेज़ ऊपर जाने को थीं तो ऊपर जाने के बजाय नीचे गईं। उसके बाद, अगस्त के बाद जब हमारी खरीफ की फसल खराब हुई और वर्षा नहीं हुई तो उस समय ग्रेन कन्डीशन्स बदली। फसलें पानी के अभाव में न हो पाईं। इसलिये भारत के फूड मिनिस्टर ने सारे प्रान्तों की हालत फूड के बारे में थी उसको सुना और फूड मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा और आप इस बात को महसूस करेंगे कि जिन व्यापारियों ने एमर्जेन्सी के समय में सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन प्राइसेज़ को ऊपर नहीं उठने में दिया था वे लोग भी अब इस कोऑर्डिनेशन से दूर दूर भागने लगे और इसका नतीजा यह हुआ कि प्राइसेज़ बढ़ने लगीं और मुनाफाखोरी और होर्डिंग ज्यादा से ज्यादा जोर पकड़ने लगा। अगर आप इसके दो साल के पिछड़े आंकड़ों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पेडी (paddy) और व्हीट और जितने भी धान हैं उनकी प्राइसेज़ लेवल होती है उनका सबका आपस में एक दूसरे से सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके एनेलिसस की तरफ ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि पेडी की प्रोडक्शन १९६१-६२ के मुकाबले में कम थी और व्हीट की भी प्रोडक्शन सारे कन्ट्री की, ओवर ऑल प्रोडक्शन कम थी। यह बात ठीक है कि हमारे यहां पेडी की प्रोडक्शन है उसमें कुछ हद तक कमी आई लेकिन इस तरह की कमी नहीं आई कि जिस तरह से ये प्राइसेज़ हैं उनको सूट करें। इसके अलावा जितने भी अन्य प्रान्तों के फूड मिनिस्टर थे उनका सब का यही मत था कि जिस प्रकार से लोगों की भावना एमर्जेन्सी में काम कर रही थी कि प्राइसेज़ ऊपर न चढ़ें, वह टेन्डेन्सी उनकी अब नहीं रही। इसलिये उस व्यापारी वर्ग में उस अहसास को फिर से पैदा करने के लिए सरकार को प्रयत्न करके वही दृष्टिकोण फिर से उनके सामने लाने चाहिये कि वे लोग अपनी जिम्मेदारी को फिर से उसी तरह महसूस करें जो एमर्जेन्सी के समय महसूस करते थे। इसके लिये कुछ निर्णय कॉन्फ्रेन्स ने लिये हैं और कुछ नीति निर्धारित की है।

(११.१ म० पू०)

इस चीज को आप खुद महसूस करेंगे कि हमारी खाद्य नीति है वह सारे देश की है एक प्रान्त की नहीं और इस पर सारे देश को मिल जुल कर फैसला करना पड़ता है और वे फैसले आपके सामने जल्दी आने वाले हैं। प्राइसेज़ की जो बढ़ती हुई टेन्डेन्सीज़ हैं और जो दिनों दिन तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं उसको रोकने की बहुत आवश्यकता है। मैं यह कहूँगा कि इसके लिए विशेष तौर से ऑर्डिनेन्स बना हुआ है, उस ऑर्डिनेन्स के फॉर्म के नीचे लाइसेन्सीज़ हैं उनको अपना स्टोक डिक्लेअर करने का प्रावधान है। उनको १५-१५ दिनों में अपना स्टोक का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्टेटमेंट पेश करना पड़ता है। अब तक फूड डिपार्टमेंट इसके लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं था क्योंकि नॉर्मल कन्डीशन्स चल रही थीं और सुपीरियर व्हीट की कीमत २० रु० या २१ रु० मन का भाव था और नीचे के क्वालिटी के व्हीट की कीमत १७ या १८ रु० तक पड़ती थी। आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले, वैस्ट बंगाल में कुछ महीने पहले आपने महसूस किया होगा कि पेडी का भाव ५५) रु० क्विन्टल हो गया था और सरकार ने जो मेजर्स उठाये हैं उनके फल-स्वरूप अब ३५) रु० क्विन्टल हो गया है। अतः जो मेजर्स सरकार ने इसके लिये काम के लिए थे उनको व्हीट के लिये भी अपनाना होगा और दूसरे नाजों के लिये भी अपनाये इस जावेंगे। सम्बन्ध में कॉन्फ्रेन्स ने कुछ लौंग टर्म और शॉर्ट पॉलिसी डिसीज़न लिये हैं। मगर, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ऑर्डिनेन्स है उसके सारे प्रावधानों को अमल में लाने के लिये सख्ती से पालन किया जावेगा और इसके लिये उनसे स्टॉक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिया जावेगा और यह देखा जावेगा कि जो डिक्लेरेशन दिया जाता है क्या वह सही तौर से दिया गया है या नहीं और कितना स्टॉक बड़े पैमाने पर उनके पास है। उसको देख कर प्राइसेज़ फिक्स की जावेगी। इस पर कॉन्फ्रेन्स ने सोचा है और मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बारे में जो कुछ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी वह तेजी के साथ करनी चाहिये, जो की जावेगी और प्राइसेज़ को लेवल में लाने की कोशिश की जावेगी और कर रहे हैं।

इन सारी बातों पर कॉन्फ्रेन्स ने विचार किया है, इसके लिये हमने कुछ निर्णय भी लिये हैं। हमारे यहां तीन प्रकार का अन्न मुख्य तौर से काम में आता है। गेहूँ; बाजरा और ज्वार। हमने इसकी फ्लोर प्राइसेज़ १३, १४ और १५ रु० गेहूँ की और ज्वार, बाजरा की ९, १० और ११ रु० रखी। किसानों को राहत देने के लिये सरकार ने कहा था कि अगर प्राइसेज़ नीचे गिरती हैं तो उसको रोकने के लिए सरकार या तो खुद या भारत सरकार की एजेन्सी मार्केट में आवेगी और किसानों को राहत देने के लिए प्राइसेज़ को नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करेगी। इसके अलावा सीलिंग प्राइसेज़ को भी ध्यान में रख कर डिक्लेअर करना होगा। इसके लिए डिटेल्स तय करने के लिये ऑफिसर्स दिल्ली में बैठे थे और उन्होंने कुछ निर्णय लिये।

मैनेजमेंट के बारे में कहा कि सरकार ने हमारे यहां के गेहूँ, मक्का और दूसरा धान बाहर क्यों जा रहा है और हमारी सरकार को चहिये था कि वह धान के इम्पोर्ट को बन्द करती, मगर हमारी सरकार ने हमारे यहां के धान को बाहर भेजा और खराब धान मंगा कर हमको खिलाया जाता है; माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये मैं निवेदन करूंगा कि आज से पहले जोन सिस्टमथा व्हीट का अलग और पेडी का अलग। इसके लिये साउथ, नोर्थ व वेस्ट जोन बने थे। उसी प्रकार के जोन फिर बने और इसी प्रकार से किसको कितने नाज की जरूरत है, सरकारी एजेन्सी को कितना बीच में डाला जावे और किस तरह से स्टॉक पोज़िशन के मीट किया जावे, इन सारी चीजों पर बहुत गंभीरता

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से विचार किया जाए। अगर मैं आपको यह निवेदन करूं कि पंजाब गवर्नमेंट अलग से यह निश्चय करे कि एक्सपोर्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको रोका जावे, यू० पी० सरकार अलग से और राजस्थान सरकार अलग से निश्चय कर ले कि एक्सपोर्ट को रोका जावे तो मैं यह कहूँगा कि उचित नहीं होगा कि एक एक प्रान्त अपनी अपनी सुविधाओं को दृष्टि-कोण में रख कर निर्णय ले, यह नहीं किया जा सकता। हमको सारे देश के लिये और सारे देश के हित में एक सामूहिक निर्णय लेना उचित होगा। इन सारी बातों को देखते हुए और ध्यान में रखते हुए जल्दी ही फैसला होने को है। जैसा मैंने आपको फ्लोर प्राइसेज़ का जिक्र किया है, सीलिंग प्राइसेज़ का जिक्र किया, ऑर्डिनेन्स को किस प्रकार से सख्ती से लागू किया जावे और इसके साथ साथ व्यापारियों के ट्रेण्ड को बदलने और किस प्रकार से बढ़ते हुए प्राइसेज़ के ट्रेण्ड को रोका जावे, इसके लिये काफी गम्भीर निर्णय कान्फ्रेन्स में लिये गये हैं, वे जनता के सामने आवेंगे और सरकार के सामने भी आवेंगे। और मैं आपको निवेदन करूं कि सरकार को अगर कोई सख्त से सख्त कदम भी उठाने पड़ें तो उठाने में कसर नहीं रखेगी जब कॉन्फ्रेन्स के निर्णय उनके सामने आवेंगे।

इसके अलावा एमर्जेन्सी के समय जो व्यापारियों का ट्रेण्ड था वह नहीं रहा है। चीन के हमले के समय जो व्यापारियों का ट्रेण्ड था उसके लिए उनमें कॉन्फीडेन्स रेस्टोर करना होगा और प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स के बीच में ट्रेड एजेन्सी अननेसेसरी गड़बड़ करते हैं उनको समझायश की जावेगी और कुछ कानून के जरिये और कुछ सख्ती के जरिये और कुछ व्यापारियों को कॉन्फीडेन्स में लेकर समझायश की जावेगी कि हम मुसीबत से गुजर रहे हैं, इसलिये अननेसेसरी प्राइसेज़ रेज़ नहीं हों। इसके लिये मजबूती से कदम उठाया जावेगा और उसका परिणाम, मेरी ऐसी निश्चित धारणा है कि अच्छा होगा, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि वेस्ट बंगाल में जो प्राइसेज़ ५५ रुपया प्रति क्विन्टल तक पहुंच गई थी, उनको इस प्रकार के स्टेप्स से ३५ रुपया प्रति क्विन्टल तक ला दिया गया। और तीन चार महीने के प्रयास से ला दिया गया; तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का ऐसा मत बनता है तो इससे प्राइसेज़ को नीचा ला सकेंगे। तो मैंने फूड प्रेन्स के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखीं। पानी के साथ कुछ और बातें जुड़ी हुई हैं उनके सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हुं। शुगर और गुड़ के बारे में देश में कुछ हालात पैदा हुए। पिछले सैशन में शूगर के बारे में कैसी परिस्थिति बनी, यह मैंने निवेदन किया था। इस समय कन्ट्री की क्या ओवर ऑल पोज़िशन है और राजस्थान में क्या हुआ, इस बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज देश में शूगर की जो हालत है उसके बारे में हमने उस कॉन्फ्रेन्स में डिस्कशन किया। वहां जो फूड मिनस्टर साहब ने कहा, आपने अखबारों में पढ़ा है। आने वाले वर्ष में भी शूगर की बहुत हैप्पी पोज़िशन हमारे कन्ट्री में नहीं होने वाली है, इस बात को फूड मिनिस्टर साहब ने कहा था; इस प्रकार की बात आपने अखबारों में पढ़ी होगी। इस साल शूगर का काम शुरू किया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

था, तो करीब २५ लाख टन शूगर की देश को जरूरत है। हमने २७ लाख टन से शुरू किया और देश को अगले साल का जो टार्गेट शूगर प्रोडक्शन का था वह ३१ लाख टन का था। फरवरी के एन्ड तक शूगर मिल्स के फीगर्स आये हैं उनको देखने से पता चलेगा कि पिछले दो साल से इनको कम्पेअर करें तो पहले से प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। ६१-६२ में साढ़े तेरह लाख टन शूगर का प्रोडक्शन हुआ, ६२-६३ में साढ़े चौदह लाख टन शूगर का प्रोडक्शन हुआ और इस साल करीब १६ लाख टन।

श्री रामकिशन (वैर) : उत्तर प्रदेश और बिहार के भी शामिल हैं........

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे इण्डिया की मिलों की बात बता रहा हूं। पर आज जो रेट चल रही है केन की, मिलों में गन्ना कम आ रहा है। खास तौर से राजस्थान को लीजिये; बारह तेरह लाख मन पैदा कर सकेंगे, क्योंकि गन्ना गुड़ बनाने में ज्यादा डाइवर्ट हो गया है। इस वजह से और दूसरी वजहों से जितना गन्ना मिलों को मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पा रहा है। रेट गंगानगर और भोपाल सागर दोनों में बढ़ाई हैं। बावजूद इन परिस्थितियों के गन्ने से गुड़ बनाने में एक आना, दो आना प्रति रुपया रिटर्न आता है। इस हिसाब से राजस्थान की स्थिति को ध्यान में रखें तो ज्यादा गन्ना मिलों में नहीं जायेगा। इसलिये पिछले साल से भी राजस्थान का प्रोडक्शन कम है। लोंग रेंज से यही स्थिति हिन्दुस्तान में है कि जितना गन्ना मिल वालों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। ऐसी दशा में जो ३१ लाख टन शूगर का प्रोडक्शन करने का हिन्दुस्तान का टार्गेट था उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। ऐसा केन्द्र के फूड मिनिस्टर का और दूसरे प्रोविन्सेज़ के खाद्य मंत्रियों का ख्याल है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : भोपालसागर शूगर मिल बन्द क्यों हो गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गन्ना जितनी मात्रा में चाहिये उतना नहीं आ रहा है, लोग गुड़ बना रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : रेंट्स का ही तो झगड़ा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो रुपया मेग्ज़िमम तक कर सकते हैं, पर दो रुपये के भाव में भी गन्ना नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि गन्ने से गुड़ प्रोडक्ट करते हैं तो रिटर्न उनको एक आने से २ आना तक प्रति रुपया मिलता है। ये बहुत सारी बातें हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : किसानों को हताश किया गया है इसलिये गन्ना नहीं आ रहा है। ५ रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से तय किया गया और ४.७० न. पैसा दिया, इसलिये किसान हताश हो गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे उस डिस्प्यूट का पता नहीं है। इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर सम्बन्धित मिनिस्टर हैं वे बता सकते हैं।

तो जिस टार्गेट पर हम पहुंचना चाहते थे उस तक शायद नहीं पहुंच सकेंगे। ३१ लाख टन शूगर प्रोडक्शन का हिन्दुस्तान का टार्गेट था उसके बजाय २६ लाख टन प्रोड-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

क्शन कर सकेंगे। इसमें से हमें एक्सपोर्ट का कमिटमेंट पूरा करना है क्योंकि हमें फोरिन एक्सचेन्ज की आवश्यकता है। लास्ट ईयर का ५ लाख टन का एक्सपोर्ट का कमिटमेंट था उसको पूरा कर चुके, ३ लाख टन शूगर का इस साल का कमिटमेंट है उसे हम पूरा करना चाहते हैं। जो इससे बचता है उससे हमें काम चलाना है।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान की २६ लाख टन की डिमाण्ड है, २६ लाख टन शूगर का प्रोडक्शन होगा, उसमें से ३ लाख टन शूगर का एक्सपोर्ट होगा तो २६ लाख टन शूगर हिन्दुस्तान के पास रह गई, और आपके कहने के अनुसार २६ लाख टन की खपत है तो फिर कमी किस बात की रहेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : कुछ मिनिमम क्वान्टिटी केरी ओवर करनी पड़ती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ केरी ओवर भी करना पड़ता है। १.७ से हमने केरी ओवर किया था। सब ध्यान रख कर चलना पड़ता है। इसलिये जितना हमारा कमिटमेंट है उतना तो एक्सपोर्ट करना है। भारत सरकार के फूड मिनिस्टर ने यहां तक कहा है कि अगले साल में कुछ स्टेट्स का कोटा शायद घटाना भी पड़े, पर राजस्थान का कोटा ६ हजार टन है वह कम नहीं किया जायगा। जो हमारा ६ हजार टन कोटा है वह जिस बेस पर सारे कन्ट्री का कोटा बना था उसी बेस पर बना था। ६१ में शूगर की कमी हुई थी तो राजस्थान के लिये साढ़े आठ हजार टन कोटा अलॉट किया था। उस समय ट्रेन्ड (trend) और मांग के अनुसार हमारा कोटा बना। उस समय राजस्थान ने कभी ३ हजार टन, किसी महीने में साढे तीन हजार टन उठाया, मेग्ज़िमम साढ़े पांच हजार टन कोटा शूगर का उठाया और उसी के आधार पर यह कोटा निर्धारित किया गया। क्यों नहीं उठाया, इसके कारणों को हमने एनेलाइज किया है और वह कारण यह है कि खण्डसारी गुड़, मुश्ती के भाव, दानेदार शक्कर के मुकाबले कम थे, इसलिये लोग गुड़, खण्डसारी और मुश्ती को ज्यादा काम में लेने लगे, दानेदार चीनी को खाने के इतने उत्सुक नहीं थे। तो शूगर की उस समय की खपत को ही कोटा मुकर्रर करते हुए बेस मान लिया; अब तो गुड़, खंडसारी, मुश्ती सब ही का कन्ट्रोल करना पड़ा। जब इस तरह की मुसीबत बढ़ जाती है तो कमी के सिस्टम को, कन्ट्रोल के सिस्टम को अपनाना पड़ता है।

दूसरे प्रोविन्सेज़ में कोटा ज्यादा है, दो-दो करोड़ की पोपुलेशन हमारे पड़ौसी गुजरात और पंजाब प्रान्तों की है, पर पंजाब को १४ हजार टन और गुजरात को ११।। हजार टन शूगर का कोटा प्रतिमाह मिलता है, इसलिये उनकी हालत हमारे जितनी खराब नहीं है; बल्कि यहां तक होता है कि जब हमारे यहां ब्लैक मार्केट में प्राइसेज़ हैवी होती हैं तो पड़ोसी स्टेट्स से वहां का कोटा हमारे यहां आना शुरू हो जाता है। यह सही है कि हमारा कोटा कम है, पर उस समय जो राजस्थान का कोटा उठाने में कमी रही थी उसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इन सारी समस्याओं को गंभीरता से विचारना होगा। निश्चित रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोटा बढ़ने की आशा है।

श्री भैरोंसिंह : इस साल कितना मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह महीने का कोटा होता है। वह ६ हजार टन मिलता है। होली और दीवाली के लिए ५००–६०० टन एक्स्ट्रा मिलता था। वह हमारे कोटा में से काट कर तीन-चार महीनों में पूरा कर दिया। जैसा मैंने कहा, हमने अपने केस को भारत सरकार के सामने रखा है और खाद्य मंत्री के सामने भी। आशा है कि राजस्थान को कोटा ज्यादा मिलेगा। अब राजस्थान में शक्कर के वितरण का प्रश्न है········

श्री भैरोंसिंह : मैं एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि राजस्थान को ६ हजार टन कोटा मिलता था, इस शॉर्टेज के बाद में जो कोटा मिलना चाहिए उसमें एक्चुअल कितनी कमी आई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां दो करोड़ की पॉपुलेशन है वहां जो कोटा मिलता है वह दस हजार टन से कम नहीं है। हमारा कोटा ६ हजार टन है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल है कि जो शूगर आपको ऑर्डिनरी टाइम्स में मिलती थी उसके बाद जो एमर्जेन्सी या शोर्टेज आई उसमें आपको कुल कितना मिला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऑर्डिनरी टाइम्स में जो आता था वे फिगर्स लेकर मैं आपको बताऊं। वह करीब ११ हजार टन के बीच पड़ता है नोर्मल ट्रेड चैनल्स के बीच में। १९६१ में राजस्थान को साढ़े आठ टन हजार कोटा दिया था लेकिन हमने कभी भी साढ़े आट हजार नहीं उठाया ५।। हजार टन से अधिक कभी नहीं राजस्थान ने उठाया। इससे उन्होंने यह इन्फरेन्स डिराइव कर लिया कि राजस्थान के लोगों की खांड खाने की आदत कम है। इसलिए उन्होंने कृपा करके ६ हजार टन दे दिये। ये ६ हजार बराबर मिलते आ रहे हैं। उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है।

अब डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न है। पहले हमारे यहां हिन्दुस्तान के अन्दर थ्योरी थी, उसके ऊपर एक बेस मान कर रखा था, अलग अलग जिले के कोटा दिए थे, वह शायद सितम्बर या अक्टूबर की बात है। हमने एक आधार माना कि कौन से जिले में किस प्रकार का कन्ज़म्पशन है, बेस कितना रहा है; किस जिले के अन्दर शूगर के कितने डिब्बे जाते थे, किसी के अन्दर ५–५, तो किसी के अन्दर २ व किसी के अन्दर ४। उस बेस को हमने राजस्थान के अन्दर अनरिअलिस्टिक माना। उधर जनता की आवाज उठी कि गांवों और शहरों में भेदभाव क्यों ? मैं निवेदन करूं कि यह शूगर का प्रश्न ऐसा है कि बहुत बारीकी की नजर उस पर नहीं डाल सकते हैं। न इसको इन्कम के साथ जोड़ सकते हैं, न आदत के साथ और न गांव और शहर को ही बेस बना सकते हैं क्योंकि गांवों के अन्दर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां शहरों से भी ज्यादा शुगर खपाते हैं और कुछ ऐसे शहर भी हैं जो गांवों के बराबर भी नहीं हैं। तो हमें कोई वाया मीडिया वायबल हो तो उसे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

निकालना पड़ेगा। हमने हलवाइयों का भी ख्याल रखा क्योंकि लोगों में मिठाई खाने की आदत है, मुसीबत के वक्त भी जो हमारी आदतें हैं उनके बगैर नहीं रह सकते।

श्री भैरोसिंह : कुछ अपन को भी खाने की आदत है।

श्री नाथूलाल मिर्धा : इन सारी परिस्थितियों को देखकर कोटा को तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। गांवों की आबादी को ३,२०० टन और शहरों की आबादी को दो हजार टन और उसके बाद ६०० टन हलवाइयों, बेकरीज़, छोटे रेस्टोरेन्ट्स और होटल वालों के लिए इस प्रकार के कोटाज़ दिए। फिर पोपूलेशन के आधार पर कलेक्टर्स को अलॉट कर दिया और कह दिया कि इसी ब्रेक-अप के अनुसार ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज किया जाय।

गुड़ के बारे में इस प्रकार का निर्णय लिया कि उसको गांवों के लिए रखा जाय और शहरों के लिए नहीं। अब तक १०॥ हजार टन गुड़ राजस्थान में आया है वह गांवों के पास भेजा है। अलग अलग जिलों के अन्दर क्रय-विक्रय संघ के मार्फत गया था वह गांवों में पहुँचा है।

श्री केसरीसिंह (पाली) : यह जो कोटा आप डिवाइड कर रहे हैं, जो तीन हिस्से किये तो मेरा निवेदन है कि एक ऐसा कोटा रखें जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे खयाल से इतनी बारीकी में जाना संभव नहीं होगा। हमने कलेक्टर्स पर छोड़ रखा है।

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा (नसीराबाद) : इस विषय में मैंने प्रश्न उठाया था कि तीन वर्ष के यूनिट को छोड़ देते हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए जरूरत होती है। आप मेडीकल डिपार्टमेंट से पूछकर डिटेल्स....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे कहा कि डीटेल्स के अन्दर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों के जिस एज ग्रुप की बात आप करते हैं, कलेक्टर्स को हम सक्यूंलर भेज सकते हैं कि उनका ध्यान रख कर शक्कर दिया जाय, पर प्रश्न यह है कि इन सारी चीजों को एडजस्ट करने की जरूरत है। हम कलेक्टर्स पर ही छोड़ सकते हैं कि स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए डिमांड है उनका विशेष तौर से ध्यान रखा जाय। यदि माननीय सदस्यों की इस तरह की इच्छा है तो कलेक्टरों को हिदायत दी जायगी।

(११·२८ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह से बीच में बोलेंगे तो मेरी बात दो घण्टे में भी खत्म नहीं होगी। फिर मैं जरूरी बातें नहीं कह सकूंगा और आपको संतोष नहीं होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक जानकारी चाहता हूँ। आपने इस कोटा को तीन हिस्सों में बांट रखा है। भीलवाड़ा में यह हो रहा है कि रूरल एरिया का कोटा अरबन में चला जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यदि ऐसा होता है तो कलेक्टर गैर वाजिब काम करता है। उसकी शिकायत आने पर हम जरूर एक्शन लेंगे, सख्ती के साथ लेंगे। जो पॉलिसी डिसीज़न्स हैं उनके अन्दर यदि वैरिएशन्स होती हैं तो हम कार्यवाही करेंगे। यहां इम्प्लीमेंटेशन एज़ ए होल के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनके बारे में पॉलिसी डिसीज़न्स हैं उनको केरी आउट किया जाना चाहिये। हमने जो कुछ कोटा दे दिया है उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए।

गुड़ के बारे में थोड़ी सी बात कह दूं। गुड़ के बारे में स्थिति सुधरती जा रही है। कुछ तो यहां मेन्फेक्चर हुआ है और कुछ बाहर से आया है; हमारे यहां का कोटा भी बड़ा है। इस महीने में मैं दस हजार टन गुड़ मिला है। यह आगे तीस हजार तक हो जायगा। क्रय-विक्रय संघ को यह व्यवस्था देने के लिए एक पोलिसी के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। कई व्यापारियों ने निस्संदेह विश्वास दिलाया था और कहा था कि हम सस्ता लाकर बाजार को सप्लाई करेंगे लेकिन उनको हमने नहीं दिया और क्रय विक्रय संघ को यह दिया है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोत्साहित करना चाहते है। बाजार में सप्लाई करने का कोआपरेटिव के द्वारा यही अभिप्राय है कि कन्ज़्यूमर्स के पास आसानी से पहुंच जाय, ब्लेक न हो। एक व्यवस्था यह भी की है कि अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कलेटर्स या अन्य अधिकारियों के पास प्राइसेज फिक्स कराने के लिए जाना पड़ेगा जब कि पहले प्राइसेज़ फिक्स कराने के लिए जाना पड़ता था। सर्टेन प्राइसेज़ फिक्स चीजों की डिफाइन कर दी गई हैं कि जैसे ट्रान्स्पोर्ट चार्ज आदि। वे उन प्राइसेज़ में जोड़ दिये जावेंगे और जो इस हिसाब से रीज़नेबल प्राइसेज़ होती हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तय करके कन्ज़्यूमर्स को उन पर सप्लाई करें। प्राइसे फिक्सज़ करने के लिए कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों की जो इन्तजार करनी पड़ती थी अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। पहले प्राइसेज़ फिक्स कराने के लिए जाना पड़ता था इस कारण भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माल पड़ा रहता था। वह अब नहीं रहेगा और जो डिसीज़न लिया गया है उससे यह कठिनाई दूर हो जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इधर उधर से जो गुड़ आ रहा है तस्कर व्यापार के जरिये से. खास कर यू. पी. के बोर्डर से आ रहा है; उसके लिए सरकार की क्या पोलिसी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्टरनेशनल बोर्डर्स पर भी कई प्रकार की मशीनरी लगाने पर भी लूप होल्स रहते हैं; तो यह तो इन्टर-प्रोविन्शियल बाउन्डरीज़ का सवाल है। सरकार की निश्चित तौर पर यह पॉलिसी है कि आने देना नहीं चाहिए; सरकार की यह पोलिसी नहीं है कि चोरी से आने देना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल ; कागजों पर तो यह है, असल में है क्या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अमल में भी यही रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : गुड़ का भाव बढ़ जावेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : नेचुरल कॉन्सी-क्वेन्सेज से होगा तो फेस करना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तस्कर व्यापार से आता है तो उससे तो कोऑपरेटिव मूवमेन्ट फैल हो रहा है। सहकारी समितियां गुड़ उठाती नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: तस्कर से जो गुड़ आया है उसकी प्राइसेज़ बाजार में १ रु० ६ आना है जब कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ८० से ८५ नये पैसे प्रति किलो मिलता है। अभी काफी मार्जिन है। फैल होने की स्थिति न तो बनती है और न ही आने देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खेरथल और कामा की मंडियों में गुड़ तस्कर व्यापार होकर आ रहा है। क्या कदम उठाये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा ; हजारों कदम उठेंगे, आप देखिये तो सही। कदम उठाने का विचार कर लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : साथ हो उठेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, साथ ही उठेंगे।

मैंने आपको, गुड़ की प्राइसेज़ फिक्स करने के लिए जो इन्तजार करना पडता था वह अब नहीं करना पड़ेगा, यह बताया।

इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि क्रय-विक्रय संघ की फाइनेन्सेज़ की व्यवस्था को भी पूरा किया है ताकि वे माल उठा सकें।

ये बातें मैंने आपको कहीं। मैं सदन का थोड़ा अधिक समय ले रहा हूँ। कुछ इरिगेशन और दूसरे प्रश्न रह जाते हैं। उनकी ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान केनाल और गंग केनाल के पानी की परिस्थितियों के बारे में कहा।

श्री केसरीसिंह (पाली) : पैकेज प्रोग्राम के बारे में भी कह दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी मैं बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप टाइम की बात करते हैं !

श्री नाथूराम मिर्धा : अधिक टाइम भी मैं बैठ सकता हूँ आप लोग तैयार हों तो।

राजस्थान केनाल के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। फेमीन के लिए भी यह यह बड़ी बून साबित हो रही है। वहां पर ऊंटों के १॥ हजार छकड़े काम कर रहे हैं और लेबर लगा हुआ है। अगर दूसरी जगहों के ऊंटों के छकड़ों को प्रोत्साहन दें तो वहां बहुत आवश्यकता है उनकी। छकड़े वालों को दस-बीस रुपया रोज की आमदनी पड़ती है। यह राजस्थान का एक ट्रेक्टर उस कैनाल में बून साबित हो रहा है। जहां करोड़ों रुपयों की मशीनरी लगाने की बात सोचते थे और फिर भी उसको शिड्यूल्ड टाइम पर पूरा करने

Page No. 76

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की चिन्ता थी । इन छकड़ों वालों को काम मिला और जो पैसा है वह भी राजस्थान के लोगों को मिलेगा । ज्यादा से ज्यादा लोग छकड़े लेकर जावें और काम करें । माननीय सदस्यों को उन इलाकों से जाने के लिए कोशिश करनी चाहिये जहां से वे जा सकते है । उनको भी अच्छी कमाई होगी, अधिक छकड़े ले जावेंगे तो और हमारा भी काम अच्छा चलेगा और काफी हद तक काम जल्दी होगा ।

श्री भैरोंसिंह : उन छकड़ों के कारण राजस्थान कैनाल पर गधे आते थे उनके तो रोक लग गयी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : गधे भी काम पर आ रहे हैं । उनको भी काफी काम मिल रहा है । इसके साथ साथ यह है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहां तीन सौ से ऊपर काम पर आदमी आते हों, तो वहां पर चीप ग्रेन शोप न खोली गई हो, उसका वहां प्रबन्ध न हो । यह मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कहना चाहूँगा ।

एक बात मैं इस सम्बन्ध में कहना भूल गया था । माननीय सदस्यों की सूचना के लिए यह बता दूं कि एक लाख टन गेहूँ राजस्थान में मंगाने का प्रबन्ध कर लिया गया है । इस समय दो ढाई हजार चीप ग्रेन शोप्स काम कर रही हैं, उनको अधिक से अधिक खोलना चाहते हैं । रेड व्हीट या व्हाइट व्हीट जितना भी अवेलेबल होगा वह मंगाया जायगा । हम प्राइसेज़ को डाउन करने की कोशिश करेंगे । सरकार नेजो दूकानें खोलने का प्रबन्ध किया है उसका माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है । यह शिकायत है कि लोग अपने धान में चीप ग्रेन को मिला कर कभी बेचते हैं और कुछ देर के लिए रुक जाते हैं । यह इन्सान का स्वभाव है कि जब उसको मौका लगता है तो वह गुन्जाइश निकालने की कोशिश करता है । इन स्टेप्स के लिए जाने के कारण अब उन चीजों में कमी होगी और परिणाम हमारे सामने एक राहत के रूप में आवेगा । सप्लाई के इन्डेन्ट का प्रोसीजर भी इस तरह पर कर लेंगे कि एक लाख टन में से सब डिस्ट्रिक्ट पर रिज़र्व स्टाक बना लिया जाय । ५६ हजार टन हमारे डिस्ट्रिक्ट्स पर आज तक पहुंच चुका है यह मेरे पास सूचना आयी है । तेजी से काम करने के लिए मशीनरी सतर्क है । जिन जिलों पर पहुंचाने की कमियां हैं उनको दूर करके पहुंचा देंगे ।

राजस्थान कैनाल और नेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ बातें कही गईं । इस बारे में राज्य सरकार ने भारत सरकार के सामने और प्लानिंग कमीशन के सामने इस सारे मसले को रखा है । राजस्थान कि फाइनेन्शियल हालात को देखते हुए भारत सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने हमारे केस को असेस किया है । उसका फैसला करना भारत सरकार के हाथ में है । माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है उससे सरकार को बल मिलता है और इस प्रकार बल मिलने से कभी न कभी हम इसके फलीभूत होने की आशा कर सकते हैं ।

गंग केनाल और भाखरा केनाल के पानी का भी यहां जिक्र किया गया । कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिनकी वजह से पानी की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कम सप्लाई हो पायी है। राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जिनको हमने भारत सरकार के सामने फैसला करने के लिये रखा है। हमने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि आप इसमें हमारी मदद कीजिये। वे मसले चार-पांच हैं, जिनका मैं बजट के समय जिक्र करूंगा। हमने अपना दृष्टिकोण भारत सरकार के सामने रखा। पंजाब सरकार के दिमाग में, वहां के अधिकारियों के दिमाग में, वहां के लोगों के दिमाग में इसका रिएक्शन है, वे हमारे को पानी कम देते हैं, हमारे लिये परेशानियां खड़ी कर देते हैं, इस बारे में कन्ट्रोल हो वह ऐसे आदमी के हाथ में हो जो न्यूटरल हो; आज वह पंजाब सरकार के हाथ में है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप एक अजीब सी बात करते हैं, जब कि दोनों प्रान्तों की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है। दोनों एक विधान के नीचे काम करती हैं, दोनों जगह विधान सभायें हैं। इस मामले में हमें सीरियस होना चाहिये कि वे लोग हमारे साथ ऐसा क्यों बरताव करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेन्टर को हमने इसीलिये तो बीच में डाला है। हमारा जो कुछ फैसला होगा वह सेन्टर के द्वारा होगा। भारत सरकार बीच में रह कर फैसला करायेगी। इस सारे वाटर कन्ट्रोल के बारे में भारत सरकार से निवेदन किया है कि इसके लिये न्यूटरल एजेन्सी रहनी चाहिये, वे इस बारे में विचार करेंगे। भारत सरकार और पंजाब सरकार के मिनिस्टरों के बीच बातचीत चल रही है, उससे कुछ नतीजा निकलेगा। यह मैं मानता हूँ कि पानी की निश्चित रूप से कमी हुई। गंग केनाल में सप्लाई कम होने की वजह से निश्चित तौर से प्रोडक्शन पर असर पड़ा है, एकरेज प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। जहां से हम ३॥ लाख टन की अपेक्षा करके चलते थे वहां इस वर्ष २.२० लाख से ज्यादा नहीं पड़ेगा। क्योंकि सोइंग का सीज़न था उस समय पानी नहीं मिल पाया, और इस तरह से सारे रकबे को पानी नहीं मिल पाया। इस तरह से पानी की कमी की वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ। यह अलग बात है कि इससे दो-तीन करोड़ का नुकसान होगा ; या कम होगा इससे लैन्ड रेवेन्यू को लोस होगा आपके और हमारे टेन्टेटिव आंकड़े करीब करीब मिल जाते हैं। इस प्रकार हमें नुक्सान हुआ है, हम इस बारे में सतर्क हैं और जिस लेवल पर काम करने की आवश्यकता है भारत सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं। आखिर हम चाहते हैं कि किसी भी चीज का हल मिल-जुल कर शान्ति के तरीके से हो, वह हल हम निकालना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राज्य सरकार अपना कोई इन्जीनियर अपोइन्ट कर सकती है ताकि जहां से पानी का डिस्ट्रिब्यूशन होता है उसको वाच कर सके।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि एक अधिकारी जो सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर की रैंक का होगा वहां पर रहे और जो रोज गॉज रीडिंग होता है उस पर वाच रक्खे। यह फैसला कर चुके हैं, इसको तुरन्त इम्पलीमेंट करने वाले हैं।

घग्घर की फ्लड के बारे में भी बात कही

Page No. 78

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गई । रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने घग्घर फ्लड से होने वाले नुकसान के बारे में कहा कि जो वहां के लिये टेक्निकल स्कीम बनी थी वह ४॥ करोड़ रुपये की थी। उसको भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया है और उसको लौटा दिया है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि भारत सरकार और सी० पी० डब्लू. सी. ने हमारी इस सारी स्कीम को सही मान लिया है और इसको इम्प्लीमेंट करने की इजाजत भी दे दी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): क्या यह स्कीम टेक्निकल ग्राइडेन्स पर वापिस नहीं आयी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करूं, वापिस करने का सवाल नहीं, वह तो मन्जूर हो चुकी है । आपको यह गलत जानकारी है । वह स्कीम मन्जूर हो चुकी है और उस स्कीम का काम भी शुरू कर दिया है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तीसरी योजना के अन्दर घग्घर की जो योजना है उसको हम शत प्रतिशत पूर्ण कर देंगे और आशा है अगले साल के बजट में इसके लिये प्रोवीज़न भी रख देंगे ।

भरतपुर के फ्लड के बारे में भी जिक्र आया। कामा पहाड़ी पर काम चल रहा है । धौलपुर से जो कनेक्टेड इलाका है उसके लिये भी स्कीम बन चुकी है, सर्वे हो चुका है उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे । कामा पहाड़ी टाउन स्कीम १९६५ की बरसात के पहले पहले हम खत्म कर लेंगे ।

श्री रामकिशन (वैर) : फिर भी इस साल वर्षा में नुकसान होगा । जब कि बहुत अर्से से यह स्कीम चल रही है और आप ६५ में पूरा करेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे चार्ज लेने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ६५ की बरसात से पहले हम इसको खत्म कर देंगे । इससे जल्दी और क्या कर सकते हैं हैं ?

श्री रामकिशन : मंत्री तो बदलते रहते हैं, तो क्या उससे काम में भी फर्क पड़ता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मंत्री बदलते रहे हैं किन्तु गति आती है तभी आती है । इर्रिगेशन के बारे में जितने भी पोइन्ट्स उठाये गये हैं उनका मैंने जवाब देने का प्रयत्न किया है ।

इसके अतिरिक्त चम्बल क्षेत्र में जो वाटर लोगिंग होता है उसके बारे में भी बातें कही गईं, इसके लिए मैं निवेदन कर दूं; जिन जिन जिन क्षेत्रों में इस प्रकार से वाटर लोगिंग की समस्या है वहां से बेटरमेन्ट लेवी नहीं लेने का हमने फैसला कर लिया है । वाटर युटिलाइ–ज़ेशन पोटेन्शियल के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान का वाटर युटिलाइज़ेशन पोटेन्शियल जो क्रिएट हुआ है, उसका मैं सब मिलाकर बता सकता हूँ । चम्बल आदि सब क्षेत्रों का ६३–६४ का पोटेन्शियल इर्रिगेशन मेजर, माइनर, मीडियम से क्रिएट हुआ है उसका १०॥ लाख एकड़ का है; that will be about Nine and a half lakh acres. इससे मैं मानता हूँ चम्बल एरिया के लोगों को दिक्कत है, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस बारे में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सतर्क हैं। इसके लिए समय समय पर हम लोग आपस में मिलते हैं पन्द्रह बीस रोज में और इन परिस्थितियों पर विचार करते हैं। ये जो आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ उस हिसाब से पिछले साल की अपेक्षा इस साल उन आंकड़ों में कमी हुई है, पिछली साल जो ८०-८५ हजार था...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Out of......

श्री नाथूराम मिर्धा : Out of four and a half lakh. इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसमें कमी हुई है। हम इस बारे में सतर्क हैं और जितना करने की आवश्यकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस तरह से इर्रिगेशन के बारे में पोइन्ट्स थे उनकी मैंने जानकारी देने की कोशिश की।

फैंड्ड प्रोग्राम के बारे में चिन्ता जाहिर की गई। पाली में हमने फैंड्ड प्रोग्राम सिलेक्ट किया, इसके बारे में उनको ख्याल था कि गलती हुई। गलती नहीं हुई। हिन्दुस्तान में जब फैंड्ड प्रोग्राम आया तो सात जिलों में इसे बांटा गया। व्हीट का, पेडी का और मिलेटका फैंड्ड प्रोग्राम था। इनमें राजस्थान को कहा कि हमको वे मिलेट का दे सकते हैं। व्हीट का और पैडी का नहीं। तो मिलेट के के लिये स्थान की छानबीन की। इस दृष्टि से हमने पाली को चुना क्योंकि वहां कुए वगैरह व बान्ध भी थे। यह सब रेकॉर्ड में है। भारत सरकार ने हमारे इस सिलेक्शन को मंजूर किया। पर बाद में जाकर मिलेट की इम्पोर्टेन्स नहीं रही। जिस चीज का जितना प्रोडक्शन बढ़ा सकें बढ़ाया जावे, यह कहा गया।

तब प्रश्न हुआ कि पाली जिले में जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी नहीं हुई। इसका कारण पिछले सालों में बरसात की कमी रही। ६०-६१ में हालत अच्छी थी। फैंड्ड प्रोग्राम का भी एक तरीका है। इसमें कोऑपरेटिव्ज़ की बेस मजबूत बनानी होती है, फेमिली प्लानिंग भी करनी पड़ती है। पहले साल ४० पर्सेन्ट से ऊपर आंकड़े गये थे; पर दुर्भाग्य से बाद में बरसात के कम होने से और इसके कारण बांध में और कुओं में भी पानी की कमी आ जाने से पूरा लाभ नहीं हो सका और फैंड्ड प्रोग्राम नीचे गया।

अब हमने सारी हालतों पर फिर गौर करके यह किया है कि कुछ सिरोही का हिस्सा इसमें और जोड़ दिया है। यह अमेन्डमेन्ट किया है और पाली के इस क्षेत्र के कुछ हिस्से को एनीमल हस्बेन्डरी की तरफ से डेवलप करने की बात स्वीकार की है।

तो अनफोर्चुनेटली बरसात की कमी की वजह से जैसा परिणाम आना चाहिये वह नहीं आया। यह बात हमने भारत सरकार के मिनिस्टरों और अधिकारियों को भी समझा दी है और शिफ्ट करने की बात अब नहीं रह गई है, जैसा कि कहा गया कि भीलवाड़े में बदल रहे हैं।

यह बात नहीं है। बल्कि यह है कि भीलवाड़ा वगैरह और जगहों पर हम और चीजों के लिये तय कर रहे हैं। जैसे भीलवाड़ा में मूंगफली, ऑइल सीड, गंगानगर में कॉटन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सीड की अलग अलग क्रॉप्स के बारे में इन्टेन्सिव प्रोडक्शन के लिये चुना है और इसके साधनों को वहां विकसित किया जा रहा है।

सदन स्वीकार करेगा कि सदन की कृपा से ही, लोगों के सहयोग से ही राजस्थान का जो प्रोडक्शन टार्गेट था दूसरी योजना का उसे हम एक्सीड कर पाये हैं। तीसरी योजना के तीसरे साल भी लाइन पर चल रहे हैं। १६ लाख टन का एडीशनल प्रोडक्शन हमने सोचा है। आशा है, हम ज्यादा ही करेंगे।

आगे एनीमल हस्बेन्डरी के बारे में बातें कही गईं। पर चूंकि सदन का समय अधिक हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, उसके समय को ध्यान में रखते हुए इस पर आगे कहूँगा। जितना और बातों को खुलासा किया जा सकता था वह मैंने किया है। आशा है इसके बाद सदन धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करेगा। आशा करता हूँ कि डिस्कशन का हमारा आगे का ट्रैन्ड कॉन्क्रीट स्जेशन के रूप में चलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप १५–२० मिनिट में समाप्त कर देंगे, ऐसी आशा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस पार्टी का का।१घंटा है। काफी टाइम है। आपने शुरू में ही कहना आरम्भ कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो प्रार्थना करूंगा सभी सदस्यों से कि वे मुझे कह दें कि विशेष तौर से इजाजत है और मैं इसके पहले कि धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर आऊं मुझे ब्रिटेन के कोर्ट की एक कथा याद आ गई है, उसे कह देता हूँ। उस कथा में यह हुआ कि मजिस्ट्रेट के सामने जूरी बैठे थे।

श्री केसरीसिंह (पाली) : रिलेवेन्सी का ख्याल रक्खें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी बुद्धि को तो मैं पहले ही सलाम करता हूँ। आप शान्ति से सुनिये।

ब्रिटेन की एक कथा है कोर्टकी। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने केस आया। एक आदमी ने गधा चुराया था। सब जगह यह मशहूर था कि उसने गधा चुराया है। वह कोर्ट की डैक में घुसा। उसके घुसने के बाद वकील ने जिरह की। जूरी का वर्डिक्ट यह हो गया कि उसने गधा नहीं चुराया। मजिस्ट्रेट जो जानता था कि उसने चुराया है, पर जूरी के वर्डिक्ट के हिसाब से उस गधे के चोर को छोड़ दिया। छोड़ कर जब वह जाने लगा तो मजिस्ट्रेट ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारा तो फैसला हो गया, तुम्हें छोड़ दिया गया; पर असली बात तो बताओ कि क्या सचमुच में तुम गधा-चोर नहीं हो। उसने कहा कि हुजूर मैं आपके सामने क्या अर्ज करूं। कठघरे में जब घुसा तो चोर था। मेरे वकील ने जब जिरह शुरू की और पैरवी की तो मुझे शुबहा होने लगा कि मैंने कोई गधा चुराया है। और जब आपने छोड़

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दिया तो क्या बाकी रहा। मैं गधा-चोर नहीं हूँ।

यह कथा इसलिये कही है मैंने, कि तर्क का जो तरीका है वह किसी एक निश्चित तौर पर हो और जो आम जनता की आज राजस्थान में हालत है उस हालत से वाक्फियत रखते हुए इन्सानियत के साथ, जजबात के साथ विचार करें।

तो आज की परिस्थितियों के बारे में तो मैं अन्त में कहूँगा। पर आज जो अभाव और अकाल की सी परिस्थितियां हैं उनके राजनैतिक पहलुओं पर पहले बात कर लूं। उसमें भी एक बात कहना चाहूँगा। मैंने भी आपकी बातें सुनी हैं।

आज यूरोप और एशिया में दो ट्रेन्ड चल रहे हैं। एक तरफ डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप यानी अधिनायकवाद है। राज तो कोई न कोई रहेगा, चाहे इसे रखो या उसे रखो। समाज है तो राज होना लाजिमी है।

अब राज रहेगा तो राज में यह पसन्द करना है कि किस तरह की प्रणाली राज की हो। कुछ मुल्क पसन्द करते हैं डेमोक्रैसी को, कुछ करते हैं अधिनायकवादी तन्त्र को। यह पुरातनवाद है। तो स्थिति आज इस देश में हम देख रहे हैं कि दो विचारधाराएं बह रही हैं। हमने इस भाषण में एक ऐतिहासिक ऐलान किया कि हम किस तरह का राज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोकतन्त्र के आधार पर समाजवादी समाज का निर्माण करें। यह एक नया कदम हमने उठाया है और पहली मर्तबा हमारी सरकार की तरफ से इसको यहां पर कहा गया है। अब डेमोक्रेसी की एक कमजोरी है। यह दिमागी आजादी, विचार की स्वतन्त्रता की हामी है। इसलिये स्वतन्त्र पार्टी हो, कॉम्यूनिस्ट पार्टी हो, जनसंघ हो, कोई पार्टी हो उनको भी अपने विचार रखने की इसमें खुली छूट है। यह व्यवस्था हो इस देश में; इसके हम हामी हैं।

पर जहां तक उनका सम्बन्ध है जिनका जोड़ अधिनायकवाद से है और जो अपना दिमाग उधर लगाते हैं, ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें इनसे खतरा है। तो हम अपनी नाव इस तरह से चलावें कि इस अधिनायकवाद में हमारा देश न फंस जावें। हिन्दुस्तान में जनता मालिक है, जनतन्त्र में। जनतन्त्र में हमने अधिनायकवाद में विश्वास रखने वालों को भी विचार-स्वातन्त्र्य और विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता दे रखी है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं, प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर हमारे और हमारी सरकार के गलत कदम हुए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसका असर बुरा पड़ेगा, बोलने की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग होगा। अधिनायकवाद वालों को हम मौका देंगे जनता को गुमराह करने का। तो इसलिये हम कटिबद्ध हों सही कदम डालने के लिये और इस तरह से अधिनायकवाद को रोकने के लिये।

(१२·०० मध्यान्ह)

इसके साथ अभी एक मामला आया वह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लड़ाई के बारे में। एक अजीब विषय था वह क्या कि किसी ने पूछा कि तुम कितने भाई हो। उसने कहा हम दो भाई हैं। तो उसने कहा कि तुम ३ हो जाओ तो मेरा क्या कर लो। पहले वाले ने कहा कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते, हम तो हैं ही दो। उसने फिर कहा कि तीन हो जाओ तो मेरा क्या करलो। तो इस तरह का तर्क है। यहां पर महुआ कॉन्स्टीयूएन्सी की बात होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यहां पर अगर आप जीते हो तो जनसंघ से जीते हो। उस क्षेत्र से ३ दफा जनसंघ जीता है। आप कोई हमसे जीते हो ? हमने तो तुमसे यों ही रास्ते चलते ही बात कर ली। श्रीमन्, इन सारी चीजों को भूलिये। यह क्या कि जर्मनी की तोपों के अन्दर हम बांस डाल देंगे। अजीब बात है। जनाबवाला ! स्वतंत्र पार्टी वाले इसको सोचने की कोशिश करें। अगर कोई बात हो तो कहिये। हमने सिर्फ यह कोशिश की है और वह कामयाबी की कोशिश है। मैं बधाई देता हूँ हमारे सारे वर्कर्स को कि हमने इतनी टक्कर ली और वह टक्कर इस तरह की ली है कि जिसके अन्दर २ पर्सेन्ट से जीते हैं। यह हालत है। जो कॉन्सटीट्यूएन्सी आज १० साल से जनसंघ ले रहा था उसमें हमसे २ परसेन्ट से जीत कर आते हैं ! हम तो रास्ते चलते भिड़ गये आपसे। आपकी मक्खन पॉलिश शुरू हो गयी यहां पर। मैं, माननीय विरोधी दल के नेता हैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन अब की जिन भाषाओं का उपयोग और मिर्च लगाकर महार साहब ने किया मेरे मन में तो दुःख होता है, लेकिन साथ ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कॉंग्रेचुलेट किया जनसंघ को इस सदन में वह उचित नहीं था। झगड़ा न हो जाये इसलिए जनसंघ के पॉलिश करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि इनका जो सहयोग रहा हम उसके बड़े आभारी हैं और उसके लिए धन्य-वाद देने के लिए इस जगह को काम में लिया। आज सही स्थिति से लोग परिचित नहीं हैं। कहते हैं कि जनता की याददाश्त ज्यादा लम्बी नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि असेम्बली के सदस्यों की याददाश्त ज्यादा नहीं होती। आप ऐसा बड़े जोर से बोले कि हम कांग्रेस से जीते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप तो जनसंघ से जीते हैं। आपने जनसंघ को कैसे पटाया ? जनसंघ इसका जवाब देगा कि वे क्यों नहीं लड़े.......

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : यह फोड़तोड़ की आदत यहां भी काम में लेने लगे ! भाषण में भी जोड़तोड़ और फोड़तोड़ हो रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : श्रीमान्, मेरी फोड़तोड़ की आदत नहीं है। जब फोड़तोड़ होती है तो मैं भाग जाता हूँ। मुझे निकाल देते हैं लोग।

सही माने में कॉन्स्टीट्यूएन्सी वह कभी हमारी रही नहीं। वहां से पिछली दो बार से बराबर जनसंघ जीत कर आया है और उसके बाद में आप वहां से आये तो हम देखें कि कैसे खाली मैदान छोड़ें। आप क्या समझते हैं कि हमसे जीत गये ? ३ दफा जनसंघ वहां से जीता, तो यह तो उनकी हार हुई। इसको आप भी मानो, हम भी मानें। फिर २५७१ वोट की बात कह रहा हूँ। क्या जनता का इतना ही रिफ्लेक्शन है ? जिस कॉन्स्टीट्यूएन्सी से ३ दफा जनसंघ जीता वहां हम लड़े

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और फिर आप २५७१ वोट से जीत गये, यह तो पौने दो पर्सेन्ट भी नहीं पड़ता। इसके साथ कुछ और कहा गया कि हमारे मिनिस्टर वहां क्यों चले गये? जीत जाओ तो भी करप्शन और हार जाओ तो भी करप्शन। आपने तो वही मिसाल की कि 'चित भी मेरी पुट भी मेरी और अन्टा मेरा और मेरे बाप का।' अजीब दिमाग है! इस तरह का तर्क समझ में नहीं आता और आप कहें कि हमारे मिनिस्टर क्यों चले गये? आपकी जलन से हम समझ सकते हैं। लेकिन मुझे दुख और बात का है और इस सरकार से शिकायत है। शिकायत क्या है? मिनिस्टर गये, एक तो बेचारे वॉलन्टियर की तरह, कांग्रेस के सिपाहियों की तरह वहां पर गये; लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे पूरी इज्जत है रानी साहिबा की। वे कार्यकर्त्री अच्छी हैं। राजा साहब स्वतंत्र पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है एक बात का कि मुझे खबर मिली है कि वे रिक्रूटमेन्ट के कोई ऑफीसर अपोइन्टेड हैं, उसकी वर्दी पहिन कर वे वहां पर गये, उस कॉन्सटीट्यून्सी में। अगर गलत हो तो मुझे कहें; वे वर्दी के अन्दर गये या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : वे वर्दी में ही नहीं बल्कि उस मोटर में गये जिसमें सितारा लगा हुआ था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो यह बतायें कि वे वर्दी के अन्दर गये या नहीं?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं यह कहता हूँ कि तुम बबूल बोओगे तो आम कहां से खाओगे?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमने तो पहले भी बबूल बोए तो कांटे निकले।

श्रीमान्, यह राजस्थान की बात है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था; और भी इस सिलसिले में आगे चलूं। फॉरिन पॉलिसी नेशन की पॉलिसी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस डेमोक्रेसी को खतरा है इस बात से। आपका भी राज्य बनेगा। हमारी फॉरिन पॉलिसी हर मुल्क के साथ वैसी की वैसी ही स्टेन्ड करेगी। चाहे जैसी गवर्नमेंट हो हर हुकूमत में यही होता है कि हमारी पॉलिसी उन देशों के साथ एक जैसी है। लेकिन यहां स्वतंत्र पार्टी एक गलत तरीका निकाल रही है। मुझे दुख है कि यह फॉरिन पॉलिसी के ऊपर यहां से कन्वेन्शन होता है ऑल इन्डिया की स्वतंत्र पार्टी का कन्वेन्शन होता है उसके अन्दर यह कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के अन्दर जो माइनोरिटी, हिन्दुओं को काटा गया उसके ऊपर कोई प्रस्ताव पास करने की हिम्मत नहीं होती, उस ऑल इन्डिया कन्वेन्शन के अन्दर। यह कहते हैं कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन्स होने चाहिए! जब आपका राज्य आये तो उसको भाई, काका बना लेना। सवाल यह है कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिये। दूसरे कहां घसीटना चाहते हैं, एक ही कैरेक्टर है इन सब बातों का और उसका खतरा है सरकार को और यह अधिनायकवादी पार्टी चाहे स्वतंत्र पार्टी हो या दूसरी हो, ये फासिस्ट ताकतें जो आजादी दिमाग में है इस मुल्क के लोगों में पोइज़न करने का और हुकूमत को बदलने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के भाग्य से आज परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गयीं और मुल्क के अन्दर जिस प्रकार की स्थिति हो रही

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है उसके अन्दर गरीबी, अकाल, चीजों की कमी वे आज जो तकरीरें यहां होती हैं उनका असर होता है। उनका असर यह होता है कि कोई जल जाये तो नमक लगाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी सरकार की और भी ज्यादा जिम्मेदारियां इस सिलसिले की बढ़ती जा रही हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : भंग की गोली तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अफीम की गोली होगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अफीम की गोली अफीमचियों को मिलती रहती है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कौल साहब के यहां से चुराई हुई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां गवर्नर साहब को पानी पीने को मिल सकता है, मुझे पानी भी नहीं है।

"जो जानवर को देते हैं पानी पिला, इन्सान हजरते को पानी पिलाना है मना यहां"।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह आपके ही राज में हो रहा है सब कुछ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी तबीयत जरा खराब थी।

श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिए पानी का इन्तजाम हो जाय, नहीं तो आपको गश आ जायेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इस मसले को यहीं छोड़ देता हूँ। महुआ की बात नहीं रही, दूसरी बातें नहीं रहीं। अब मैं अपने मसले पर आता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो अजमेर जा ओ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आना तो जयपुर चाहता हूं और आप अजमेर भेजना चाहते हैं। मैं तो जयपुर ही आऊंगा और आपको कहीं और जाना पड़ेगा। यह जो भाषण हुआ है इस भाषण में एक खूबी है और वह यह है कि इसको गौर से पढ़ा जाय तो जिन स्थितियों से राजस्थान निकल रहा है और इस पर जो पेचमेंट लगे हुए हैं वह सच्चाई के साथ लगाये हैं। इसमें कहा गया है, इसमें साफ तौर से कहा है, ईमानदारी से। इसमें छिपाई कौन सी बात है। इसमें कहा है, "इन सालों में बड़ा दुःख रहा है। परिस्थितियों के कारण इस वर्ष काफी असुविधाएं उठानी पड़ी हैं।"

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Point of order, Sir, माननीय सदस्य को पानी की आवश्यकता है तो पानी का प्रबन्ध होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक इस सदन की यह परम्परा नहीं रही है कि भाषणों के बीच में पानी दिया जाय।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): आपकी इजाजत से, अगर कोई माननीय सदस्य बीमार हो तो उसको दे सकते हैं। इसमें कोई परम्परा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी कोई परम्परा मानवता से परे नहीं है, कोई रूल में ऐसी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर सदन को कोई एतराज नहीं हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री) : भूतपूर्व होम मिनिस्टर, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त को भी हाउस में बैठकर बोलने की इजाजत दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member can have water.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : धन्यवाद । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था इस सिलसिले में कि (श्री हरदत्तसिंह से) आपको भी धन्यवाद । हमने आस्थाएं की हैं उन आस्थाओं को रियलाइज़ करने के लिए जो स्थितियां पैदा हो रही हैं वे स्थितियां इस तरह की हैं और उस वजह से इस कांग्रेस की जिम्मेदारी और भी बढ़ी हैं, और इस बढ़ने के साथ यह देखना होगा कि हस दायरे में हमने क्या किया है । मैं अगर साफ कहूँ तो गलत फहमी नहीं है । मैं सरकार को इस कन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूँ कि इन बड़ी जिम्मेदारियों के साथ इस सरकार के ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आई है "कि तेरी गठरी में लागा चोर....''; यह एक सिनेमा का गाना था । आज हमारे पीछे लग गये हैं लोग । तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है । उसके कन्टेक्स्ट में हमने ऐलान किया है अपनी आस्थाओं का । मैं आपकी तरफ से आपके मार्फत उनको कहना चाहता हूँ कि इस डेमोक्रेसी की रक्षा करने की बात निश्चित है और गरीबी से लड़ने के लिए समाजवाद की स्थापना करें । इस ऐलान के बाद यह और जरूरी हो जाता है कि जिन हालतों में जो प्रचार हो रहा है, जो ट्रेन्ड बढ़ रहा है, उनको रोकने के लिए सही तौर से प्रयत्न करें । उन प्रयत्नों में कहता हूँ कि हम जो विधायक हैं हम अपनी तरफ देखें । वहां पर गलतफहमी की बात न हो । हम विधायक हैं और हमने अपने विधाता, अपने नेता को चुना है । उस नेता के रूप में ब्रह्मा दिया है सरकार ने, वह आपके सामने मौजूद हैं। मैं करप्शन की बात करूं उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस ट्रेन्ड को अगर रोकना है तो मैं इस सरकार से साफ कहता हूँ कि इस सरकार को एफिशियेन्टली चलना पड़ेगा । आपने जो तैयारी की है उसके लिए कहता हूँ । क्या करप्शन है या नहीं, इसके ऊपर लोगों का दृष्टिकोण बहुत निश्चित है, लेकिन डेमोक्रेसी कानून को नहीं नैतिकता की डेमोक्रेसी हो जाती है । जहाँ प्रोफ्यूमो ने एक गलत बात कही, जहां एक शब्द गलत निकल जाय, एक आदमी बगैर पूछे उसकी मोटर ले जाय सरकारी, तो उसके ऊपर इंग्लैण्ड में इस डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, जनता के सोचने और बोलने की आजादी की रक्षा के लिए वहां पर मिनिस्टर्स ये कुर्बानियां करते हैं । एक छोटी सी गलत बात जाने-अनजाने में निकल जाय तो गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों की आम जनता के बोलने और सोचने की आजादी को कायम रखना है, उसके लिए कुर्बानी करते हैं; एक मिनिस्ट्री नहीं, १० मिनिस्ट्री कुर्बान कर देते हैं; लेकिन यहां पर जवाब देने की बात करते हैं तो इधर–उधर बगलें झांक कर निकलना चाहते हैं । यह गलत है । सही बात यह है कि सदन सारा बैठा है, जो कम्प्लीट गवर्नमेंट बैठी है ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

विधायक आपको और हमको कहते हैं तो हमें कोई कानून आता है क्या, विधायक का कानून बनाना ही अगर काम होता तो हम वकीलों को यहां चुन देते । हमारा काम यही नहीं कि हम विधायक ही हों । इसके बाद विधेयक जो बनाये हैं सरकार ने, जो यहां बैठी है वे लागू कैसे हो रहे हैं ? हम अपनी कॉन्स्टीट्यून्सी में जाते हैं तो वहां, यह किस तरह से चल रहे हैं, यह देखने का कर्त्तव्य भी हमारा है । इसीलिए हम विधायक कहलाते हैं । विधायक हुए तो बड़े पंडित हो गये कानूनों के ! उन कानूनों की बहस में हिस्सा लेकर सुधार की बात करते हैं, बल्कि हम यहां निगहबान हैं कि हर आदमी पर यह कानून कैसे लागू करते हैं । जिन्होंने हमको चुना है उन पर यह कानून लागू किये जाते हैं । वहां जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि क्या पास कर आये थे और क्या चल रहा है । आप इस तरह से चलाइये कि यहां पर जो पास करते हैं और हमारी आकांक्षायें और ध्येय हैं उनके मुताबिक सरकार ने जो कानून बनाया है वह वहां चले । लेकिन इस सदन के बारे में आप निर्णय लेते हैं कि चार सेशन्स बुलाये जायेंगे अब और सेशन्स दो ही होते हैं । ऑर्डिनेन्स से हुकूमत चलाई जाती है । पिछले साल ७ ऑर्डिनेन्स निकाले । ऑर्डिनेन्स उस जगह पर निकाले जाते हैं जहां कि गवर्नमेंट फैल हो रही हो । उसी वक्त ही इनका उपयोग होना चाहिए ।

अंग्रेजों के समय में ११–१२ साल जैल में रहा हूँ । जब कांग्रेस फाइट कर रही थी उस वक्त कितने ऑर्डिनेन्स अपनी हिस्ट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाले थे, वह ऑटोक्रेट गवर्नमेंट थी । उसने कितने ऑर्डिनेन्स निकाले ? जब ऑर्डिनेन्स निकाले तो काले झण्डे बताये कि काला कानून निकाला है । असेम्बली को चार दफा बुलाने का था तो क्या ऐसा क्राइसिस आ गया कि असेम्बली को नहीं बुलायें और डेमोक्रेसी को गर्क करें, आज के दिन के अन्दर जब कि अधिनायकवादी शक्तियां, जब कि अभाव और कमियां हैं उस वक्त सरकार को कभी भी डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिए ऑर्डिनेन्स नहीं निकालने चाहिए । ऑर्डिनेन्स का राज्य, डेमोक्रेसी का राज्य किसी जगह भी नहीं कहला सकता । ७ ऑर्डिनेन्स किन किन बातों के हैं । उन ऑर्डिनेन्स के मैं नाम बतलाऊं । उनकी इम्पोर्टेन्स देखिये । ये लोग कहते हैं कि इसमें क्या करना, एक ऑर्डिनेन्स निकाल देंगे । कोई भी आकर कहता है तो ऑर्डिनेन्स निकाल दिया । दस्तखत हो जाते हैं । उसका क्या कन्टेन्शन लेते हैं । इस तरह से आप प्रिसिडेन्स पैदा करना चाहते हैं ।

यह तो बदलता जायगा, बदलता रहेगा डेमोक्रेसी रहेगी, मेरा यह पक्का विश्वास है । और कांग्रेस । कांग्रेस को जब आप कहते हो तो मेरे को लगती है । कांग्रेस मुल्क की एस्पिरेशन का नाम है, मुल्क की आकांक्षा का नाम है । उसके पीछे लाखों आदमी इधर बैठे हुए और उधर बैठे हुओं का नाम है । जिन्होंने देश को आजाद कराया उनमें जवाहरलाल और गांधीजी का नाम है । कांग्रेस का नाम लेने से कितनी ही चीजें दिमाग में आती हैं ।

सन् ४२ में अंग्रेजों ने मासूम बच्चों को संगीनों पर ले लिया था, वे चीजें दिमाग में आती हैं । कांग्रेस के झंडे के नीचे आपने

Page No. 87

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आजादी हासिल की और आज आप क्या करते हैं ? "कांग्रेस कांग्रेस" करते हैं ! तुम्हें कहना हो तो ठीक तरह से कहो । किसी मंदिर में पुजारी गड़बड़ करता है, कोई महंत गड़बड़ करता है और तुम्हारी उससे नहीं बनती तो उस महंत और पुजारी को जो चाहे कहो, लेकिन तुम मूर्त्तियों को गाली देते हो, देवताओं को गाली देते हो ! जो मुल्क उनको गाली देता है वह मुल्क खड़ा नहीं रहेगा । कांग्रेस के लिए, उसके साथ आपकी आत्मा रहेगी, आपके बाप की आत्मा में कांग्रेस रहेगी, आपके बच्चों की आत्मा में कांग्रेस रहेगी । तो यह ऑर्डिनेन्स निकालने की बात गलत है । ऑर्डिनेन्स में क्या है ? हमने डिक्लेयर किया कि हमें समाजवाद के सिद्धांत को जिन्दा करना है, इस सिद्धांत को डेमोक्रेसी में लाना है । अभी मामला आया, हमने पास किया........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक शब्द का उपयोग किया है, वह बेजा है । हमारे लिए तो जो कुछ कहो उसको सुनने के लिये हम तैयार हैं, लेकिन हमारे बाप को यहां घसीट कर लाना उपयुक्त नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बच्चे थे तब मैं जेल काट रहा था........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभी मेम्बर्स के बाप के लिए कहना उचित नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप गलत समझ गये, किसी को बुरा नहीं लगा........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं असल की औलाद हूँ इसलिये मुझे बुरा लगता है; नकली की औलाद को बुरा नहीं लगे इसलिए इस पर आपका रूलिंग होना चाहिये कि या तो ये इस शब्द को वापिस लें या इसको कार्यवाही में से निकाला जाय । हमारे बाप को यहां नहीं घसीटें ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप कांग्रेस के साथ थे, तब आपको बुरा नहीं लगता था ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अच्छा साहब आपको खुश करने के लिये........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप प्रारम्भ करें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कभी यह मकसद नहीं था, मैं आपके सामने कह रहा था देखिये यहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स है........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए रूलिंग दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि एक तरफ किसानों पर हमने टैक्स लगाया । हमने यहां पास किया सरचार्ज अंडर ५०) रुपये । उसका इन्टरप्रिटेशन किसानों पर जो तय किया डिपार्टमेंट ने वह सुन लीजिये । किसानों पर जो सरचार्ज लगाया उसका इन्टरप्रिटेशन रिजिड हो, यह इच्छा हमारी नहीं थी इस सदन में । क्योंकि हमारा काम है, कैसे लागू होता है, यह भी देखना । हमने कहा यदि जोत का कुआ है

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और नदी आ रही है और एक जगह वहां पर सब फेमिलीज़ हैं उनको यदि ६०) देने पड़ते हैं तो उसका बंटवारा नहीं किया और जोइन्ट मानकर ५०) रुपये से ज्यादा मान लिया, जो किसान हिस्सा लेता है उसको मान लिया और १०, २०, ५० वर्षों से अलग-अलग जमीन की लगान देते हैं उसको जोइंट मानकर ५०) रु० में उसको शामिल कर लिया। हमारी मंशा ऐसी कभी नहीं थी, जैसा आप सोच रहे हैं। यदि आप जल्दी असेम्बली बुलाते तो मुमकिन है किसान इससे बच जाते, आज उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है उससे वे बच जाते। और दूसरी तरफ आपने क्या किया ? मैं चिल्लाया, चीखा, बहुत चीखा सदन के सामने कि डिस्क्रीशनरी पॉवर फाइनेन्स के मामले में देना गलत है। पहले जो डिस्क्रीशन दिया था उस पर भी आपको गर्व है, उस समय फाइनेन्स मिनिस्टर थे हरिभाऊ जी। ऊन के व्यापारियों से उन्होंने कह दिया कि समझौता करके २ लाख में ले जाओ। इस पर हम चिल्लाये और उनसे बात हुई तो कहा कि गलत असर नहीं पड़ेगा। कुछ और जोरों से बातें हुईं तो वह समझौता नहीं हुआ और ६ लाख रुपयों की आमदनी हुई। हम कहते हैं इस असेम्बली में आपके जरिये कि इस सदन ने ६ लाख रुपये एक्सचेकर को दिलाये नहीं तो २ लाख रुपये ही आकर रह जाते। इसलिये मैं कहता हूँ डिस्क्रीशन देना गलत है।

आपने पहले एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स सिनेमाओं की कुर्सियों पर लगाये। सिनेमा वालों का डेपुटेशन आपके पास आया। आपसे उद्घाटन कराया, तब आपने कह दिया कि यह टैक्स कम कर दो। अब आपने एग्ज़ीबिशन पर टैक्स लगाया, किसानों पर टैक्स लगाया। इनकी आमदनी कितनी है, किसानों के साथ यह व्यवहार आपका और दूसरी ओर सिनेमा वाले करोड़पतियों और लखपतियों के साथ यह व्यवहार रहता है आपका। जहां बम्बई में आपका स्वागत होता है तो आप कहते हैं कि इसको रिलेक्स कर दो। मैंने जब कहा कि कम्प्रशन हुआ तो मेरे कहने से मिलने मेरे से थोड़े ही आये। जिनके पास (अश्रव्य) है उनके पास आते हैं, आपके सामने आकर कहते हैं और वह भी साधारण ढंग से नहीं, उनकी बात मंजूर हो गई। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि किसानों के लिए ऑर्डिनेन्स निकाला जाता है।

बम्बई में एग्ज़ीबिशन वालों की तरफ से स्वागत होता है, कई रिश्तेदारों की एजेन्सी वाले सहायता करते हैं और उसके बाद ऑर्डिनेन्स निकालना! एसेम्बली को चार दफा नहीं बुलाना, शुरू में जब रिलेक्सेशन देने के लिये एग्ज़ीबिशन के ऊपर जब मैं चिल्लाकर कह रहा था सदन में, पार्टी में कि ३० लाख में से ३ लाख नहीं आयेंगे, तब नहीं माने। जब लोग आपके पास आते हैं और आने के बाद एग्ज़ीबिशन में कम क्यों नहीं करते, क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं थी इसलिये ऑर्डिनेन्स निकाल कर रिलेक्सेशन किया। लाखों रुपये बसेज़ के लोगों में बाकी पड़े हैं, वे रियलाइज़ नहीं होते हैं, वहां सौदा करते हैं, पैसे वाले वहां कहते हैं इधर दोगे तो उधर लोगे। पैसा तो बहुतसा पड़ा है लोगों से वसूल करने के लिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और भी बातें बताऊंगा। राजस्थान चैम्बर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ऑफ कॉमर्स नाम की जो संस्था है पैसे वालों की, लखपतियों और करोड़पतियों की उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आप जमीन देते हैं। क्या वे भूखे और नंगे हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं है जो आप उनको इस तरह की जमीन देते हैं ? मेरे ख्याल से वह ५० लाख रुपयों की जमीन होगी। इस तरह के काम करने से समाजवाद की प्रगति कैसे होगी ? उनसे कह दिया कि कह देना इन्डस्ट्रियल एग्जीबिशन रखेंगे। इन्डस्ट्रियल एग्ज़ीबिशन तो एक कमरे में रखोगे और सारी जमीन के मालिक तुम बनोगे। आज आप वह जमीन मुझे दे दीजिये, मैं चन्दा करके १०० एम. एल. एज़. को बसा दूंगा, उस पर इसकी सारी व्यवस्था मैं करूंगा।

पैसे वालों को पैसा लेकर दे दो, जमीन की बोली लगा कर दे दो। लेकिन ऐसी बात नहीं की। कहा–नहीं, ले जाओ; ले जाओ। तुम उद्घाटन करो। ये सारी बातें मैंने आपको कहीं, ये मैंने एक-दो मिसालें बताईं और इनके द्वारा आपको वार्निंग दी है। ऐसी बातों से अधिनायकवादी पार्टियां फायदा उठाती हैं। आप क्यों नहीं सफाई दे देते ? आप सफाई दे दो और सफाई देकर मुझे मौका दे दो तो मैं अच्छी तरह इन्हें सफाई दे दूं। आम जनता में ये इन बातों का प्रचार करते हैं। ये कहते हैं, "ये कैसे समाजवाद लायेंगे ? हम राजा अच्छे हैं, हमारी डिक्टेटरशिप अच्छी है, प्रोलिटरेट डिक्टेटरशिप अच्छी है।" आप इन्हें मौका मत दो। इनका मुंह बन्द करो। इन बातों को साफ करो। ये इन बातों की चर्चा करते हैं।

श्रीमन्, इसके बाद पुलिस....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्री महोदय पौने दो घंटे बोले उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हुई घंटी बजाने की। ये लोग नहीं चाहेंगे सुनना, उस वक्त मैं खुद छोड़ दूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : सुनना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऊपर वाले यह नहीं सुनते हैं और इनकी बात आपकी बात नहीं सुनते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कौन, काजी या मुल्ला ?

इसके बाद डाकुओं की बात आती है ...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके बाद मैं डाकुओं की बात पर आता हूँ। हम मानते हैं, यह बात जरूर है कि यहां लॉ एण्ड व्यवस्था है। लेकिन मुझे अफसोस होता है, आप जनता का माइन्ड साफ नहीं करते हैं।। जनता से हमारा सीधा सम्पर्क है डेमोक्रेसी में। मैं इस बात पर ऑब्जेक्ट करता हूँ कि डाकुओं का नाम लिख दें, डाकुओं को हिस्टोरिकल बना देना ठीक नहीं। दूसरे स्थानों पर जिसने समाज का शोषण किया है उसका नाम लिया जाय, यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी व्यवस्था की जायगी...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां। सवाल यह है कि डाकुओं के गिरोह के सरदार का, जगमाल का नाम डॉक्यूमेंट में नहीं आना चाहिए।

यह तो मैंने विशेष बात कही लेकिन इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूँ और इसका उल्लेख करता हूं कि हम जनतंत्र के अन्दर विचार रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र की सुरक्षा करने के लिए काम भी हो रहा है। लेकिन ये सारी समस्यायें हैं इनको मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि पुलिस द्वारा दो करोड़ आदमियों का इन्तजाम करना पड़े और इसके लिए सारी पुलिस को हम कन्डेम कर दें–यह बात ठीक नहीं है। साथ ही उसको खुला छोड़ देंगे तो यह सरकार कोई भगवान नहीं है कि वह वहां की वहां संभाल दे। इसलिए हमें कानून का राज्य करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से हम जब कुछ बातों पर रोशनी डालते हैं और उनकी जांच करने के लिए कहते हैं तो जो जाच होती है उसकी रिपोर्ट का यहां उल्लेख नहीं होता है। इधर से और उधर से जनता में प्रजातंत्र के प्रति विश्वास रखने के लिए और गलत कार्यवाहियों पर एक्शन लेकर उनको रोकने के लिए कई बातें कही गईं और पिछली साल कितनी ही बातों की चर्चा हुई, विरोधियों द्वारा जमीन की चर्चा हुई कि फलां आदमी ने यह जमीन ले ली, फलां आदमी ने वह जमीन ले ली, कई करप्शन की बातों की चर्चा हुई और उसके साथ ही कुछ फाइलों की बात हुई ! आप फाइल नहीं रखते हैं। अरे, फाइल क्यों नहीं रखते हैं। आप कहते हैं कि यह जो है 'not in the public interest', I challenge it. यह कहना शर्म की बात है। It may not be in his interest, but it is wrong to say that it is not in public interest. Public interest is defined in the Act. Public interest is only when security is involved.

इस असेम्बली से कोई चीज दूर नहीं रख सकते। जिस फाइल को रखने के लिए कहते हैं उसको रखने से नहीं रोक सकते। आपको उस सच्चाई को यहां लाना पड़ेगा। आप कहते हैं, पब्लिक इन्ट्रेस्ट में फाइल नहीं दिखा सकते, फाइल नहीं रखते–इसको यह सदन बर्दाश्त करे, यह गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अन्दर जितने सदस्य हैं वे अगर कोई फाइल चाहते है तो उसको रखना पड़ेगा। आप फाइल रख देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी हो जाती है और हमें मालूम हो जाय सच्चाई तो जनता को भी मालूम हो जाती है। लेकिन आप फाइल नहीं रखते हैं। जैसे कोई डाका पड़ जायगा या आसमान फट जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सच्चाई को छिपा कर नहीं रख सकते, सच्चाई को नहीं रोक सकते। यह गवर्नमेंट बैठी है, इसको कहा कि फाइल रख दो, तो कहते हैं फाइल नहीं रखेंगे। कहा जाता है पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं रखेंगे ! पब्लिक इन्ट्रेस्ट की डेफीनिशन डिफाइन्ड है। What is public interest ? यह डिफाइन्ड है।

तो, श्रीमन्, यह बहुत गलत बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं अब पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात नहीं कहता।

अब मैं आपके सामने एक बात रखूं कि जहां तक अकाल हमारे यहां पड़ने का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सवाल है, अकाल के बारे में, श्रीमन् , जिन स्थितियों में यहां पर सदन में चर्चा हुई है– उनसे वातावरण नहीं बना है। मैं आपके सामने वातावरण बनाना चाहता हूं। मैं आपकी कल्पना को वहां ले जाना चाहता हूं जहां गरीब अपने सामान को पीठ पर लादे हुए, अपने बच्चों को लिये, अपने पशुओं को लिये हुए एक फौज की फौज के रूप में, एक लम्बी लकीर की लकीर के रूप में अपने गांवों को छोड़ कर भीलवाड़ा और विजयनगर की सड़कों पर जाते हुए दिखते हैं। वे हमारे भाई हैं और साथ ही साथ वे इन्सान हैं जो हमारे लिए अनाज पैदा करने वाले हैं, हमको चुनने वाले हैं और अपने पौने दो दिन खत्म करके वोट देने वाले हैं। अपने गांवों को छोड़ कर, राजस्थान को छोड़ कर जाते हैं....

(हंसी)

आप हंस सकते हैं। तुम्हें हंसी आ सकती है। जब जब यहां बातें हुई हैं, जनता की लाश की और अकाल की तो आप रोटियां खाना चाहते हो। मैं भयंकर अकाल की बात कहता हूं तो आपको हंसी आती है। आप हंसिये, मैं आपकी हंसी जनता को दिखाना चाहता हूं। आपको यह पता चले कि जनता आपको देखती है। आप कहते हैं, यह सरकार कुछ नहीं कर रही है और आप अकाल की बात पर दन-दन करते हैं, हंसते हैं...

श्री रामकिशन (वैर) : यह क्या हुआ ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको कहता हूं, सदन को पूरी तरह से यह ध्यान में रखना चाहिए, यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम उनके पास होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह भगवान की कुदरत है, तो हमें कम से कम सहानुभूति उनके साथ होनी चाहिए। हमें हंसना नहीं चाहिए। हम उनके रिप्रज़ेंटेटिव कहलाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इस बात पर क्यों बजा रहे हैं। तो, श्रीमन् , इस तरह की बात सारे हिन्दुस्तान में है, राजस्थान में नहीं है। सभी जगह परिस्थितियां ऐसी हैं। यह सही है कि जितने गरीब लोग हैं उनके आप ने पांच रुपये बढ़ा दिये। पांच रुपये कर देने के साथ ही आप अपने स्टेटमेंट में इस बात को मानते हैं कि यह बढ़ोत्तरी कीमतों के लिहाज से नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि आप नाकारा हैं क्योंकि वह आपसे पांच रुपये नहीं मांगता। वह आपके पास रोजगार पर आता है तो इसलिए नहीं आता कि वह रोटी नहीं खाता है, चांदी खाता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप रुपया देते हैं वह उसके घर में नहीं पहुँचता है। आप कल्पना कीजिये, जब एक चपरासी, एक सिपाही, एक फोर्थ क्लास सर्वेन्ट घर को जाता है तो घर में एक तबाही मची हुई होती है, बच्चों और बीबी की जो हालत है वह देख नहीं सकता। उसके बाद उसको काम करना पड़ता है। आप मानते हैं कि मंहगाई बढ़ी है। आप खुद मानते हैं, लेकिन जो आपको अपना माई-बाप, पालनहार समझते हैं, जो आपके आश्रित हैं, जो आपके बच्चों से

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ज्यादा आश्रित हैं–वे गरीब लोग हैं, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं लेकिन उस माफिक आप उन्हें इन्साफ नहीं देते हैं। आप दो करोड़ एमर्जेन्सी में खर्च कर सकते हैं लेकिन वह दो करोड़ रुपया इनको नहीं दे सकते जिससे वे रोटी खा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन सब बातों के लिए बहस हो सकती है, लेकिन इनके लिए बहस नहीं हो सकती।

अब एक बात और कहना चाहता हूं। यह बात कह कर मैं आपका आदेश मान लूंगा। सर्विसेज़ और राजा–मैं पुराने राजाओं की बात कह रहा हूं। आज तो वे बहुत गरीब हैं–ये स्तम्भ थे अंग्रेजों के, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को गिअर-अप रखने के लिए इनका ऑर्गेनाइज़ेशन हुआ था, जिससे अंग्रेजों और पब्लिक के बीच में यह नेगोशियेन्स करा सकें। जब अंग्रेज यहां से छोड़ कर चले तो इन दोनों ने कहा–हमारा क्या होगा ? उन्होंने कहा, तुम्हारे आकाजी तुम्हारे लिए लिख कर जाते हैं। और क्या हुआ, इतिहास साक्षी है, कि इन्होंने अपना क्लेम किया। उस वक्त जो राजकर्त्ता थे, उन्होंने स्थिति को देखते हुए कहा कि इन दोनों क्लास को तकलीफ नहीं होगी, इनको हम आराम से रखेंगे। राजाओं को कुछ प्रिवी पर्स देकर रख दिया और इनके लिए कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोवीज़न रखा है। लेकिन यह तथ्य है कि ये दोनों बने थे देश को गुलाम रखने के लिए। यह क्लास आजादी को बनाये रखने के लिए और विकास करने के लिए नहीं बनी थी, इसलिए यह क्लास देश को आजाद रखते हुए विकास की ओर नहीं ले जा सकती। यह मशीनरी अपनी जगह बनी रही। राजाओं को तो केप्चर कर लिया कुछ पैसा देकर और उन्हें निकाल दिया। आज इनको प्रोटेक्शन है। लेकिन यह मशीनरी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए नहीं थी, यह अंग्रेजों का राज्य कायम करने के लिए थी। यह अंग्रेजों का राज्य कायम रखने के लिये थी। आज राजा महाराजा नहीं रहे, मगर यह जो मशीनरी है उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो जिन कानूनों को हम जनता की भलाई के लिये बनाते हैं उनका अमल नहीं हो पाएगा क्योंकि इस मशीनरी में जब हम ठीक तरह काम करने के लिये ग्रीस डालते हैं तो इस मशीनरी का गीयर ही उल्टा चलने लग जाता है। ये लोग तो समझ ही नहीं सकते। कोई भी कानून मजदूरों और दूकानों पर काम करने वालों के लिये क्यों नहीं बनावें ?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

वे अधिकारी उनके गुमाश्तों से मिल जाते हैं और कानून को पूर्ण रूप से अमल में नहीं आने देते हैं। जो दूध में या किसी चीज में मिलावट करते हैं उसको रोकने के लिए अधिकारी रखते हैं १५०) रुपयों का। मगर वह भी उन दूकानदारों से मिल जाता है और दूकानदार से कह देता है कि २०) माहवार दे दो तेरी दुकान पर आकर दूध नहीं देखेंगे। इसी तरह से दूकानदार चाहे जिस दिन चाहे जब तक खुली रखे, अपने नौकरों से चाहे जितना काम ले, वह अधिकारी से मिल ले फिर चाहे जैसा आजादी से कार्य करे, कोई कहने और पूछने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वाला नहीं। कानून भले ही अच्छे लोगों के बनाये हित के लिये जावें लेकिन जब वे लागू होते हैं तो मशीनरी इस प्रकार की है कि ठीक तरह से काम नहीं करती। आप दवा वालों को देख लीजिये, दूध वालों को देख लीजिये। यही बात उन पर और रीएम्बर्समेंट आदि सब पर यही....

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! Order!!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लोग कहते हैं और हम यही सुनते रहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि गरीबी से लड कर गरीबों को गरीबी से छुटकारा दिलाना है और डेमोक्रेटिक सोश्यलिज़्म को लाना है। इसके लिये हमको डट कर मुकाबला करना हैं और इसके लिये जरूरी है कि हमें खुद की ताकत से हुकूमत को चलाना है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : योजना मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों के भाषण हुए। यह स्वाभाविक ही था कि इन सब भाषणों पर अकाल और मंहगाई पर चर्चाएं हुई थीं। अकाल और मंहगाई के बारे में हमारे कृषि मंत्रीजी ने इसके बारे में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। श्रीमान, मैं इन सब मुद्दों में न जाकर, मैं आपके सामने जो दूसरी बातें इस सदन में कही गई हैं उन पर चर्चा करूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को शुरू से आखिर तक पढ लिया जावे तो राज्यपाल ने जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है और मेरा ख्याल है कि राज्यपाल का यह पहला अभिभाषण है जिसमें उन्होंने राजस्थान की हालत को देखते हुए वास्तविक स्थिति इस सदन के सामने रखी है। इससे अच्छा राज्यपाल महोदय का रीअलिस्टिक भाषण पहले कभी पेश नहीं हुआ। मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर): आप अपनी बात कहें, क्या कहना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): It is a post-script condemnation.

श्री मथुरादास माथुर : राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के शुरुआत में और अंत में और दौरान में sequenence से बातें कही हैं उन बातों से जाहिर होता है कि राज्य सरकार देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए नये तरीकों से समाजवादी समाज की स्थापना के लिए जो कदम उठाये जा रहा है उसका उन्होंने शुरू और अंत में जिक्र किया है। विरोधी दल के नेता ने जो अपने भाषण में तथ्य रखे और साथ ही साथ हमारे और दूसरे दलों के नेताओं ने दूसरी बातें रखी मैं कहूंगा कि मुझे उसमें कुछ नई बात-सुनने को नहीं मिली। मैंने विरोधी दल के नेता का एक साल पहले का भाषण भी पढ़ा तो बड़े बड़े मुद्दे जो हमेशा वे दोहराते हैं और उनकी पार्टी की नीति है उन्होंने चर्चा की। सदन

(श्री मथुरादास माथुर)

खूब समझता है कि उनकी पार्टी की क्या नीति है। वे समाजवादी समाज का निर्माण करना नहीं चाहते इसलिए उन्होने जो तर्क और दलीलें रखी हैं, उनसे धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन की उम्मीद करना कि वे इसमें अपना हिस्सा जोड़ दें, हमें उम्मीद नहीं है।

मैं यह कहूंगा कि यह अपनी परम्परा बन गई है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में अच्छी बातें हों, चाहे देश की बहबूदी की बातें हों, वे उनमें कभी शरीक नहीं होते, यह democratic Convention सा होता जा रहा है। यह मौका होता है कि जब मुख्तलिफ पार्टी अपनी नीति सदन के सामने रखती हैं तो उस ओर बैठने वाले और कांग्रेस पार्टी की नीति है, वह उसकी नीति नहीं है बल्कि देश में जो जनता की आवाज है उसको उन्होंने पुरजोर बताया है, इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे इस बात को कहना पड़ता है कि विरोधी दल के नेता समाजवादी समाज और समाजवाद की समस्या को समझ नहीं पाये हैं इसलिए वे अमूमन अपने तर्क में यह कह देते हैं और खास तौर से सरकार की ओर से जब समाजवादी समाज के लिए कहा जाता है तो कहते हैं वे डिक्टेटरशिप के नाम से या सोवरेन्टी के नाम पर इसे जारी करना चाहते हैं। हमारी नीति और पार्टी की नीति साफ है — देश की नीति साफ है। लोक-सभा में यानी पार्लियामेंट में एलान कर किया गया है कि देश में डेमोक्रेटिक सोश्यलिज़्म कायम होकर रहेगा। इस बात को लेकर ये तकरीरें चलती रहती हैं, वह कभी उनको शोभा नहीं देता।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं कहना चाहूँगा, माननीय सदस्यों से अगर आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को शुरू से आखिर तक पढ़ें और सदन के माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि उन्होंने खास मुद्दे दिये हैं, इसलिये नहीं कि हमारी नीति को रख कर चुप हो गये हों, ऐसी बातें नहीं हैं–हमारी राज्य सरकार ने भी कदम उठाये हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अभी तक इसका श्रीगणेश ही है और जितना हिस्सा समाजवादी समाज में लोगों को मिलना चाहिए मिलने में कुछ समय लगेगा। आज ४० वर्षों की कोशिश के बाद रूस में समाजवादी समाज की रूपरेखा बन चुकी है और वह अब आगे बढ़ने जा रहा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम ५—७ वर्षों में अपने देश में समाजवादी समाज को लाना चाहते हैं उसमें समय लगेगा और जिन प्रजातान्त्रिक तरीकों से हम उसे लाना चाहते हैं उसमें समय लगाना जरूरी है। इसलिये हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सहकारी समिति में ५) रु० की गड़बड़ हो गई या किसी मार्केटिंग सोसाइटी में गड़बड़ हो गई, तो सोसाइटी व सहकारिता के लिए कहते हैं कि कि हमें सहकारिता को छोड़ देना चाहिये– वे इस तरह के विचार रखते हैं कि सहकारिता समाप्त हो–इससे कई रोड़े खड़े करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है कि यदि हमें समाजवादी समाज को लाना है तो सहकारिता को समाज में प्रोत्साहन देना होगा। हमें गरीब लोगों को सहकारिता के आन्दोलन में शामिल लेना होगा। आज सहकारी समितियों की हैसियत ऐसी नहीं कि वे पूंजी में हिस्सा बंटा सकें; इसलिए

(श्री मथुरादास माथुर)

उनके लिए राज्यपाल महोदय ने कहा है कि जो सहकारी समितियाँ जिनकी पूंजी थोड़ी होगी, जिनका फायदा वहां के ग्राम वाले और समाज नहीं उठा सकें उनको रिज़र्व बैंक द्वारा ५० प्रतिशत ऋण देगा और उससे वे व्यापार करेंगे। यदि कहीं के व्यक्ति पिछड़े हुए हैं उनको शेयर कैपीटल सरकार देकर सहकारी समिति बनावेगी जिससे वे लोग सहकारी समिति के सदस्य बन सकें। क्या यह कदम हमारे समाज के पिछड़े हुए लोगों को सहकारिता के आन्दोलन में लाने का कदम नहीं है? हो सकता है कुछ लोग उनको डरावें। मगर हमें इस ओर कदम उठाना होगा।

राज्यपाल महोदय ने जो बातें कहीं और खास तौर से गरीब लोगों को समाज की उस पूंजी में हिस्सा लेने के लिये जोड़ा जावेगा और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा कदम है, मेरा ख्याल है कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके साथ ही साथ अकाल और मंहगाई की बातों को हमारे यहां यह फैसला हुआ जिसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि सरकार की ओर से कन्ज्यूमर्स स्टोर्स हम कायम करना चाहते हैं। १५०० ऐसे कन्ज्यूमर्स स्टोर्स कायम करेंगे जिससे कि चीजों के भाव नीचे आ जायं। यह कदम केवल भावों को नीचे लाने का ही नहीं बल्कि स्टेट ट्रेडिंग की ओर अग्रसर होने का भी है। सरकार की दूकानें खुलें, गेहूँ सस्ता बिके, शक्कर सस्ती बिके, गुड़ सस्ता बिके इसके लिये कन्ज्यूमर्स स्टोर्स कायम किये जा रहे हैं। शक्कर और गेहूँ के कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोलने का सरकार फैसला कर चुकी है जिसका राज्यपाल महोदय के भाषण में जिक्र है। इन चीजों की दूकानें खोल कर मिडल मैन को एलीमिनेट किया गया है, क्या यह सरकार का समाजवादी समाज की तरफ कदम नहीं है? समाजवादी तत्व ही इसे समझ सकते हैं। यह कदम आगे बढ़ता बढ़ता और आगे बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आयेगा कि हमारे समाज की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उनमें स्टेट ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तभी सही माने में समाजवादी समाज की स्थापना हो सकेगी।

इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी जो कहा है जो मजदूर हैं, पिछड़े हुए हैं, हम यह मानते हैं कि मंहगाई बढ़ी है इसलिए स्टेट एन्टरप्राइज़ेज़ में जो मजदूर है उन्हें ५ रुपया मिलेगा। फैक्ट्री एक्ट से कवर्ड जितने भी मजदूर हैं उनके ५ रु० बढ़ाने का फैसला किया। क्या यह समाजवाद की तरफ कदम नहीं है? हो सकता है कि मांग यह हो कि १० रुपये बढ़ाये जायं या २० रुपये बढ़ाये जायें लेकिन जो सोर्सेज़ ऑफ इन्कम ऑफ दी स्टेट हैं, उनका, मैं, आप, जो स्टेट के जमादार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको खयाल रखना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जमादार कौन हैं साहब?

श्री मथुरादास माथुर : तो कन्ज्यूमर्स स्टोर्स, सस्ती चीजों की सरकारी दूकानें खोलने का फैसला किया है। कुल ११० दूकानें यहां हैं, गांवों में जो दूकानें खोली जायंगी वे शहरों से अलग होंगी। हमारा यह कदम हमारी उस नीति के आधार पर है कि जिसके अनुसार हम देश के अन्दर समाजवादी समाज का निर्माण कर सकें।

आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को गौर से पढ़ा होगा समाजवाद लाने के लिये

(श्री मथुरादास माथुर)

मिडल मैन का एलिमिनेशन जरूरी है पी.डब्ल्यू. डी., सिंचाई विभाग में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म कर दिया जायगा, सरकार अपनी ओर से इमारतें, बांध, सड़कें आदि बनायेगी, उसमें यह घोषणा की है, वह समाजवाद की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। माइनिंग की रॉयल्टी के लिये कॉन्ट्रैक्ट दिये जाते हैं उसको खत्म किया जायगा, स्टेट खुद यह रॉयल्टी वसूल करेगी, राज्यपाल महोदय के भाषण में इसका जिक्र है कि मिडलमैन हैं उनका एलिमिनेशन किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माइनिंग और फोरेस्ट में मोनोपोलीज़ चलती हैं उनका क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं बताता हूं, गोकि राज्यपाल के भाषण में इसका जिक्र नहीं है, पर हल्के हल्के राज्य सरकार की नीति है कि सब जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करके मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जाय, वह फोरेस्ट में, माइनिंग में बचा नहीं रह जायगा।

श्री भैरोंसिंह : बचा नहीं रह जायगा, यह तो समझ में आ गया पर गवर्नमेंट को इमीजियेटली घोषणा करने में क्या आपत्ति है ?

श्री मथुरादास माथुर : माइनिंग की, सिंचाई विभाग की, पी. डब्ल्यू. डी. की घोषणा हो चुकी है। सदन का सत्र काफी समय तक चलेगा, तसल्ली रखिये; जो घोषणा समाजवादी समाज के लिये आवश्यक है वह होगी, अगर आप समाजवादी समाज में विश्वास करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : फोरेस्ट और माइनिंग की मोनोपोली क्यों खत्म नहीं की जाती ?

श्री मथुरादास माथुर : मोनोपोली कहीं नहीं है किसी की, लीज़ेज़ दी जाती हैं—आप संतोष रखिये मैं आ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : मोनोपोलीज़ हैं। कैसे नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लीज़ेज़ बड़े बड़े भू–खण्डों पर दी जाती हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एक दिन में सारी काया पलट नहीं होती। जो केपिटलिस्टिक नोर्म्स सोसाइटी में घुसे हुए हैं उनको निकालने में समय लगता है। जनता में ऐसी विचारधारा नहीं पैदा हो जाती तब तक नहीं निकल सकते। तो राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है वह समाजवाद की तरफ आगे बढ़ने का एक कदम है।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी योजना में भूमि–सुधार के बारे में जितनी योजनाएं थीं वे पूरी कर चुके हैं। १५ दिसम्बर से सीलिंग को लागू किया गया है, अब जमीन पर से बिचौलियों को खत्म करने के हल्के हल्के कदम उठाये जा चुके हैं और ट्रेड में भी बिचौलियों को खत्म करने के हल्के हल्के कदम उठाये जा रहे हैं। हम और हमारी सरकार जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया देश की जो समाजवादी नीति है, उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है, वह जो बात कही गई है वह गलत है। बिचौलियों का नाम और रख दिया गया है। बिचौलियों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का नाम खातेदार रख देने से बिचौलिये खत्म नहीं हो जाते ।

श्री मथुरादास माथुर : बिचौलियों में और खातेदार में बहुत फर्क है । बिचौलिया वह है जो खुदकाश्त नहीं करता और किसान की मेहनत का फायदा उठाता है और खातेदार वह है जो खुदकाश्त करता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खुदकाश्त नहीं करते और आधा बांटा लेते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि १०० खातेदारों में से राजस्थान में ६५–६६ खुदकाश्त करते हैं । दो चार ऐसे होंगे जो दूसरों से काश्त कराते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फेक्च्चुअली गलत है । आपकी गवर्नमेंट मशीनरी में कई ऐसे हैं जो खुदकाश्त नहीं करते और आधा बांटा लेते हैं । रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर हैं जो आधा बांटा लेते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : अगर कोई लेता है तो उसको कतई लेने का अधिकार नहीं है । कोई लेता है तो कानून के खिलाफ लेता है और हर एक को हक है कि कानून के अन्दर जो रास्ता बताया हुआ है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करवाये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आधा बांटा लेते हैं, यह गवर्नमेंट के रेकॉर्ड में मौजूद है ।

श्री मथुरादास माथुर : चोरी करना मना है, किसी की औरत को उठा कर ले जाना मना है पर कोई ले जाय तो उसके लिये कानून रास्ता भी बताता है । अगर कोई ऐसा करता है लाठाई से, बेईमानी से करता है तो उसके बारे में यदि मुद्दा रखें तो एक्शन लिया जा सकता है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्कीम ऑफ थिंकिंग है, योजना है उसमें राज्यपाल महोदय ने एक और घोषणा की है । अमूमन यह शिकायत की जाती है, जनता की तरफ से जो शिकायतें की जाती हैं उन पर कदम नहीं उठाया जाता । राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है कि पब्लिक ग्रीवेन्सेज़, को दूर करने के लिये, पब्लिक की शिकायतों को दूर करने के लिये, जो कि शिकायतें इन्डिविज्युअल नेचर की न होकर पब्लिक नेचर की हों, उनको दूर करने के लिये एक स्पेशल विभाग को कायम किया जा रहा है यह भी वह कदम है जोकि हमें डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ाता है। अगर कोई गड़बड़ी करे तो शिकायत हो सकती है । इसके लिए खास विभाग डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवान्सेज सुनने के लिए होगा । यह एक बहुत बड़ी घोषणा है । इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, हल्के हल्के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और नए समाज के निर्माण की दिशा में, वेलफेयर स्टेट की ओर हमारा कदम है ।

(१·०० म० प०)

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर स्टेट एन्टरप्राइज़ेज़ का जिक्र हुआ है । राजस्थान सरकार की जिन्दगी में पहली बार ही स्टेट एन्टरप्राइज़ेज़ का अलग विभाग बनाकर उस पर कमिश्नर मुकर्रर होगा । पब्लिक सेक्टर बढ़ाने

(श्री मथुरादास माथुर)

से हम राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ते हैं और समाजवाद की तरफ बढ़ते हैं और साथ साथ में नोन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज़ को टैप कर सकते हैं जिसकी वजह से वेलफेयर स्टेट की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इस समय स्टेट एन्टरप्राइजेज़ के अन्दर जो मेरा विभाग है उसके अन्दर लिगनाइट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पचपदरा डीडवाना में साल्ट, गंगानगर में शूगर फैक्टरी, धौलपुर में हाइटेच और छोटे मोटे माइनिंग के काम या लाइम स्टोन भी स्टेट सेक्टर के अन्दर हैं। हमने यह फैसला किया है कि एक स्टेट कॉर्पोरेशन बनाया जाय, स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कायम की जाय और वह उसके लिए कार्यवाही चल रही है और एक महीने भर के अन्दर वह कॉर्पोरेशन कायम हो जायगा। उसके बाद में जितने भी स्टेट एन्टरप्राइज़ेज़ हैं उस कार्पोरेशन के मातहत आते हैं। इस तरह से हमारे पास योजना के अन्दर जो भी रुपया बैंकों या एल० आइ० सी० से ले सकते हैं उसे लेकर हम इन स्टेट एन्टरप्राइज़ेज़ को डेवलप करना चाहते हैं। नेशनाइलेज़न खास खास उद्योगों को करना चाहते हैं। जितने भी हमारी सरकार के रिसोर्सेज़ हैं उन रिसोर्सेज़ को बढ़ाने के लिए यह कार्य किया गया है।

राज्यपाल महोदय ने ४५,०० स्पिंडल्स के वूल कारखाने की घोषणा भी कर दी है। इससे भी यह जाहिर होता है कि हम हल्के हल्के समाजवाद की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और नेशनलाइज़ेशन और उद्योग-धंधों में भी राष्ट्रीयकरण करते जा रहे हैं।

हमारे यहां स्टेट एन्टरप्राइजेज़ के अन्दर, खास तौर से गंगानगर शुगर फैक्टरी के अन्दर आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने मजदूरों को इन्तजाम में पूरा हक दिया है। यही नहीं कि उनकी मांगें पूरी की हैं बल्कि हमारी नीति है कि जोइंट मैनेजमेंट कौंसिल बनाना चाहते हैं गंगानगर और भीलवाड़ा में। गंगानगर में तो बना चुके हैं, काम कर रहा है। भीलवाड़ा के लिए मसविदा बन चुका है और वहां पर भी लागू कर दिया जायगा और हल्के हल्के दूसरे स्टेट एन्टरप्राइज़ेज़ के अन्दर जोइंट मैनेजमेंट कौंसिल्स बनाए ताकि मजदूरों को और सरकार के नुमाइंदों को मिलाकर उस उद्योग को पनपाएं जिसकी वजह से ज्यादा उत्पादन हो और जो कुछ भी मुनाफा हो सरकार के खजाने में जाय जो, इन्डाइरेक्टली सोशियल एमिनिटीज़ के फॉर्म में वापस आम जनता के पास पहुंचाया जाय। यह भी एक कदम समाजवाद की तरफ बढ़ने का है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में रोडवेज कॉर्पोरेशन का भी जिक्र किया। उसके साथ साथ में हमारी स्टेट में जो टूरिस्ट्स का ट्रेड है उसको डेवलप करने के लिए और व्यक्तिगत मुनाफा भी न हो, उसके लिए राजस्थान सरकार ने होटेल कॉर्पोरेशन कायम करने का फैसला किया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके बाद रोडवेज़ कॉर्पोरेशन, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन पहले ही हैं। ये सब कॉर्पोरेशन्स कायम कर हम और आगे बढ़ेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि हम किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं।

कल जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नमक के बारे में जिक्र किया। उन्होंने जो सुझाव रखे वे राज्य सरकार के पहले ही

(श्री मथुरादास माथुर)

नोलेज में हैं। हमारे यहां सोडियम सल्फेट जो हैं, मेरे खयाल से हिन्दुस्तान के अन्दर कम इलाके ऐसे हैं जितना कि डीडवाना में बनता है। सोडियम सल्फेट के अन्दर हमारे स्टेट एन्टरप्राइजेज़ २० टन का प्रोजेक्ट प्लान हमने वेस्ट जर्मनी के कोलोबरेशन में किया है, उसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है और २० टन प्रोडक्शन होता है। लेकिन साथ में यह भी सुझाव दिया गया कि वहां सर्दी के दो महीने में कम से कम ४०–४५ दिन ऐसे होते हैं डीडवाना में जहां सोडियम सल्फेट ब्राइम में ७–८ पर्सेन्ट मौजूद हैं, अपने आप क्रिस्टलाइज़ होता है। यह एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर किया है। अगले साल हम बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, इससे एक लाख रुपया रोज मुनाफा हो जायगा। मैं उसके मुंह में गुड़ दे दूं जिसकी वजह से १ लाख रुपया मुनाफा हो जाय। जो भी मुनाफा होगा आपके सामने रख दिया जायगा। सो इस पब्लिक सेक्टर के जरिए और इन इन्डस्ट्रीज़ के जरिये राजस्थान के निर्माण में काफी मदद मिलेगी।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल कहा था कि पचपदरा के अन्दर नमक पैदा होता है वह हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा होता है, इसकी प्योरिटी ६६·२ पर्सेन्ट तक मानी गई है और उसके बाद में बाकी २५ कारबोनेट्स हैं और बाकी प्योरली क्रिस्टलाइज़ नमक माना गया है। यहां खेड़वाल के लोग पैदा करते हैं उधर देशवाल हैं। यह ब्रिटिश डेज़ से पहले वहां के जागीरदार, जालोल के ठाकुर, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनकी प्रोपर्टी थी वे नमक निकलवाते थे। उसके बाद में जब जोधपुर रियासत बनाई गई तो वह बनाया उन्हीं खेड़वाल लोगों ने। उसके बाद में १८६६ में ब्रिटिश और जोधपुर दरबार के बीच में ट्रीटी हो गई। चाहे सांभर हो या डीडवाना, चाहे फलोदी हो या पचपदरा, लीज़ दी गई। वे १६५० तक स्टेट को रॉयल्टी देते रहे। १६५० में राज्यप्रमुख और प्रेसीडेन्ट ऑफ इण्डिया के बीच और ट्रीटी हो गई जिसकी वजह से ब्रिटिश ट्रीटी खत्म हो गई। उसके बाद में हम जमीन के मालिक बन गए, यानी राजस्थान सरकार मालिक बन गई। जब राजस्थान सरकार मालिक बन गई तो उसके बाद में सांभर के अन्दर एक कंपनी बनी जिसमें स्टेट का शेयर है और भारत सरकार का शेयर है। सॉल्ट कम्पनी बन गई। बाकी दो जगहों पर डीडवाना और पचपदरा में पिट्स के मालिक वे हैं, उनको मोर्गेज कर सकते हैं, इन्हेरिट कर सकते हैं। ट्रीटी जो चल रही है उसके अनुसार नमक बनाने के लिए पिट्स का खर्चा राजस्थान सरकार लोन पर देती है और इस पर इन्सटालमेंट्स चुका देते हैं। वह जो ट्रीटी है उसके आधार पर ही नमक बेचते हैं। हम यहां पर उसके अन्दर ट्रेड करते हैं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भाई को यह भ्रम हो तो दूर कर लें। देशवाल और खेडवालों की ट्रीटी से साफ जाहिर है। उन्होंने रिप्रेज़ेन्टेशन किया था, फैसला हो गया। १ क्विन्टल नमक बनाने के लिए खेडवालों को १) मिलता था। मेरे इस विभाग का चार्ज लेने के बाद दस नये पैसे पर क्विन्टल बढ़ा दिया है। उनको खड्डा खोदना पड़ता है। वे झाड़ी डाल देते हैं, क्रिस्टल जमा हो जाते हैं तो झटक लिये जाते हैं। नेचुरल प्रोसेस है। १) १० नये पसे पर क्विन्टल देते हैं। देशवालों का भी रिप्रे-

Page No. 100

(श्री मथुरादास माथुर)

ज़ेन्टेशन है कि उनकी भी रेट्स बढ़ायी जांय। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने केवल भारत सरकार से मैन्युफेक्चर करने के लिए लाइसेन्स लिया है, ट्रीटी इन्हेरिट नहीं हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : भारत सरकार इसका लाइसेन्स देने वाली कौन होती है? पहले जागीरदार इस लेक के मालिक होते थे। इसके बाद जोधपुर दरबार हो गये। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर उसको लीज़ दे दी गई। उसके जाने के बाद वह टर्मिनेट हो गयी। इस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया लैसी बन गई और हम मालिक रहे। हम उस जमीन को किस तरह से काम में लावें यह हमारा हक है। राजस्थान सरकार की उस पर पूरी मिलकियत है। जो कदमी काम करते आये हैं वे देशवाल और खेडवाल हैं। हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है कि हम दूसरों को नमक नहीं देंगे, वे हमको ही देंगे। हमें तो उनका नमक खरीदना ही पड़ता है, चाहे वह बिके या नहीं बिके। चालीस लाख मन नमक पड़ा हुआ है, फिर भी हमने खरीदा है क्योंकि उनके और हमारे बीच एग्रीमेंट है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार को मैन्यूफेक्चर करने का लाइसेन्स है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार खुद मालिक है। लाइसेन्स लेने की जरूरत ही नहीं है। देशवालों और खेडवालों से नमक खुद पैदा करवाते हैं। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य के यह बात समझ में आ गयी होगी और नहीं आयी है तो यह किताब है इसके बारे में उसको पढ़ लें।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरे पास भी है और मैंने उसको देख रखा है। मैन्यूफेक्चर करने का राइट इनहेरेन्ट नहीं होता है।

श्री मथुरादास माथुर : ट्रीटी को पढ़ लें और संदेह हो तो हमसे पूछ लें। जो पैसा आता है वह एक्स्चेकर के पास जाता है जिससे हम आपकी और देश की सेवा करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उससे कोई झगड़ा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : एक बात विरोधी दल के नेता ने कही, जोरदार शब्दों में कही, किसानों के साथ बड़ी हमदर्दी दिखायी। किसानों के साथ हमदर्दी करने के लिए चारों तरफ से बातें होती हैं। रूरल इन्डेटेडनैस से किसान दब रहा है, पिस रहा है न जाने और कई प्रकार के विशेषण लगा कर किसान की हमदर्दी प्रकट करने की कोशिश की। आपने किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई उसके लिए खुशी हुई।

मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगा। आज रूरल इन्डेटेडनैस है उसको समझना पड़ेगा। फ्युडल जमाने में इन्डेटेडनैस का कारण बोहरे और पूंजीपति थे। आज सरकार किसानों को तकावी देती है, रिज़र्वबैंक देता है। लेकिन उसको इन्डेटेडनैस में नहीं गिन सकते। वह तो इन्वेस्टमेंट है। इसको यदि बन्द कर दिया जाय तो किसान जिन्दा नहीं रह सकता। बीज के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के

(श्री मथुरादास माथुर)

लिए, खाद के लिए, बैल के लिए तकावी दी जाती है। मुखतलिफ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से उसको रिलीफ दिया जाता है; एग्रीकल्चर, फेमीन डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आदि से उसको कर्जा दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह कुल कितना है और वे मनीलेंडर्स से कितना लेते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं जानता हूँ कि आप क्या सवाल पूछेंगे।

किसानों की मालीहालत जागीरदारी खत्म होने के बाद काफी सुधरी है। काफी पैसा (कर्जा) उन्होंने चुका दिया है। रिकन्सिलियेशन बोर्ड ५० से ५५ तक कायम था। आपसी समझौता होकर पुराना कर्जा खत्म हो गया। "जो धन जावे डूबतो तो आधो लीजे बांट" वाली कहावत के अनुसार आधा पैसा लेकर ही उन्होंने फैसला किया। पर्सेन्टेज की रिपोर्ट अभी मेरे पास फाइनल होकर नहीं आयी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में ही अपनी दयनीय स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में १०० में से ४२ न. पै. प्रति व्यक्ति तरक्की कर पाये हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना की हालत और भी दयनीय है, गरीब की स्थिति और भी गरीब हुई है और आप कहते हैं कि अच्छी हालत है। यह मानिये कि गरीब अधिक गरीब हो गये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसान अधिक गरीब हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं मानेंगे तब तक राजस्थान की हालत को अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आप यह नारा नहीं देंगे तो आपकी जिन्दगी कैसे कायम रहेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : शीशों के महल में बैठने से सोशलिज्म नहीं आवेगा।

श्री मथुरादास माथुर : इन्हीं हाथों से आवेगा। चीन से मिलने से नहीं आवेगा।

तो मैं कह रहा था कि किसानों की माली हालत पहले से अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा मैं भी नहीं मानता। इन्डेटेडनैस के लिहाज से टोटल किसान को दिया जाता है इन्वेस्टमेंट्स १२ से २० पर्सेन्ट होते हैं। मैं आपको फीगर्स के साथ बताना चाहता हूं। ६०-६१ स्टेट इन्कम : ६३,६६१ लाख एट करेन्ट प्राइसेज़। ६१-६२ : ६८,६२६ लाख एट करेन्ट प्राइसेज़। इसमें बढोत्तरी हुई है। ६३ से नेशनल इन्कम बढ़ी है। ६१-६२ में एग्रीकल्चर की इन्कम है वह है २,५४३ लाख रुपया। स्टेट इन्कम में एग्रीकल्चर सेक्टर ने कॉन्ट्रिब्यूट किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६२-६३ के फीगर्स दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : ६२-६३ के फीगर्स कम्पाइल नहीं हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६२-६३ तो ३१ मार्च, ६३ को ही समाप्त हो चुका।

श्री मथुरादास माथुर : आंकड़े अभी अवेलेबल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और छप चुकी हैं।

श्री मथुरादास माथुर : नेशनल इन्कम के फीगर्स नहीं आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अन्कम्फर्टेबल हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अन्कम्फर्टेबल नहीं है। ६०-६१ और ६१-६२ में क्रमश : ६३,६६१ लाख, ६८,६२६ लाख थी उसमें से ६१-६२ में एग्रीकल्चरल सेक्टर ने २,५४३ लाख दिया है। यह नेशनल इन्कम बढ़ाने में साझीदार है।

इससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार की तरफ से जो कर्जा दिया जाता है वह किसानों पर इन्वेस्टमेन्ट है जो उनकी इन्कम को बढ़ाने वाला है....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आप उस पर सूद भी तो प्राप्त करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जो कम्पेरिज़न आपके सामने रखा है कि वह करेन्ट प्राइसेज़ के हिसाब से कम्पेरिज़न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह बताइये कि इन्डेक्स नम्बर में कितना फर्क है, इसको अगर निकालेंगे तो रिअल इन्कम का पता लग सकेगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं स्टेट इन्कम की बात कह रहा था पर केपिटा।

श्री अब्दुलजब्बार : स्टेट इन्कम की बात कर रहे हैं, आप जो लोन्स आदि किसानों को देते हैं वह सीधा तो देते नहीं हैं, वह किसी एजेन्सी के मार्फत देते हैं वह उनके पास पहुंचता तक नहीं, बीच में खत्म हो जाता है; क्या इसको भी आपने देखा है ?

श्री मथुरादास माथुर : समय कम है, आप मुझे अपनी बात को पूरी करने दें। एग्रीकल्चर इन्डेटेडनैस किसानों पर बढ़ रहा है; यह जो नारा आप दे रहे हैं वह गलत है। यह कर्जा नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से नेशनल इन्कम बढ़ी है।

यह भी बात कही गई फेमीन के इलाके में जो कुछ कार्य हो रहा है उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी प्रकाश डालेंगे। एक बात मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर प्रथम पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में और तीसरी पंचवर्षीय योजना में फेमीन के इलाके में और रूरल एरिया में जितने कुए खोदे हैं उनके आंकड़े मैं सदन की जानकारी के लिये रख देना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि इससे पानी की समस्या का हल हो गया है। इतने कुए खोदे गये, कई जगह पर पानी मिला है, कुछ जगहों पर खारा पानी मिला है। बोर्डर के इलाकों में भी ट्यूब वेल्स खोदे हैं, कहीं पर हमें कामयाबी हुई है कहीं पर नहीं भी हुई। २५० ट्यूब वेल्स लगाये जा रहे हैं। हमें आपसे ज्यादा दर्द होता है हम जिस इलाके से आते हैं जब वहां किसानों को, मां-बापों को अपने बच्चे उठाकर मालवा आदि जाना पड़ता है तो किसी को अच्छा मालूम नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

होता। फ्यूडल परम्पराओं को बदलना चाहते हैं। हमने यह निर्णय किया है कि २०-२० और दस दस माइल पर ट्यूब वेल लगाया जाय। उसमें भारत सरकार ने २५० ट्यूब वेल बनाने का आश्वासन दिया है और हम राजस्थान की तरफ से ७५ और उस में जोड़ना चाहते हैं। इस तरह से करीब ३५० कुए हमने खोदना शुरू कर दिया है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को चार मशीनें और दे दी हैं। इस तरह से जहां पर पानी मिल जायगा वहां वाटर बैंक खोल देंगे, फोडर बैंक खोल देंगे, ताकि फेमीन के समय आगे नहीं जाना पड़ेगा....

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : पचपदरा तहसील का भी नम्बर आने वाला है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : पचपदरा तहसील बाड़मेर में है, वहां पर दो मशीनें काम कर रही हैं। यदि आपकी जल्दी इच्छा है तो पचपदरा में भिजवा देंगे। पचपदरा फेमीन अफेकटेड एरिया है, दो मशीनें बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं; किस जगह कुए खुदवाना है वह जगह आप बता दें।

श्री अमरसिंह : यह कहां हो रहा है, इसकी जानकारी हमें भी तो रहनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये हमने कलेक्टर से कहा है कि लोकल एम० एल०एज०, पंच सरपंच गांव में सूंगा हो तो उसके बताने की जगह पर बोरिंग किया जायगा, यह इन्तजाम हो गया है और काम शुरू हो गया है। मैं अब वे आंकड़े रखना चाहता हूं कि किस किस योजना में कितने कुए खोदे गये।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में ७५० कुए खोदे गये।

दूसरी योजना में ४१,७४६ कुए खोदे गये।

तीसरी योजना के वर्ष १९६१-६२ में ९,१६५ कुए खोदे गये और ६२–६३ में ९,३९० खोदे गये। ९९ प्रतिशत कुओं में पानी मिला है। हो सकता है किन्हीं कुओं में खारा पानी मिला हो लेकिन उसको भी कुछ मीठा पानी मिलाकर इधर उधर करके उसको लोग काम में लेते हैं और उससे लोग अपना जीवन चलाते हैं। इसके लिये हमने एक स्पेशल डिवीज़न कायम किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जो आपने फीगर्स दिये हैं वे एक्सपेन्डीचर के बेसिस पर दिये हैं या फिज़िकल अचीवमेन्ट्स हैं।

श्री मथुरादास माथुर : फिज़िकल वेरीफिकेशन के बाद में यह फीगर्स बताये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर हाउसिंग के बारे में भी कल विरोधी दल के नेता ने बात कही थी कि मकान नहीं बन रहे हैं। हम सेन्सस जो ६० में हुई उसके आंकड़े लें और सन् ५१ की सेन्सस के आंकड़ों को लें तो ६१ के अन्दर ३१ लाख मकानात थे इसमें कच्चे-पक्के दोनों शामिल हैं। सन् ५१ के अन्दर २५,९५,८४६ रेजीडेन्शियल हाउसेज़ हैं; पक्के और कच्चे दोनों शामिल हैं। ६१ की

(श्री मथुरादास माथुर)

सेन्सस के अन्दर यह कुल मिलाकर ३१,७२, ८५१ हो गये हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के फीगर्स हैं। उसके बाद मुख्तलिफ योजनाओं में जिनमें निम्न प्रकार से स्कीम्स थीं—लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, मीडियम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, Slum Clearance Housing Scheme, Backward Class Scheme, Scavanger Scheme; इन सब स्कीमों के अन्दर फर्स्ट प्लान में, सेकन्ड प्लान में और थर्ड प्लान के इन दो सालों के अन्दर भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जो मकानात बने हैं वह मैं बताना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): पक्के और कच्चों की संख्या अलग अलग बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर: प्रथम योजना में २०२, १,१७७। दूसरी योजना में ४८१, १६५, ११२२, १२०, ६२२। तीसरी योजना ६१-६२ में ६०२, २०४, ५१२, ८०, २३७, ५६, तीसरी योजना ६२–६३ में ७८६, १७८, ३६८, ८०, १७३५। इतने मकानात बने जो स्कीम्स मैंने पहले बतायीं उनके अन्तर्गत। इससे आप नतीजा निकाल सकते हैं इस बारे में हम कितने जागरूक हैं।

श्री अब्दुजलब्बार (निम्बाहेड़ा): गवर्नमेंट बिल्डिंग्ज़ भी इसमें इन्क्लूडेड हैं, क्या?

श्री मथुरादास माथुर: नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट का और समय दिया जाय ताकि मैं अपना भाषण समाप्त कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय पांच मिनिट के लिये और बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

पांच मिनिट का समय बढ़ाया गया।

श्री मथुरादास माथुर: इसके बाद में जहां तक पॉवर के बारे में बातें कही गईं उनका उत्तर विद्युत् मन्त्री कल आपके सामने पेश करेंगे। इस बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, वह यह कि हमारे यहां बिजली की भिन्न भिन्न रेट्स थीं, हमारे यहां दो टेरिफ्स हैं, जोधपुर डिवीज़न में ऐसे इलाके हैं जहां थर्मल पॉवर था वहां इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट का काम नामुमकिन हो गया था क्योंकि टेरिफ बहुत ऊंचे थे, भाखरा के अलग, चम्बल के अलग थे, अब हमने डीज़ल का टेरिफ एक कर दिया और नोन-डीज़ल का एक कर दिया है। इससे जो इन्डस्ट्रीज़ के मायने में बैकवर्ड एरिया है उसको बहुत राहत मिलेगी, यह एक क्रान्तिकारी कदम है जिसके लिये माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहिये। कन्ज़म्पशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है राज्यपाल महोदय ने आंकड़े दिये थे।

श्री रामानन्द: ये रेटें कब से लागू होंगी?

श्री मथुरादास माथुर: पहली अप्रेल से। राजस्थान कैनाल के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मैं समझता हूं; राजस्थान कैनाल की इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटी ही नहीं है।

(श्री मथुरादास माथुर)

देश की एक सोशियो-इकोनोमी पोटेन्शियेलिटी भी है। इसके निर्माण में किसी जागीरदार के गढ़ या किसी सेठ की हवेली को गिराना नहीं है। खुला मैदान पड़ा है। इसलिये यह एक सोशियो-इकोनोमिक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और इस आधार पर हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि इस जैसे बड़े प्रोजेक्ट को खुद अपने हाथ में ले किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा या सीधा वह उसे चलावे। हां, आपने जो हमारा ध्यान जमीन के अलॉटमेंट के प्रश्न की तरफ खींचा है उस ओर से हम सावधान हैं। यह हक हम भारत सरकार को सरेन्डर नहीं करेंगे।

कल इलेक्शन के बारे में जयपुर के पड़ोस के देहात से आने वाले मानसिंहजी महार ने कहा था कि पंचायत इलेक्शन पोस्टपोन क्यों किये गये। मैं इस बारे में निवेदन करू कि एक तरफ तो आप फेमीन के बरे में दर्दनाक कहानी कह कर हमदर्दी दिखाने की बात कहते हैं और जो फेमीन में फंसे हुए हैं, जो दूर–दूराज जाकर कान में और अपनी आजविका में लगे हैं, जिनके लिये सरकार प्रबन्ध कर रही है, उस समय आप इलेक्शन की बात करते हैं! कुछ राजस्थान कैनाल पर लगे हैं, कुछ राणा प्रताप सागर बान्ध पर लगे हैं। तो वोटर तो अपनी जिन्दगी और मौत की कुश्ती लड़ रहा है और हम इलेक्शन कराना चाहते हैं।

किसी की जान ली, आपकी अदा ठहरी।

श्री रामकिशन (वैर) : यह दलील तो अच्छी ढूंढी जान बचाने के लिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): महुवा के इलेक्शन के पहले ऐसी दलील आपको नहीं मिली ?

श्री मथुरादास माथुर : जूडीशियरी और एक्ज़ीयूटिव के सेपरेशन के बारे में कहा गया। इसके हमारे चार टायर्स हैं। ऊंचे में हाई कोर्ट है और नीचे में न्याय पंचायत। हिन्दुस्तान में राजस्थान ही पहली स्टेट है जहां इलेक्टेड बोडी न्याय पंचायत है। ऐसी बात पर अगर आप भी धन्यवाद नहीं देंगे तो आपके लिये हमारे विचार दूसरे होंगे।

श्री रामकिशन : आपकी इस महेनत के लिये हम जरूर धन्यवाद देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : ५७ डिस्ट्रिक्ट्स में यह सेक्शन हो चुकी है। २३ बाकी हैं। योजना बन चुकी है। लास्ट टाइम एमर्जेन्सी की वजह से रिसोर्सेज़ हमें नहीं मिल सके थे इसलिये रुक गया था। अब हम धीरे धीरे सब कर रहे हैं।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने हमारे यहां पर आकर सरकार की नीति और देश की नीति रखने में और जो भाषण देने में कष्ट किया है उनके उस अभिभाषण के लिये वे धान्यवाद के पात्र हैं और मैं उस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का एक मिनट का समय और है। श्री अमरसिंह।

(अल्प विराम के अनन्तर श्री अमरसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

(श्री उपाध्यक्ष)

आप कल प्रारम्भ रखें। समय करीब करीब समाप्त हो गया है।

समय समाप्त हुआ। सदन कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थागित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.पू. १ बज कर ३४ मिनिट पर दिनांक २६ फरवरी, १९६४ के म. पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार दिनांक २५ फरवरी, १९६४)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
उच्चस्तरीय स्कूल, बड़ी सादड़ी ।	१	पत्रों की ग्राहक संख्या ।	
हिण्डौन-खरेटा सड़क का सर्वे ।		बीकानेर–रतनगढ़ ट्रांसमिशन लाइन का सर्वे ।	
शाहबाद व छबड़ा तहसीलों की सड़कें ।		पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब ।	
फर्टीलाइज़र फैक्ट्री, हनुमानगढ़ ।		संगीत स्कूल, गुमानपुरा, कोटा ।	
सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी का गठन ।		हाई स्कूल, भादरा का हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तन ।	
देवगढ़ हाई स्कूल के मेन्टीनेन्स के लिए धनराशि ।		नसीराबाद–नीमच स्टेट हाईवे पर रेल्वे फाटकों की सड़क पर मुड़ाव ।	
जयपुर–भरतपुर रूट पर बसों की कमी ।		रूपारेल नदी के घाट सीतल पर पुल ।	
बिजली की कन्सेशनल रेट ।		टीचर्स की बकाया रकम ।	
राजकीय उच्च विद्यालय, नापासर ।		निम्बाहेड़ा–बेगूं रूट की बसों का टाइम टेबल ।	
साराडा-पलोदड़ा सड़क की भूमि का मुआवजा ।		लाखेरी ग्राम से स्टेशन तक सड़क निर्माण में विलम्ब ।	
माध्यमिक शाला, सारोला कलां ।		श्री गोपीनाथ जी का मन्दिर, कामां ।	
ग्रामीण विद्युतिकरण एवं कृषि प्रयोजनों के लिए विद्युत् ।		नाथद्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का क्षेत्र एवं मुकदमों की संख्या ।	

बीकानेर पोलीटैक्निक की बिल्डिंग ।

आबकारी एवं कर विभाग, निम्बाहेडा के भवन की बिक्री ।

(स्थगित प्रश्न २४-२-६४)

२. अतारकित प्रश्नों के शीर्षक ६१

क्रय विक्रय सहकारी समिति ।

ताश बनाने का कारखाना भरतपुर ।

सरकार द्वारा नियंत्रित मन्दिरों की सम्पत्ति ।

निम्बाहेड़ा में बिजली के कनेक्शन्स देने में विलम्ब ।

फलवा नगर में बिजली की सप्लाई ।

राशमी–गंगरार सड़क ।

जयपुर–बीकानेर हाईवे ।

टोंक जिले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति ।

शिक्षा विभाग कार्यालय, अलवर द्वारा सामान की खरीद ।

प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फण्ड नियम ।

डूंगर कॉलेज में हाल तथा छात्रावास ।

३. सदन की मेज पर रखे गये पत्र ७१

निम्नांकित पत्रादि सदन की मेज पर रखे गए:—

(१) कम्पनीज़ अधिनियम,१९५६ की धारा ६१९ क के अन्तर्गत नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड (National Project Construction Coporation Limited.) न्यू देहली के संचालकों के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं तत्संबंधी लेखों के विवरण:—

(क) कोरपोरेशन का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन तथा १ अप्रेल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक के लेखों के विवरण;

(ख) कोरपोरेशन का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन तथा १ अप्रेल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक के लेखों का विवरण ।

(२) राजस्व विधि आयोग का प्रथम प्रतिवेदन ।

४. प्रतिवेदन का उपस्थापन ७२

श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, ने विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

स्कम्भ

५. स्थगन प्रस्ताव ७३

राणा प्रताप सागर डेम के मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने से संबंधित श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के स्थगन-प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

संबंधित मन्त्री दिनांक २६ फरवरी, १९६४ को उपरोक्त विषय पर वक्तव्य देंगे।

स्कम्भ

६. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। ७३

श्री बृजसुन्दर शर्मा, सदस्य विधान सभा, द्वारा दिनांक २२ फरवरी, १९६४ को प्रस्तुत धन्यवाद-प्रस्ताव पर आज भी बहस जारी रही।

बुधवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की कार्यसूची

(१) मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।

(२) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF TIME-BARRED CASES

Serial No.	Inspectorate	Amt. of arrears due on a/c of fixation in U.P.S.	Amt. of arrears due on a/c of fixation in R.P.S.	Payment of arrears of increment	Payment of arrears of T.A. Bills	Payment of arrears of leave salary and other allied matters	Total	Total Amt. paid during 1962-63
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sikar	—	1315	2132	—	3230	5677	2792
2.	Jhalawar	—	1497	—	6	13603	15100	699
3.	Jaipur	172410	37260	48685	4109	6918	269382	69180
4.	Jhunjhunu	—	—	2314	266	—	2580	—
5.	Alwar	849	485	592	318	9038	11282	6126
6.	Kota	2356	3965	2185	4076	13201	25783	105
7.	Ganganagar	5120	5556	5641	800	9980	97097	9876
8.	Sirohi	700	1225	5250	1550	4575	13300	—
9.	Banswara	7161	855	3293	216	16698	28223	1505

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Chittor	3744	1222	2116	761	15949	23792	1762
11.	Pali	10612	19751	22458	6058	24846	83725	428
12.	Bhilwara	3637	4572	2465	1089	4447	16210	—
13.	Jodhpur	1712	1161	12635	1339	700	17547	4798
14.	Udaipur	2631	2697	2116	2097	17165	26706	9778
15.	Karauli	3063	19212	11119	4348	38623	76365	7411
16.	Nagaur	754	4428	1898	126	5914	13120	290
17.	Churu	11938	—	—	124	—	12062	175
18.	Bharatpur	4741	9696	10276	4704	28096	57513	—
19.	Ajmer	—	15675	—	1539	42994	60208	10460
20.	Barmer	925	926	3006	15751	6767	13195	—
21.	Bikaner	—	1535	2662	394	1926	6447	—
22.	DIGS, Kota	—	3000	3500	90 bills	10292	16792	3745
23.	„ Jodhpur	2333	3415	3778	12588	13739	35853	630

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	„ Jaipur	10846	2033	3516	—	6476	22871	22427
25.	„ Udaipur	1396	5300	717	350	49008	56771	19030
26.	„ Bikaner	40000	29700	5550	2000	2400	79650	47066
27.	„ Ajmer	651	—	3624	310	7681	12266	23776

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर देखिये)

TIME-TABLE

2 Permits have been sanatctioned on Nimbahera-Begun route

Departure from Nimbahera at 7.30 A.M.	Arrival at Begun at 12.00 Noon.
Departure from Nimbahera at 4.00 P.M.	Arrival at Kanera at 6.00 P.M.
Departure from Begun at 2.00 P.M	Arrival at Nimbahera at 6.30 P.M
Departure from Kanera at 8.00 A.M.	Arrival at Nimbahera at 10.00A.M.

Vehicles are playing regularly. They are playing under permits of RTA.

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर देखिए)

१. खिमियादासजी का रामद्वारा जोधपुर।
२. जगन्नाथरायजी का मंदिर घास मण्डी, जोधपुर।
३. रमोला रामद्वारा की अव्यवस्था।
४. रघुनाथजी का मंदिर फतेसागर, जोधपुर।
५. चारभुजाजी का मंदिर वाके मेड़ता।
६. मुरलीमनोहरजी का मंदिर, सोजती गेट, जोधपुर।
७. गान्धवकला तहसील बाड़मेर में ठाकुरजी के मंदिर की अव्यवस्था।
८. राम देवरा तहसील पोकरण के मंदिर की अव्यवस्था।
९. सेवा पुरी चन्दनपुरी का मठ, जोधपुर।
१०. राणावतजी का मंदिर हाथीराम का ओडा, जोधपुर।
११. रघुनाथजी के मंदिर, ओसियों की जायदाद की अव्यवस्था।
१२. गांव नादेड तहसील लाडनूं जिला नागौर में हनुमानजी के मंदिर की अव्यवस्था
१३. अचलेश्वर महादेवजी का मंदिर वाके कटला बाजार, जोधपुर।
१४. महादेवजी का मंदिर, वाके देवाली।
१५. मंदिर श्री सीरिया देवी वाके गांव ऊन्दरी।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २५ फरवरी, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४	१४, १५	काईठेरिया	काफ्टेरिया
,,	२४	(श्री मथुरादास नाथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
५	शीर्ष	(श्रीमती नगेन्द्रवाला)	(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
६	१३	श्री निरजननाथ आचार्य:	श्री निरंजननाथ आचार्य
११	२०	करगे	करेंगे
१४	१६	श्री निरंजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	२०	पन्द्रह दिन	पन्द्रह दिन
१६	१२	श्री भैरवलाल "कालाबादल"	श्री भैरवलाल "कालाबादल"
२२	७	ग्रामों	ग्रामों
,,	१०	विजली	बिजली
२३	१७	श्रो विजयसिंह झाला	श्री विजयसिंह झाला
२५	शीर्ष	(श्री निरंजनानथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
३१	शीर्षक	२५ फरवरी, ६३	२५ फरवरी, ६४
३२	३	श्री निरंजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
३४	२३	श्री निजरंननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
४२	५	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
४७	१६	वेसेज	केसेज़
४६	७	श्री भवानीशंकर नन्दवाना	श्री भवानीशंकर नन्दवाना
५१	शीर्षक	—२५ फरयरी, ६४	२५ फरवरी, ६४
,,	१६	फैकट्री	फैक्ट्री
५५	शीर्ष	(श्री मोहनलाल सुगडिया)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
,,	६	फैक्टस	फैक्ट्स
५६	शीर्षक	ंकितताारप्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
६३	शीर्ष	(श्री विट्ल भाई)	(श्री विट्ठल भाई)
६४	१३	अव्यव्वस्था	अव्यवस्था
६५	शीर्ष	(श्री विट्ल)	(श्री अब्दुलजब्बार)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६६	११	वर्स में	वर्ष में
७१	अन्तिम से २	कॉर्गेरशन	कॉर्पोरेशन
,,	,, २	संचलकों	संचालकों
७३	,, ४	अभिभापण	अभिभाषण
८३	३	वडे वडे	बड़े बड़े
८४	शीर्षक	वान-विवाद	वाद-विवाद
८४ से ८५	शीर्ष	(श्री दुर्गालाल वाडदार)	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
८५	१, २	कम । से कम	कम से कम
८८	अन्तिम २	मजिट्रेट	मजिस्ट्रेट
९०	६	नहीं	नहीं
९१	शीर्षक	महोदय	महोदय
,,	८	एक्टिविटीज	एक्टिविटीज़
९५	८	वहा	वहां
,,	१६	शिनिष्टर	मिनिस्टर
९७	१८	उस सम यतलवार	उस समय तलवार
,,	२३	मैकेनाइज्ड फामूस	मैकेनाइज़्ड फार्म्स
१००	१६	(१०.०० म० प०)	(१०.०० म० पू०)
१०१	शीर्प	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
,,	५	वमूल	वसूल
,,	२६	राजथ्थान	राजस्थान
,,	२७	उसकौ	उसको
,,	अन्तिम से ३	एक माननीय सदन्य	एक माननीय सदस्य
१०२	११	आवादो	आबादी
,,	१२	राजस्वान	राजस्थान
१०३	७	लगाया गवा है	लगाया गया है
,,	१७	वोला	बोला
,,	२५	एक प्रकासेत्परिपाटी	एक प्रकार से परिपाटी
१०४	१२	श्री मथुरादास मादुर	श्री मथुरादास माथुर
,,	१६	श्री योगेन्द्र नाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	अन्तिम से ४	श्री योगेन्दनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१०५	१	एक माननीय सदस्य ।	एक माननीय सदस्य
,,	३	श्री योगेन्दनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०५	६	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
,,	१८	श्री योगेन्दनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१०६	१७	कमी भीह मैं नहीं	कभी भी हमें नहीं
१११	शीर्ष	(श्री वोगेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
११३	अन्तिम से ५	क्योंकि	क्योंकि
११५	शीर्षक	अभिभापण	अभिभाषण
१२२	२१	मंहागई	मंहगाई
१२३	७	राणा प्रतापसाकर	राणा प्रतापसागर
१२६	१०	लिए	लिए
,,	अन्तिम से ६	मवशी	मवेशी
१३१	२७	खापेंगे	खायेंगे
१३२	६	घाह	घास
,,	अन्तिम से ४	एमर्जेन्स	एमर्जेन्सी
१३८	१८	प्रेन्स	ग्रेन्स
,,	२१	चाहता हुं	चाहता हूं
१३६	३	टार्गेट	टार्गेट
१४५	५	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से ३	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
१४७	१४	मेन्फेक्चर	मैन्युफेक्चर
,,	२१	विश्वासष	विश्वास
१४६	२३	मैंने	तो मैंने
१५१	अन्तिम	उसक	उसका
१५६	७	सकते हैं हैं ?	सकते हैं ?
१५६	शीर्षक	अभिभ्काषण	अभिभाषण
१६१	शीर्ष	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१६४	अन्तिम से २	कॉन्स्टीट्य	कॉन्स्टीट्यू —
१६५	१६	रानी साहिब	रानी साहिबा
,,	२०	अफीसर	ऑफीसर
१६७	शीर्षक	अभिभ्काषण	अभिभाषण
१७५	शीर्षक	राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण—२५ फरवरी, ६५—	राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण—२५ फरवरी, ६४—

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१७७	शीर्ष	(श्री ज्वालाप्रषाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१९२	शीर्षक	अग्रैतर	अग्रेतर
१९५	२२, २३	नेशनाइलेजन	नेशनलाइजेशन
१९९	३	श्री मैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
२१०	५	एग्क्जीयूटिव	एग्ज़ीक्यूटिव
२१२	२	कार्यवाही म. पू. १ बज कर ३४ मिनिट	कार्यवाही म. प. १ बज कर ३४ मिनट
२१५	१४	फस्बा नगर	कस्बा नगर
२१६	६, १०	Coporation	Corporation